



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1941 (श0)

(सं० पटना 1068) पटना, मंगलवार, 17 सितम्बर 2019

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

17 सितम्बर 2019

सं० 4/वी०मु०-20-93/18-3174/एम०—खान एवं भूतत्व (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम 67) की धारा 15 सहपठित धारा 23ग तथा धारा 26 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ—

- (1) यह नियमावली बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ— इस नियमावली, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो —

- (i) “अधिनियम” से अभिप्रेत है खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम 67) ;
- (ii) “समाहर्त्ता” से अभिप्रेत है किसी जिले का समाहर्त्ता—सह—जिला दण्डाधिकारी अथवा समाहर्त्ता—सह—जिला दण्डाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का अनुपालन करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ;
- (iii) “सक्षम पदाधिकारी” से अभिप्रेत है—

(क) भारतीय वन अधिनियम 1927 (केन्द्रीय अधिनियम XVI 1927) के अधीन सुरक्षित और संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित भूमि में उत्खनन अनुज्ञापत्र की दशा में जहाँ वास्तविक खनन कार्य केवल सतह से अथवा पॉच फीट से अनधिक गहराई से कुछ हटाना मात्र हो, तथा केवल 10000 घन फीट की सीमा तक हो संबंधित सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्र का प्रमंडलीय वन पदाधिकारी;

- (ख) सभी भूमि तथा उप मिट्टी, जिसमें खान और खनिज का कोई अधिकार, चाहे खोज निकाला गया हो तथा चाहे उस पर कार्य किया जा रहा हो या नहीं, सम्मिलित है, के सभी अन्य मामलों में जिला का खनन पदाधिकारी,
- (iv) **“सक्षम प्राधिकार”** से अभिप्रेत है इस नियमावली में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए प्राधिकार और इसमें पर्यावरणीय अनापत्ति देने के मामले में पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी शामिल है ;
- (v) **“वाहन”** से अभिप्रेत है किसी मोड़ या सवारी की सुविधा जिसके द्वारा अयस्क/ खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता हो और इसमें यांत्रिक उपाय, व्यक्ति, जानवर, गाड़ी, नाव शामिल हैं ;
- (vi) **“विभाग”** से अभिप्रेत है खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार;
- (vii) **“प्रमंडलीय आयुक्त”** से अभिप्रेत राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त प्रमंडल का आयुक्त ;
- (viii) **“खान निदेशक”** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त खान निदेशक;
- (ix) **“निर्यात”** से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा-शुल्क सीमान्त से पार से अन्यथा बिहार राज्य के बाहर ले जाना ;
- (x) **“प्रपत्र”** से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची I में दिए गए प्रपत्र ;
- (xi) **“सरकार”** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;
- (xii) **“आयात”** से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत के पार से अन्यथा बिहार राज्य में लाना ;
- (xiii) **“स्थानीय प्राधिकार”** से अभिप्रेत है नगर पालिका समिति, जिला पर्वद अथवा किसी नगरपालिका या स्थानीय विधि के नियंत्रण या प्रबंधन से सरकार द्वारा विधिक रूप से हक दिया गया अथवा न्यस्त किया गया कोई अन्य प्राधिकार ;
- (xiv) **“खान आयुक्त”** से अभिप्रेत है आयुक्त खान एवं भूतत्व, बिहार अथवा इस नियमावली के अधीन खान आयुक्त के कर्तव्यों का पालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ;
- (xv) **“लघु खनिज”** से अभिप्रेत है खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड (ई0) में यथा परिभाषित लघु खनिज और इसमें ऐसे खनिज शामिल हैं जो खान मंत्रालय द्वारा इनकी अधिसूचना संख्या एस0ओ0 423(ई0), दिनांक 10.02.2015 में अधिसूचित किए गए हैं ;
- (xvi) **“खनिज समानुदान”** से अभिप्रेत है लघु खनिजों के संबंध में खनन पट्टा या बन्दोबस्ती और इसमें खनन अनुज्ञा पत्र और इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार लघु खनिजों के खदान क्रिया का अनुज्ञा पत्र देना शामिल है ;
- (xvii) **“खनिज समानुदान धारक/बंदोबस्तधारी/पट्टाधारी”** से अभिप्रेत है कि बंदोबस्त/पट्टाधारित क्षेत्र से खनन किया पत्थर, बालू और अन्य लघु खनिजों को निकालने के लिए कोई वैध खनिज समानुदान धारित करता हो और उसका बहुवचन भी इसमें शामिल होगा;
- (xviii) **“खनन योजना”** से अभिप्रेत है लघु खनिज का धारक विभाग/खनन समानुदान के निमित्त मान्यता प्राप्त अर्हताप्राप्त व्यक्ति द्वारा तैयार की गई योजना और इसमें आनुक्रमिक तथा खान बंदी योजना शामिल है ;
- (xix) **“खनन अधिकारी”** से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन यथोल्लिखित अधिकारी ;
- (xx) **“व्यक्ति”** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संगठन अथवा व्यक्ति निकाय; कोई संस्था अन्यथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का विभाग ;
- (xxi) **“विहित”** से अभिप्रेत है इस नियमावली अथवा मार्गदर्शन द्वारा विहित ;
- (xxii) **“लोक मांग”** से अभिप्रेत है बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (1914 का अधिनियम 4) के अधीन यथा परिभाषित लोक मांग ;
- (xxiii) **“खनन क्रिया अनुज्ञा पत्र”** से अभिप्रेत है इस नियमावली के अध्याय vii के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से विनिर्दिष्ट मात्रा में किसी लघु खनिज को निकालने और हटाने के लिए दिया गया अनुज्ञा पत्र;

- (xxiv) “मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति” से अभिप्रेत है विभाग द्वारा इस रूप में जो अधिसूचित/पैनलकृत किया गया हो;
- (xxv) “बालूघाट” से अभिप्रेत है बालू वाला क्षेत्र जहाँ से बालू उत्खनन किया तथा वाहन के माध्यम से परिवहन किया जा सके;
- (xxvi) “बंदोबस्ती” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित प्रतियोगी बोली लगाने की प्रक्रिया द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट बालू तथा अन्य लघु खनिजों के खनन, खान से अयस्क निकालने, कार्य करने और ढो ले जाने के लिए सरकार की ओर से दिया गया खनन अधिकार ;
- (xxvii) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची;
- (xxviii) “परिवहन” से अभिप्रेत है बिहार राज्य के भीतर एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाना;
- (xxix) “कार्य विभाग” से अभिप्रेत है राज्य अथवा केन्द्र सरकार का वैसा विभाग जिसमें सरकारी कंपनी , निगम, उपक्रम, स्वायत्त निकाय शामिल हो तथा जो कार्य संवेदकों को अपनी ओर से किसी निर्माण कार्य के लिए वचनबद्ध करता हो ;
- (xxx) “कार्य संवेदक” से अभिप्रेत कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघटन या व्यक्ति निकाय जो कार्य विभाग से किसी करार के अधीन उक्त विभाग के लिए कार्य करता हों ;
- (2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों।

## अध्याय-II

### स्थापना और नियंत्रण

3. **खान आयुक्त की नियुक्ति**— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, खान आयुक्त नियुक्त कर सकेगी जो राज्य स्तर पर इस नियमावली के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।
4. **खान निदेशक की नियुक्ति**— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, खान निदेशक नियुक्त कर सकेगी जो जिला स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालयों में इस नियमावली के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।
5. **समाहर्ता की भूमिका**—
  - (1) जिले का समाहर्ता अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।
  - (2) समाहर्ता इस नियमावली के अधीन खनन अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सक्षम भी होगा।
  - (3) समाहर्ता जिलों के सभी खनन अधिकारियों पर सीधा नियंत्रण एवं अधीक्षण का प्रयोग करेगा।
  - (4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, खान विभाग के खनिज विकास पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी अथवा राजस्व विभाग के उप समाहर्ता से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को, वैसे पदनाम, शक्तियों तथा कर्तव्यों के साथ, जो सरकार उचित समझे, समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त कर सकेगी।
6. **पुलिस अधीक्षक की भूमिका**— पुलिस अधीक्षक निम्नलिखित करेगा :—
  - (क) अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में समाहर्ता को सहायता करना ;
  - (ख) समाहर्ता के सीधे नियंत्रण एवं अधीक्षण के अधीन कार्य करना;
  - (ग) अधिनियम तथा इस नियमावली के अधीन यथा निर्गत समाहर्ता, या खान आयुक्त अथवा खान निदेशक के विधि पूर्ण निदेशों को लागू तथा क्रियान्वयन करना ;
  - (घ) वैसा प्रतिवेदन उस रीति से समर्पित करना जैसी समाहर्ता अथवा खान आयुक्त या खान निदेशक की इच्छा हो।
7. **खान आयुक्त की शक्तियाँ एवं कृत्य**— खान आयुक्त
  - (क) राज्य में सभी खनन अधिकारियों पर सभी नियंत्रण तथा अधीक्षण का प्रयोग करेगा ;
  - (ख) ऐसे दस्तावेजों, लेखा अथवा अन्य साक्ष्य जिसे उचित समझा जाय, सूचना द्वारा, अपने समक्ष उपस्थापित करने हेतु किसी लघु खनिज समुदान धारक से अपेक्षा कर सकेगा।
  - (ग) अधिनियम तथा इस नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी, अधिकारी अथवा उसके अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा संचालित किसी कार्यवाही के अभिलेख की मांग तथा परीक्षण, स्वप्रेरण्य से, कर सकेगा और यदि उसका विचार हो कि उसमें पारित कोई आदेश गलत अथवा राजस्व, खान नियमावली के हितों तथा पर्यावरणीय शर्तों के प्रतिकूल है तो वह लघु समानुदान धारक अथवा संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश

- पारित कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे ;
- (घ) खनिज समानुदान धारक के क्रियाकलापों का अनुश्रवण करेगा तथा यदि उसका प्रथमदृष्टया समाधान हो जाता है कि कोई खनिज समुदान धारक लीज/बंदाबस्ती की सभी या किसी शर्त का उल्लंघन किया है अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा निर्गत विधिपूर्ण निदेश को पूरा नहीं कर रहा है तो वह समाहर्ता को इस लीज या बंदाबस्ती को रद्द/निलंबित करने हेतु कार्यवाही आरंभ करने हेतु निदेश देगा:
8. **खान निदेशक की शक्तियाँ एवं कृत्य—**
- (1) वह खान निदेशालय का प्रधान होगा और विभाग के सभी खनन पदाधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करेगा।
  - (2) वह राज्य में सभी खनन प्रचालनों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह यह भी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि राज्य के हित सुरक्षित हैं और सभी खनिज समुदान धारक, निगम, अन्य अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार क्रियाशील हैं।
  - (3) वह स्वामिस्व तथा अन्य भुगतेय राजस्वों के संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा।
  - (4) उसके अधीन एक सुरक्षा निदेशालय हो सकेगा जो सिविल/पुलिस कर्मी अथवा सेवानिवृत्त सुरक्षा/पारा मिलिटरी/पुलिस कर्मी से प्रतिनियुक्त अथवा भर्ती द्वारा पर्याप्त कर्मी को नियोजित कर सकेगा।
  - (5) सुरक्षा निदेशालय निदेशक के नियंत्रण तथा अधीक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का कारित अपराधों के अनुसंधान सहित, निर्वहन करेगा जो निदेशक द्वारा उसे समनुदेशित किया जाय।
  - (6) सुरक्षा निदेशालय की संरचना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
9. **जिला स्तर पर खनन अधिकारी—** राज्य के सभी जिलों में एक खनन कार्यालय होगा जिसके प्रधान राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक समुचित खनन अधिकारी करेंगे।
10. **विशेष शक्तियों के साथ व्यक्ति—** राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के विचार से खनन अधिकारी से अन्यथा किसी सरकारी कृत्यकारी को इस नियमावली अधीन किसी खनन अधिकारी के सभी या किसी कृत्य के पालन हेतु शक्तियों से सशक्त कर सकेगी और वैसा व्यक्ति इन कृत्यों के प्रयोग में एक खनन अधिकारी समझा जाएगा।

### अध्याय—III

#### खनन संक्रियाओं का दायित्व लेने संबंधित सामान्य प्रतिबंध

11. **बिना अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा के खनन प्रचालन का प्रतिषेध—**
- (1) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में, खनन संक्रियाएँ इस नियमावली के अधीन अनुदत्त, यथा स्थिति, अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन तथा उसके निबंधनों और शर्तों के अनुसार करेगा, अथवा नहीं :  
परन्तु इस उप नियम की कोई बात उन खनन संक्रियाओं पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका खनन किसी क्षेत्र में इस नियमावली के प्रारंभ के पूर्व अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया गया हो।
  - (2) कोई भी खनन पट्टा अथवा खनन अनुज्ञप्ति इस नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध निर्गत नहीं किया जा सकेगा।
12. **खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा देने पर प्रतिबंध—**
- (1) कोई खनिज समुदान अनुज्ञप्ति/पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही देय होगा :—  
(क) सरकार के पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक न हो;  
(ख) सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय सरकार, स्थानीय प्राधिकार के उपयोग अथवा किसी अन्य आमजन के लिए अथवा विशेष प्रयोजनों के लिए यथा आरक्षित सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि के संबंध में;  
(ग) संबंधित प्रमंडलीय वन अधिकारी के परामर्श के बिना आरक्षित और सुरक्षित वन क्षेत्र के संबंध में;  
(घ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय किसी ग्राम, पुल राष्ट्रीय पथ या जल स्रोत से 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी भूमि के संबंध में ;  
(ङ) पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा अपने शब्दकोश के अर्थानुसार यथा पहचानकृत “वन” के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद के सिवाय;  
(च) सुरक्षित क्षेत्र यथा राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, कम्प्यूनिटी रिजर्वस, पारिस्थितिक

- संवेदनशील जोन, अधिसूचित आर्द्रभूमि तथा वन्य प्राणी कॉरिडोर के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र के संबंध में;
- (छ) जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18) के प्रावधानों के अधीन यथा परिभाषित जैव-विविधता विरासत दृश्यों के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र के संबंध में ; और
- (ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वर्जित खनन जोन के संबंध में।
- (2) कोई भी खनन पट्टा तथा खनन क्रिया अनुज्ञा पत्र किसी ऐसे लघु खनिज के लिए नहीं दिया जाएगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय।
- परंतु ऐसी अधिसूचना संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए जारी की जा सकेगी।
13. **सतह के नीचे सीमा-** किसी खनिज समुदान द्वारा आच्छादित क्षेत्र की सीमा भूमि के केन्द्र की ओर सतह के नीचे उर्ध्वरूप से होगी।
14. **खनन पट्टा/बंदोबस्ती के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम क्षेत्र-**
- (क) कोई व्यक्ति राज्य में 200 (दो सौ) हेक्टेयर से अधिक कुल क्षेत्र से आच्छादित करने वाला एक या अधिक खनिज समुदान किसी लघु खनिज के संबंध में अर्जित नहीं करेगा; परंतु बालू बंदोबस्ती के मामले में यह अधिकतम सीमा बिहार बालू खनन नीति, 2019 के कड़िका-5(i) में उल्लेखित नदियों के मामले में ही लागू होगा।
- (ख) खनिज समुदान देने के लिए न्यूनतम क्षेत्र 5 (पाँच) हेक्टेयर होगा:
15. **खनिज समानुदान का संहृत ब्लॉक में होना-** कोई भी खनिज समानुदान वैसे किसी क्षेत्र के संबंध में नहीं दिया जाएगा जो संहृत तथा जुड़ा न हो;
16. **खनिज समानुदान की अवधि-** लघु खनिजों के लिए खनिज समानुदान की अवधि 5 (पाँच) वर्षों की होगी ;
17. **खनन योजना-**प्रत्येक खनिज समानुदान धारक/सरकार/निगम यथा स्थिति को एक खनन योजना, खनन प्रचालन आरंभ होने के पूर्व विभाग/खनन अधिकारी के समक्ष समर्पित करना होगा। ऐसे खनन योजना किसी मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति के द्वारा तैयार की जायेगी।
- (1) **खनन योजना (प्लान) की तैयारी के लिए विचारणीय आवश्यक कारक-**  
खनन योजना (प्लान) तैयार करते समय आवश्यक निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए :-
- उत्पादन का प्राक्कलित स्तर;
  - यंत्रीकरण का प्राक्कलित स्तर;
  - प्रयुक्त होने वाली मशीनरी का प्रकार;
  - डिजल/ईंधन खपत की प्राक्कलित मात्रा;
  - खनन कार्य के कारण उखाड़े जाने वाले पेड़ों की प्राक्कलित संख्या।
  - नदी तल, खनन तल का पूर्व के तल का मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा खनन योग्य खनिज का गणना हेतु खनन योजना में उल्लेख किया जाएगा।
  - भू-जल स्तर का अध्ययन एवं भू-जल स्तर के नीचे खनन कार्य न हो इसके लिए खनन स्थल पर भू-जल का स्तर और उसका समावेश खनन योजना में किया जाएगा।
  - नदी तल के खनिज के खनन के मामले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार निरंतर बालू खनन के लिए वार्षिक पूनः पूर्ति दर की गणना करना होगा।।
  - खनन योजना में निर्धारित स्तर पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टे क्षेत्र में बालू की वार्षिक पुनःपूर्ति पर्याप्त होने से संबंधित अध्ययन।
- (2) **खनन योजना (प्लान) के महत्वपूर्ण पहलू-**उक्त खनन योजना (प्लान) में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा-
- लघु खनिज रिजर्व का स्वरूप एवं विस्तार को प्रदर्शित किया जाने वाला नियत क्षेत्र का योजना (प्लान);
  - स्थल/स्थलों जहाँ उत्खनन कार्य प्रस्तावित है और इसका विस्तार;
  - प्रस्तावित उत्खनन-स्थलों का विस्तृत क्रास सेक्शन और विस्तृत प्लान;
  - नियत क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत लघु खनिज का भंडार है, का भूतात्विक विवरण।
  - नियत क्षेत्र में हस्त-चालित खनन/यांत्रिक खनन का विस्तार।

- (vi) खान समापन योजना (प्लान) प्रगतिशील एवं अंतिम खान समापन योजना (प्लान) के तहत कार्रवाई।
  - (vii) वार्षिक कार्यक्रम और सम्पूर्ण पट्टा/बन्दोबस्ती अवधि के लिए वर्षानुवर्ष नियत क्षेत्र में उत्खनन के लिए योजना (प्लान),
  - (viii) वृक्ष/पौधों का संरक्षण एवं विकास योजना।
  - (ix) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार खनन योजना (प्लान) में उपबंधित किए जाने की अपेक्षा करे।
- (3) **खनन योजना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी जो नीचे विनिर्दिष्ट अर्हता तथा अनुभव रखता हो—**
- (i) खनन अभियंत्रण में डिग्री अथवा संसद या राज्य विधान मंडल किसी अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित अथवा सम्मिलित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 1956 का 3) की धारा 4 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा दी गई भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा उसके समतुल्य कोई अर्हता; और
  - (ii) खंड (i) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता प्राप्त करने के बाद खनन के क्षेत्र पर्यवेक्षकीय हैसियत से कार्य करने का पाँच वर्षों का व्यवसायिक अनुभव:  
परन्तु वह व्यक्ति राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के साथ पैनलकृत हो।
- (4) **खनन योजना का अनुमोदन और समर्पित किया जाना—** सभी खनिज समानुदान धारक अथवा सरकार/निगम यथा स्थिति किसी मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से तैयार किया गया और निदेशक या विभाग द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत पदाधिकारी/व्यक्ति/शैक्षणिक संस्थान/सरकारी संस्था अथवा अनुमोदित खनन योजना उस तिथि से, जिस तिथि को खनिज समुदान देने से संबंधित संसूचना, यथा स्थिति, प्राप्त की गई हो, तीन माह की अवधि अथवा अनुमोदित खनन योजना समर्पित करने के लिए विभाग द्वारा विनिश्चित/स्वीकृत अन्य अवधि के भीतर समर्पित करेगा:  
परन्तु यदि विभाग द्वारा एजेन्सी के माध्यम से खनन योजना तैयार करायी जाती है, तो उस पर होने वाले व्यय की वसूली संबंधित खनिज समानुदान धारक/बंदोबस्तधारी से की जायेगी।
- (5) **खनन योजना (प्लान) की वैधता की अवधि—** एक बार अनुमोदित खनन योजना (प्लान) सम्पूर्ण खनिज समानुदान की अवधि के लिए तब तक वैध रहेगा, जब तक कि खनिज समानुदान अवधि के दौरान वह संशोधित/परिवर्तित न हो।
- (6) **खनन योजना (प्लान) में परिवर्तन—**
- (i) निदेशक अथवा विभाग द्वारा इस निमित्त कोई प्राधिकृत व्यक्ति खनन प्लान में ऐसा परिवर्तन करने अथवा ऐसी शर्तों को अधिरोपित करने, जैसा कि वह आवश्यक समझे, लिखित रूप में आदेश द्वारा खनिज समानुदान धारक से अपेक्षा कर सकेगा, यदि ऐसा परिवर्तन अथवा शर्तों का अधिरोपन आवश्यक समझा जाय।
    - (क) खान के संचालन के अनुभव की दृष्टि से;
    - (ख) तकनीकी विकास में परिवर्तन के दृष्टिकोण से;
    - (ग) विधिक उपबंधों अथवा किसी न्यायालय के आदेश के आलोक में किसी परिवर्तन की दृष्टि से;
  - (ii) अनुमोदित खनन योजना (प्लान) में परिवर्तन की माँग का इच्छुक खनन पट्टाधारी/बन्दोस्तधारी विभाग अथवा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष परिवर्तन संबंधी आशय को बताते हुए और उसके लिए कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन करेगा;
  - (iii) निदेशक अथवा विभाग की ओर से इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी/व्यक्ति/शैक्षणिक संस्था/सरकारी एजेन्सी, खान योजना में परिवर्तन के लिए ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि के साठ दिनों की अवधि के अन्तर्गत परिवर्तन का अनुमोदन कर सकेगी/कर सकेगा अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुमोदन कर सकेगी/कर सकेगा, जैसा कि वह समीचीन समझे;
  - (iv) जहाँ साठ दिनों की उपर्युक्त अवधि के अन्तर्गत कोई निर्णय संसूचित नहीं किया जाता है तो यथास्थिति खनन योजना (प्लान) या परिवर्तित खनन योजना (प्लान)

- अथवा खनन स्कीम तबतक औपबधिक तौर पर अनुमोदित समझा जाएंगे, जब तक उस विषय में अंतिम निर्णय संसूचित न कर दिया जाय।
- (v) पट्टे क्षेत्र या उत्पादन क्षमता में किसी भी वृद्धि के मामले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के सक्षम प्राधिकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- (7) (i) **खान समापन योजना (प्लान)**—प्रत्येक खान में खान समापन प्लान होगा, जो दो प्रकार के होंगे—
- (क) उत्तरोत्तर खान समापन योजना (प्लान); और
- (ख) अंतिम खान समापन योजना (प्लान)।
- (ii) **उत्तरोत्तर खान समापन योजना (प्लान) का समर्पण —**
- (क) खनन पट्टा/बन्दोबस्ती की स्वीकृति के मामले में, खनन पट्टा/बन्दोबस्ती का मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक, यथास्थिति, इस निमित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के यहाँ खनन पट्टा के एक घटक के रूप में एक उत्तरोत्तर खान समापन प्लान ऐसे खनिज समानुदान की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (ख) यथास्थिति विभाग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी इसकी प्राप्ति की तिथि के नब्बे दिनों के अन्तर्गत उत्तरोत्तर खान समापन योजना (प्लान) के अपने अनुमोदन अथवा इंकार के विषय में अवगत कराएगा।
- (ग) यदि विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत खनन पट्टा/बन्दोबस्ती के मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक को उत्तरोत्तर खान समापन प्लान के अनुमोदन अथवा इंकार के बारे सूचित नहीं किया जाता है, तो उत्तरोत्तर खान समापन प्लान को औपबधिक तौर पर अनुमोदित समझा जाएगा और जब कभी संसूचित हो ऐसा अनुमोदन अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- (iii) **अंतिम खान समापन योजना का समर्पण —**
- (क) खनिज समानुदान धारक का मालिक एजेन्ट अथवा प्रबंधक खान के प्रस्तावित समापन के एक वर्ष पूर्व विभाग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष अंतिम खान समापन योजना (प्लान) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।
- (ख) विभाग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी यथास्थिति इसकी प्राप्ति की तिथि के नब्बे दिनों के अन्तर्गत अंतिम खान समापन योजना (प्लान) को अपने अनुमोदन अथवा इंकार के बारे में खनन पट्टा/बन्दोबस्ती के मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक को अवगत कराएगा।
- (ग) यदि यथा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत खनिज समानुदान धारक के मालिक एजेन्ट अथवा प्रबंधक को अंतिम समापन प्लान के अनुमोदन अथवा इंकार के विषय में सूचित नहीं किया जाता है, तो अंतिम खान समापन प्लान को औपबधिक तौर पर अनुमोदित समझा जाएगा और जब कभी संसूचित हो, ऐसा अनुमोदन अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- (घ) खान योजना, परिवर्तित खान योजना की तैयारी के लिए आवश्यक कारक तथा अंतिम खान समापन योजना की सुपूदगी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी मार्गदर्शन के अधीन रहते हुए होगी।
18. **पर्यावरण की सुरक्षा—**
- (1) खनिज समानुदान का प्रत्येक धारक खनन प्रचालन, सज्जीकरण क्रशिंग अथवा कोई सहबद्ध क्रियाकलाप संचालित करते समय पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी संभव पूर्व सावधानी लेगा:
- (2) **पर्यावरणीय स्वीकृति**—सभी खनिज समानुदान धारक अथवा सरकार / निगम यथा स्थिति प्रचलित पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना और भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अंतिम अनुदेशों के अनुसार तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर लेंगे।

परन्तु भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिला समाहर्ता द्वारा समय-समय पर, निर्गत पर्यावरणीय सुरक्षा तथा पर्यावरणीय अनापत्ति से संबंधित अन्य अनुदेशों को मानेंगे और पालन करेंगे।

- (3) **पर्यावरणीय अनापत्ति के अनुसार खनन प्रचालन होना**— सभी खनन प्रचालन पर्यावरणीय अनापत्ति के अधीन अधिकथित निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार होंगे।
19. **जिला खनिज फाउन्डेशन निधि में अंशदान**—
- (1) खनिज समुदान धारक जिला खनिज फाउन्डेशन निधि में, जो जिला खनिज फाउन्डेशन निधि (न्यास) नियमावली के अनुसार सृजित की गई हो, राज्य सरकार द्वारा विहित दर पर खनन और खनन क्रिया द्वारा प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के लाभ के लिए जमा अथवा भुगतान करेंगे।
- (2) वह रीति जिस रीति से भुगतान की अपेक्षा हो तथा भुगतान का ढंग राज्य सरकार द्वारा सुसंगत नियमावली में विहित किया जाएगा।
20. **वन क्षेत्रों में खनन**—
- (1) किसी वन क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले लघु खनिजों की बंदोबस्ती समाहर्ता द्वारा इस शर्त के साथ की जा सकेगी कि भावी बंदोबस्ती धारक वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन विभाग से सम्यक् अनुमति जाएगा।
- (2) औपचारिक खनन पट्टा विलेख वन विभाग से अपेक्षित अनापत्ति प्राप्त होने के बाद ही निष्पादित की जाएगा।
21. **अन्य शर्तें**—
- (1) विभाग किसी खनिज समानुदान धारक से पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण क्रियाकलाप करने तथा आधुनिक सुविधाओं जैसे खनन क्षेत्र या उसके परिसर पर धर्मकांटा, कम्प्यूटर, कार्यालय अधिष्ठापित करने की अपेक्षा कर सकेगा।
- (2) विभाग खनिज समानुदान धारकों पर, समय-समय पर, ऐसी अन्य शर्तें अधिकथित कर सकेगा, जैसी अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों को लागू करने के विचार से वह उचित समझे। साथ-साथ इनमें ऐसी शर्तें शामिल हैं जो किसी विशिष्ट लघु खनिज अथवा किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के प्रति विचित्र हों।

#### अध्याय—IV

#### बालू के अतिरिक्त खनन पट्टा देने की प्रक्रिया

22. किसी खनन पट्टे के रूप में कोई खनिज समानुदान केवल लोक नीलामी—सह—निविदा द्वारा ई-बिडिंग मोड में माध्यम से और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अंतिम अधिसूचना में उपवर्णित अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर, यथा विनिश्चित प्रक्रिया के अनुसार, बंदोबस्त किया जाएगा।
- (1) **लोक नीलामी—सह—निविदा द्वारा खनिज समानुदान देने के प्रयोजनार्थ, समाहर्ता क्षेत्र का निम्नलिखित विशिष्टियाँ अधिसूचित करेगा, यथा :—**
- (क) क्षेत्र तथा सीमाओं का विस्तार टोपोग्राफी संख्या;
- (ख) ग्राम, सर्किल का नाम, प्लॉट संख्या, खाता संख्या आदि;
- (ग) खनिज समानुदान की अवधि;
- (घ) नीलामी की तिथि, नीलामी की तिथि से एक माह पूर्व अधिसूचित की जाएगी।
- (2) खनिज समानुदान का प्रत्येक बोली लगाने वाला लोक नीलामी—सह—निविदा के पूर्व राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर, यथा अधिसूचित अपेक्षित दस्तावेज निम्नलिखित के साथ दाखिल करेगा—
- (क) खनन बकाया यथा प्राप्त स्वामित्व या मृत लगान और सतह लगान के संबंध में स्वच्छता प्रमाण—पत्र जैसे सक्षम अधिकारी से के संबंध में अनापत्ति प्रमाण—पत्र;
- (ख) एक शपथ—पत्र यह अभिकथित करते हुए संलग्न होगा कि आवेदक ने —
- (i) अधतन आयकर विवरणी दाखिल कर दिया है;
- (ii) अपनी कुल आय पर निर्धारित आयकर का भुगतान कर दिया है।
- (ग) प्रतिभूति के रूप नीलामी राशि के 10 (दस) प्रतिशत के बराबर राशि जो नीलामी राशि की अंतिम किस्त में समायोजित की जाएगी यदि खनन पट्टाधारक भुगतान में अन्यथा व्यतिक्रमी न हो। असफल बीडर की दशा में प्रतिभूति जमा समाहर्ता द्वारा वापस कर दी जाएगी।
- (3) **बोली की राशि का भुगतान**— बोली की राशि समान किस्तों में वार्षिक आधार पर जमा की जाएगी और प्रत्येक किस्त प्रथम वर्ष के दौरान पट्टा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष



पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा की जाएगी।

परन्तु उन पट्टों जिनका निष्पादन इस नियमावली के लागू होने के पूर्व हो चुका है वार्षिक किस्त की राशि 31 जनवरी के पूर्व जमा करता रहेगा।

परन्तु इस नियमावली में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए या अन्यथा बंदोबस्ती धारक बोली की राशि के समतुल्य मात्रा से अधिक उत्खनित और प्रेषित पत्थर/बालू की मात्रा के लिए अतिरिक्त स्वामिस्व का भुगतान करेगा।

- (4) **भुगतान में व्यक्तिक्रम**— यदि कोई किस्त विहित अवधि के पूर्व जमा नहीं जाएगी तो 24 प्रतिशत साधारण ब्याज दो माह तक प्रभारित की जाएगी और उसके बाद रद्दकरण की कार्यवाई की जाएगी।
  - (5) **न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण**—न्यूनतम आरक्षण मूल्य का निर्धारण, विभाग द्वारा, समय-समय पर, यथा विनिश्चित होगा।
  - (6) **सफल बीडर की ओर से असफलता**—यदि सफल बीडर इस संबंध में राज्य सरकार की प्रचलित अधिसूचना में यथा निर्देशित विहित समय सीमा के भीतर अन्य भुगतेय करें के साथ-साथ अपेक्षित प्रतिभूति जमा करने असफल रहता है तो उसका प्रतिभूति जमा जब्त हो जाएगी और एक नई बंदोबस्ती प्रक्रिया लोक नीलामी के माध्यम से आरंभ की जाएगी।
23. केन्द्र सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 423 (ई) दिनांक-10.02.2015 द्वारा अधिसूचित तथा अनुसूची-III के अंतर्गत सभी खनिज लोक नीलामी-सह-निविदा के माध्यम से ई-नीलामी मोड के माध्यम अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर, यथा विनिश्चय के बंदोबस्त किए जाएंगे।
24. **खनन पट्टा की मंजूरी हेतु आवेदन**— इस नियमावली में किसी बात के अंतर्गत होने पर भी, खनन पट्टा की मंजूरी के लिए आवेदन निम्नलिखित रीति से निपटाया जाएगा :—
- (1) (क) ग्रेनाइट को छोड़कर कोई खनन पट्टा समाहर्ता द्वारा मंजूर किया जाएगा।  
(ख) ग्रेनाइट खनिज का खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया जाएगा।
  - (2) किसी खनिज के संबंध में खनन पट्टा के लिए प्रत्येक आवेदन **प्रपत्र-क** में सक्षम अधिकारी अथवा समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को दिया जाएगा।
  - (3) खनन पट्टा के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ 10,000/- रुपये के शुल्क और उस भूमि का ब्योरा, जिसके संबंध में खनन पट्टा के लिए आवेदन दिया गया हो, और जहाँ अपेक्षित हो अधिकार अभिलेख का सुसंगत उदाहरण की प्रभाजित प्रतियों या प्रतियाँ साथ में देनी होगी।
  - (4) खनन पट्टा के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ बिहार राज्य में धारित सभी खनिज समुदान के संबंध में गत वित्तीय वर्ष के अंत तक का खनन बकाए, यथा स्वामिस्व या नियत लगान, सतह लगान तथा सेस के भुगतान का वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न होगा।
  - (5) प्रत्येक आवेदन के साथ यह अधिकथित करते हुए एक शपथ पत्र संलग्न होगा कि आवेदक —  
(क) अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है ;  
(ख) इसपर निर्धारित आयकर का भुगतान कर दिया है; और  
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 में यथा प्रावधानित स्वनिर्धारण के आधार पर आयकर का भुगतान कर दिया है।
  - (6) प्रत्येक आवेदन के साथ, इस राज्य में खनिज वार क्षेत्रों की विशिष्टियों को दर्शाते हुए, जिसमें आवेदक अथवा कोई व्यक्ति उसके साथ संयुक्त हो —  
(क) खनन पट्टा के अधीन पहले से धारित करता है;  
(ख) आवेदन दिया किंतु मंजूरी नहीं मिली; और  
(ग) बार-बार आवेदन देता रहा है;  
एक शपथ-पत्र संलग्न होगा।
  - (7) जहाँ आवेदक भूमि का मालिक न हो वहाँ खनन पट्टा की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ लिखित रूप में एक अभिकथन लगा होगा कि आवेदक क्षेत्र पर सतह-अधिकार प्राप्त कर लिया है अथवा खनन प्रचालन आरंभ करने के लिए स्वामियों से सहमति प्राप्त कर ली है :

परन्तु जहाँ भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में वहाँ ऐसे किसी अभिकथन की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु और कि क्षेत्र या उसके भाग में खनन प्रचालन आरंभ करने के लिए भूमि के रैयतो/स्वामियों की सहमति लीज विलेख के निष्पादन के बाद किंतु उक्त में प्रविष्टि के पूर्व सुपूर्द कर देना।

जब खनन पट्टा के लिए आवेदन के साथ उपनियम (2) से (7) तक उल्लेखित कागजात संलग्न न हो तो उसे प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर नामंजूर कर दिया जाएगा।

25. **क्षेत्र का सर्वेक्षण**— खनिज समानुदान के अधीन क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा सीमांकन खनिज समानुदान धारक द्वारा किया जाएगा और इसका सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। कोई भी खनन अथवा खनन क्रिया का प्रचालन खनन पट्टा अथवा खनन क्रिया अनुज्ञा पत्र देने के लिए आवेदित क्षेत्र की सीमाओं के सत्यापन के पूर्व आरंभ नहीं होगा।

26. **शर्तें**—

- (1) (क) प्रत्येक खनन पट्टा प्रपत्र 'ख' अथवा प्रत्येक मामले में अपेक्षित उनकी परिस्थितियों के नजदीकी प्रपत्र होगा।  
(ख) प्रपत्र 'ख' में दी गई शर्तें इस नियम के अधीन अधिरोपित शर्तें समझी जाएंगी और पट्टाधारक पर आबद्धकर होंगी।
- (2) पट्टाधारी अपने पट्टा धारण क्षेत्र की चौहद्दी पर नियमित अन्तरालों में सीमा स्तम्भों (किसी भी दशा में 20 (बीस) मीटर से अधिक नहीं) की स्थापना करेगा। उक्त सीमा-स्तम्भ कम से कम एक वर्ग फीट आयाम का तथा 1.5 मीटर ऊंचाई के रूप में प्रबलित कंकरीट का खम्भा होगा, जिसका 1/3 मात्र जमीन के नीचे गाड़ा जाएगा। जमीन से ऊपर खम्भे का भाग क्रमानुसार सफेद-काले रंग (जेबरा ढंग का) से रंग दिया जायेगा, ताकि एक विशिष्ट रूप में दिखाई पड़े।
- (3) समाहर्ता ऐसी अन्य शर्त अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह निम्नलिखित के संबंध में उचित समझे :—  
(क) लगान और रॉयल्टी के भुगतान की समय-सीमा ढंग तथा स्थान;  
(ख) खनिज समानुदान धारक भूमि के सतह अधिभोगी को उस मुआवजा का भुगतान करेगा जो इस नियमावली के अधीन भुगतेय हो गया हो;  
(ग) खनिज समानुदान धारक उस क्षेत्र में अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा चयनित किसी अन्य क्षेत्रों में किसी खनन प्रचालन के कारण नष्ट किये गए पेड़ों की संख्या के कम से कम दोगुने पौधारोपण अथवा उस हद तक जहाँ तक संभव हो ऐसे प्रचालन द्वारा नष्ट किए गए फलोरा तथा अन्य वनस्पति के प्रत्यावर्तन के लिए उपाय करेगा;  
(घ) किसी प्राधिकार द्वारा प्रतिषिद्ध किसी क्षेत्र में सतही प्रचालन पर निर्बंधन;  
(ङ) सतह अधिभोग के लिए खनिज समुदान धारक द्वारा नोटिस ;  
(च) उचित तौलने वाली मशीनों का प्रावधान;  
(छ) पट्टा क्षेत्र अथवा समवर्ती क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य खनिजों के लिए खनिज समुदान धारक द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ;  
(ज) दुर्घटनाओं को प्रतिवेदित करने;  
(झ) पिट्स एण्ड शॉफ्ट को सुनिश्चित करने;  
(ञ) तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति;  
(ट) पट्टा का समर्पण, समाप्ति या अवसान पर भूमि तथा खान का कब्जा देना;  
(ठ) युद्ध अथवा आपातकाल के कारण प्लांट, मशीनरी, परिसर तथा खानों का कब्जा लेने की शक्ति;  
(ड) लीजधारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा।
- (4) समाहर्ता, यदि उसकी राय हो कि खनिज विकास के हित में वैसा करना आवश्यक हो, सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी मामले में ऐसी शर्तों अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे।

27. **खनिज समानुदान धारक का हस्तांतरण के लिए आवेदन**—

- (1) अंतरण में हितबद्ध अंतरक तथा अंतरिती खनन बकाए जैसे बंदोबस्ती की राशि स्वामिस्व, नियत लगान, सतह लगान आदि के भुगतान संबंधित वैध अनापति प्रमाण-पत्र उपस्थापित करेगा।
- (2) (क) खनिज समानुदान धारक खनन क्रियालीज अथवा उसमें निहित किसी अधिकार, हक या हित को समनुदेशित, सब-लेट बंधक नहीं करेगा अथवा किसी अन्य

रीति से अंतरित तब तक नहीं करेगा जब तक कि समाहर्ता का पूर्व आदेश प्राप्त न हो गया हो।

- (ख) उपनियम (1) के अधीन पूर्व आदेश चाहने वाला प्रत्येक खनिज समानुदान धारक खनन पदाधिकार को एक आवेदन देगा जिसके साथ स्वामी अथवा भूमि का अधिभोगी का इस प्रभाव का सहमति पत्र लगा होगा कि अंतरिती द्वारा लघु खनिजों की खनन क्रिया के लिए उसे कोई आपत्ति नहीं है।
- (ग) खनिज समानुदान के हस्तांतरण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय/राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार /जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण की आवश्यकता होगी।

## 28. पट्टा निष्पादन—

- (1) इस नियमावली के अधीन जहाँ खनिज समानुदान दिया गया हो, वहाँ सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश के 180 दिनों के अन्दर प्रपत्र 'ख' में समाहर्ता द्वारा औपचारिक पट्टा निष्पादित किया जाएगा और यदि जिस व्यक्ति को खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है, वह व्यक्ति उपर्युक्त अवधि के अन्तर्गत निष्पादन के लिए अपेक्षित कागजात पेश करने में चूक जाता है, तो खनन पट्टा स्वीकृति आदेश प्रति संहृत समझा जायेगा और उस हालत में आवेदन शुल्क और प्रतिभूति जमा राशि जप्त हो जायेगी;
- परन्तु ऐसा कोई भी पट्टा तब तक निष्पादित नहीं किया जायेगा जब तक कि जिस व्यक्ति को ऐसा पट्टा स्वीकृत किया गया है, इस नियमावली के अधीन यथा अपेक्षित खनन योजना तथा पर्यावरणीय अनापत्ति समर्पित नहीं कर देता;
- परन्तु यह और कि जहाँ समाहर्ता को यह समाधान हो जाता है कि जिस व्यक्ति को ऐसा पट्टा स्वीकृत किया गया है, वह औपचारिक पट्टा के निष्पादन में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं है तो वह (समाहर्ता) 180 दिनों की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी औपचारिक पट्टा के निष्पादन की अनुमति प्रदान कर सकेगा।
- (2) जिस अवधि के लिए खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है उस अवधि की शुरुआत की तिथि वह तिथि होगी, जब उप-नियम (1) के अधीन खनन पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया है तथा पट्टाधारी को खनन पट्टा के निष्पादन की तिथि से किराया (रेंट)/स्वामिस्व (रॉयल्टी) का दायी होगा।
- (3) लीज विलेख उचित स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन शुल्क का भुगतान करते हुए सम्यक् रूप से निबंधित करना होगा।
- (4) लीज अवधि के विस्तार का कोई दावा किसी विलंब के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

## अध्याय—V

### बालू की बंदोबस्ती

- 29 (क) (1) बन्दोबस्ती की रीति— लघु खनिज के रूप में बालू की बन्दोबस्ती समाहर्ता द्वारा/राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा सबसे अधिक ई-बोली लगाने वाले व्यक्ति (उच्चतम डाकवक्ता) के पक्ष में सार्वजनिक नीलामी-सह-निविदा के माध्यम से किया जाएगा—
- (क) राज्य सरकार बालूघाटों के बंदोबस्ती के लिए विस्तृत प्रक्रिया के बारे में समय-समय पर और जब कभी अपेक्षित हो, अधिसूचना निर्गत करेगी।
- (ख) सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति (उच्चतम डाकवक्ता) नीलामी के तुरत बाद नीलामी राशि की 10% राशि जमा करेगा और उसके बाद सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश समाहर्ता/राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा उसके नाम से निर्गत किया जाएगा।
- (ग) उच्चतम डाकवक्ता इसके संबंध राज्य सरकार द्वारा निर्गत विद्यमान अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट विहित समय-सीमा के अन्तर्गत अपेक्षित दस्तावेज समर्पित करेगा और उसके बाद समाहर्ता/राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा उसके नाम से कार्य आदेश निर्गत किया जाएगा।
- (घ) सफल डाकवक्ता अथवा सरकार/निगम यथा स्थिति संबंधित बालूघाट के लिए तैयार और निदेशक अथवा इसके संबंध में यथा प्राधिकृत पदाधिकारी/व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित एक खनन योजना समर्पित करेगा।
- (ङ) सफल डाकवक्ता अथवा सरकार/निगम यथास्थिति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरण समाघात मूल्यांकन अधिसूचना के अनुसार और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सक्षम पदाधिकारी से पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करेगा।

## (2) बालू खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र—

- (i) बालू का उत्खनन किसी रेलवे पुल अथवा किसी राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के अन्तर्गत पड़ने वाले किसी पुल के दोनों ओर 300 (तीन सौ) मीटर दूरी के अन्तर्गत निषिद्ध होगी और किसी अन्य पुल के दोनों ओर की 100 (एक सौ) मीटर की दूरी के अन्दर निषिद्ध होगी। तथापि इसके संबंध में किसी अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा किसी पुल के बारे में इस निषिद्ध क्षेत्र का विस्तार किया जा सकेगा, यदि वैसी आवश्यकता सुरक्षा के कारणों से हो।
- (ii) सार्वजनिक स्थल यथा शमशान घाट/कोई धार्मिक स्थल आदि के 50 मीटर अन्दर उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iii) नदी के दोनों किनारों से 5 (पाँच) मीटर के अन्तर्गत उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iv) बालू की उत्खनन सिंचाई प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी डैम, बंधारा अथवा कोई अन्य संरचना से उपरिधारा और निचली धारा के 100 (एक सौ) मीटर के अन्तर्गत निषिद्ध रहेगी।
- (v) अधिमानतः बालूघाट तटबंध के नदी भाग में रहेगा। 6 मीटर से कम ऊँचाई वाले तटबंधों के लिए तटबंध के टो/हील से 25 मीटर तक उत्खनन प्रतिबंधित होगा एवं इसके परे 1.00 मीटर गहराई तक उत्खनन की अनुमति होगी। उच्च तटबंधों के मामले में तटबंध के टो/हील से 50 मीटर तक उत्खनन प्रतिबंधित होगा एवं इसके परे 75 मीटर की दूरी तक अधिकतम 1.50 मीटर गहराई तक तथा 75 मीटर की दूरी के आगे अधिकतम 2.00 मीटर गहराई तक उत्खनन की अनुमति होगी। तटबंध के लिए समानान्तर प्रवाह के विकास को कम करने के लिए माईनिंग पिट्स के गहराई के आठ गुणा चौड़ाई का क्रॉसबार 50 से 60 मीटर केन्द्र से केन्द्र अंतराल पर रखा जाना अनिवार्य होगा।
- (vi) सिंचाई मार्ग को उसी स्तर पर बनाये रखा जायेगा जैसा कि नदी तल का स्तर है और किसी भी दशा में नदी तल का स्तर सिंचाई मार्ग के स्तर से नीचे रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्तःस्तूप कूप/अन्तर्ग्राही कूप के चारों ओर 5 मीटर की दूरी तक उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (vii) वैसी नदियों, जहाँ से सिंचाई नहर का प्रवाह निकलता है, के मामले में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के उपरान्त ही बालू निकासी की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- (viii) बन्दोबस्तधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की रैयती भूमि में बालू उत्खनन की अनुमति तबतक नहीं दी जाएगी जब तक कि बन्दोबस्तधारी द्वारा संबंधित भू-स्वामी (रैयत) की सहमति प्राप्त नहीं कर ली जाती है।
- (ix) वैसे किसी क्षेत्र में बालू उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार ने प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है।

## (3) बालू उत्खनन के लिए अधिकतम अनुज्ञेय गहराई— नदी तल में बालू उत्खनन की अधिकतम गहराई किसी समय में अखनित तल स्तर से तीन मीटर अथवा जल स्तर में, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

## (4) न्यूनतम आरक्षण मूल्य का निर्धारण—

- (i) न्यूनतम आरक्षण मूल्य का निर्धारण विभाग द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित होगा।
- (ii) यदि तीन बार प्रयासों के बाद भी उक्त निर्धारित न्यूनतम सुरक्षित मूल्य पर नीलामी की प्रक्रिया के दौरान कोई बीडर नहीं मिलता है तो न्यूनतम सुरक्षित मूल्य, विभागीय तकनीकी समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र और अन्य स्थानीय/तकनीकी दशाओं में निक्षेपित बालू के आधार पर तथा समाहर्ता की अध्यक्षता वाली जिलास्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त कर पुनरीक्षित की जा सकेगी। उक्त खण्ड/बालू खंड/बालूघाट की पुनः नीलामी, राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, पुनरीक्षित न्यूनतम सुरक्षित मूल्य के आधार पर की जाएगी।

## (5) उच्चतम डाकवक्ता की ओर से चूक—यदि सफल डाकवक्ता, राज्य सरकार की अभिभावी अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट विहित समय-सीमा के भीतर अन्य भुगतान कर के साथ-साथ अपेक्षित प्रतिभूति जमा जमा करने के चूक करता है तो उसकी प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जाएगी और लोक नीलामी के माध्यम से संबंधित बालूघाट इकाई/पट्टी/बालूघाट के लिए एक नई बंदोबस्ती प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

## 29 (ख) (1) प्रतिभूति जमा का भुगतान।—लघु खनिज के रूप में बालू का प्रत्येक बन्दोबस्तधारी, बन्दोबस्ती

के निबंधन एवं शर्तों के सम्यक् अवलोकन के लिए प्रतिभूति जमा राशि के रूप में नीलामी/ निविदत्त राशि के 25 (पच्चीस) प्रतिशत के समतुल्य राशि जमा करेगा, जो सक्षम पदाधिकारी (नियमावली में यथा परिभाषित) द्वारा बन्दोबस्ती की अंतिम किस्त में समायोजित की जाएगी/बन्दोबस्ती अवधि की समाप्ति के बाद लौटायी जाएगी।

(2) **समानुदान प्रदान करना तथा विलेख का निष्पादन**—सफल डाकवक्ता को 5 वर्षों की कालावधि के लिए समानुदान प्रदान किया जाएगा। सफल डाकवक्ता इस नियमावली में विहित प्रपत्र—‘ख’ में अथवा उसके समरूप प्रपत्र में कार्य आरंभ करने के पूर्व खनिज समानुदान विलेख निष्पादित करेगा। अगर किसी कारणवश खनन योजना अनुमोदित नहीं हुई एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई हो तो उस स्थिति में सफल निविदादाता खनन पट्टा निष्पादन के पूर्व उसे प्राप्त करेगा।

(3) **स्वामिस्व/बंदोबस्ती राशि के भुगतान की रीति—**

(i) बंदोबस्तधारी निविदा दस्तावेज में यथोपदर्शित बंदोबस्ती की राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ii) निकाले गए खनिजों के लिए वार्षिक आधार पर की गई स्वामिस्व की संगणना वार्षिक बंदोबस्ती की राशि से यदि अधिक हो तो बंदोबस्तधारी निकाली गई अतिरिक्त मात्रा के लिए बंदोबस्ती राशि के अतिरिक्त अत्याधिक स्वामिस्व के भुगतान के लिए दायी होगा।

(4) **भुगतान में चूक**— विहित तिथि के भीतर किसी किस्त का भुगतान में चूक की स्थिति में, वार्षिक 24 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

29(ग) **खनन योजना (प्लान)/पर्यावरण क्लीयरेंस के शर्तों एवं बंधेजों का पालन**— बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती से संबंधित खनन योजना (प्लान) के शर्तों एवं बंधेजों और पर्यावरण क्लीयरेंस में दिये गये शर्तों एवं बंधेजों का पालन करेंगे।

29घ **बालूघाटों में मशीनरी लगाना**— बंदोबस्तधारी सतत् बालू खनन प्रबंधन मार्गदर्शन, 2016/पर्यावरणीय अनापत्ति में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगा।

29ङ **ऑन लाईन बालू पोर्टल**— बंदोबस्तधारी सभी उपभोक्ताओं (छोटे, मध्यम एवं बड़े) को बालू का विक्रय या तो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड के माध्यम से करेगा। सभी संव्यवहार/भुगतान, उत्खनन/उत्पादन/परिवहन भंडारण का ब्योरा विभागीय ऑनलाइन रीयल टाइम मोनिटरिंग सिस्टम द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा। बालू का विक्रय इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण, जो केन्द्रीय दस्तावेजीकरण अनुश्रवण सुविधा से जुड़ा रहेगा, से नियंत्रित किया जाएगा और बंदोबस्तधारी द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभागीय पोर्टल पर डाला जाएगा।

29च **धर्मकांटा का प्रतिष्ठापन**—प्रत्येक बालूघाट पर सेंट्रल सर्वर से एकीकृत एक इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा का अधिष्ठापन हो सकेगा। हालांकि संलग्न बालूघाटों के लिए विभाग कॉमन धर्मकांटा के उपयोग की स्वीकृति दे सकेगा। उचित वजन/ई—चालान बिना बालू ढोते पाया जाने वाला कोई वाहन खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 या उसके अधीन बनी नियमावली के प्रावधानों के अधीन जब्त किए जाने का दायी हो सकेगा।

29छ **गाद निकालने का जिम्मा लेने हेतु सरकार का अधिकार**— राज्य सरकार के पास ऐसे खनन ब्लॉकों में नदी प्रवाह, बाधों की सुरक्षा तथा जीओ तकनीकी एवं जल विज्ञानी विचारणों के चलते नदियों के साथ निवासियों को बनाए रखने हेतु डिशिप्लिंग ऐजेन्ट को अपने हाथ में रखने का अधिकार आरक्षित है। विभाग गाद निकालने की प्रक्रिया में निकाले गए बालू के निष्पादन के लिए मार्गदर्शन जारी करेगा।

29ज **रैयती भूमि से उप मिट्टी बालू का हटाया जाना**— खनिज समानुदान धारक भू-स्वामियों की सहमति लेने और पर्याप्त प्रतिकर देने के बाद रैयती भूमि से उपमिट्टी बालू को हटा सकेगा। ऐसे प्रस्ताव खनन योजना में शामिल किए जाएंगे और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से सम्यक् पर्यावरणीय अनापत्ति खनन प्रचालन आरंभ करने के पूर्व प्राप्त किया जाना है।

29झ **जल संसाधन विभाग से अनापत्ति**— किसी बालूघाट से बालू उठाने की दशा में यदि लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो तो खनिज समानुदान धारक जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे। आवेदन की तिथि के एक माह के भीतर यदि इस संबंध में खनिज समानुदान धारक को कोई विनिश्चय संसूचित नहीं किया जाय तो यह समझा जाएगा कि संबंधित विभाग को इस प्रस्ताव में कोई आपत्ति नहीं है।

30. **निर्बंधनों के भंग की दशा में शास्ति—**

(1) प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर खनन अथवा 3 मीटर की गहराई से अधिक बालू खनन की दशा में प्रथम बार उल्लंघन के लिए बंदोबस्तधारी के विरुद्ध एक लाख की शास्ति समाहर्ता द्वारा अधिरोपित की जाएगी।

(2) द्वितीय बार उल्लंघन के लिए बंदोबस्तधारी के विरुद्ध पाँच लाख रुपये से दस लाख

- रूपये तक की शास्ति अनियमितता की गंभीरता के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी।
- (3) तृतीय अथवा उससे अधिक बार ऐसे अपराध में जब कभी खनिज समानुदान धारक संलिप्त पाया जाता है तो उस विशिष्ट बालूघाट की बंदोबस्ती समाहर्ता द्वारा अस्थायी रूप से अधिकतम एक माह के लिए निलंबित की जा सकेगी जबतक कि उल्लंघनों में सुधार न कर लिया जाय। समाहर्ता द्वारा इस संबंध में दिए गए समय के भीतर यदि उल्लंघनों में सुधार नहीं किया जाता है तो संबंधित बालूघाट की बंदोबस्ती के रद्दकरण की कार्यवाई की जाएगी।
- (4) बालू का परिवहन केवल ढके हुए वाहनों से क्रियान्वित किया जाएगा और कोई गीला बालू वाहनों में नहीं लादा जाएगा। गीला और बिना ढके बालू के किसी परिवहन के लिए उक्त वाहन में लदे बालू के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना परिवहनकर्ता के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

#### अध्याय— VI

##### राज्य स्वामित्व वाले खनन निगम में भूमिका

31. **बिहार राज्य खनन निगम द्वारा क्रियाकलाप।** — (1) राज्य सरकार सभी अथवा किसी खनन क्रियाकलाप अथवा व्यापार, बिहार राज्य खनन निगम को सौंपेगा। निगम विशेषकर बालू के खनन क्रियाकलाप, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, भंडारण, परिवहन आदि की जिम्मेवारी ले सकेगा:
- (2) निगम उक्त प्रयोजनार्थ किसी सरकार अथवा अर्धसरकारी अथवा प्राईवेट उपक्रम के साथ कोई व्यवस्था कर सकेगा।
32. **निगम द्वारा विहित दरों पर खनिज का क्रय किया जाना।** — विभाग सभी खनिज समानुदान धारकों को अपने उत्पाद का कुछ अनुपात जो उनके उत्पाद का 50 प्रतिशत से अनधिक होगा, निगम को पिट हेड मूल्य पर विक्रय करने हेतु निदेश दे सकेगा।

#### अध्याय— VII

##### खनन क्रिया अनुज्ञा पत्र देने की प्रक्रिया

33. **खनन क्रिया अनुज्ञा पत्र देना—**(1) आवेदन दिए जाने पर, खनन अधिकारी किसी व्यक्ति को अपनी अधिकारिता के भीतर किसी विनिर्दिष्ट भूमि से दस हजार घनमीटर से अनधिक किसी खनिज बालू एवं पत्थर को छोड़कर का एक अनुज्ञा पत्र के अधीन **अनुसूची—III 'क'** में विनिर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी के पूर्व भुगतान पर, उत्खनन एवं हटाने के लिए **प्रपत्र 'घ'** में खनन क्रिया पर परमिट दे सकेगा। ऐसा परमिट देने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी स्वयं यह समाधान कर लेगा कि परमिट की अपेक्षाएँ सही हैं और कि उस क्षेत्र में खनन लीज प्राप्त करने की आवश्यकताओं का निवारण नहीं करती जिसके संबंध में खनिज के निष्काषण के लिए आवेदन दिया गया है।
- (2) खनन अधिकारी लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ ऐसे परमिट जारी करने से इंकार कर सकते हैं।
- (3) इस नियम के अधीन साधारण मिट्टी के निष्कासन के लिए परमिट वैसे मामलों के लिए, जहाँ साधारण मिट्टी/क्ले/मृदा के नीचे "बालू निक्षेप" उपलब्ध हो, तीन फीट की गहराई से अधिक उत्खनन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी रैयत खनन के लिए किसी व्यक्ति को पहले ही लीज दी गई/बंदोबस्त की गई किसी विनिर्दिष्ट भूमि से खनन के लिए परमिट हेतु कोई दावा नहीं कर सकता है।
- (4) विभाग किसी विशिष्ट खनिज या खनिजों के लिए खनन कार्य हेतु अनुज्ञा परमिट देने पर रोक लगाने के अनुदेश जारी कर सकेगा।
34. **खनन परमिट के लिए आवेदन—**(1) खनन क्रिया परमिट के लिए आवेदन **प्रपत्र 'ग'** में खनन अधिकारी को समर्पित किये जाएंगे।
- (2) खनन कार्य हेतु परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ (5,000/—रु0) की फीस (बंगला भट्टा के परमिट के लिए फीस केवल 500/— रु0 ) संलग्न करना होगा।
- (3) खनन क्रिया परमिट के प्रत्येक आवेदन के साथ एक वैध तथा खनन बकाए के यदि कोई हो, भुगतान का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाएगा। अगर खनन हेतु भूमि रैयती है तो रैयत से अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि रैयत को उनके भूमि से खनिज निकालने में कोई आपत्ति नहीं है।
- (4) आवेदन फीस और रॉयल्टी वापस नहीं की जाएगी यदि रैयत बाद में रैयती क्षेत्रों में अनुज्ञापतिधारक को कार्य करने की अनुमति देने से इन्कार कर दे।
- (5) परमिट की अवधि विस्तार के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ 1000/— रुपये की फीस संलग्न करना होगा।
- (6) खनन क्रिया परमिट देने के लिए आवेदित क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक आच्छादित नहीं करने वाले संहत ब्लॉक में होगा।

35. **खनन क्रिया परमिट के लिए आवेदन का निपटारा।—**

- (1) खनन क्रिया देने के लिए आवेदन का निपटारा खनन अधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
- (2) यदि किसी आवेदन का निपटारा उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

36. **शर्तें जिन पर खनन क्रिया परमिट दिया जाएगा :—**

- (1) नियम 33(1) के अधीन दिये जाने वाले प्रत्येक खनन क्रिया परमिट में एक शर्त अंतर्विष्ट होगी कि सतह के नीचे अधिकतम 3 (तीन) मीटर तक ही खनन कार्य किया जाएगा।
- (2) नियम 33(1) के अधीन दिये जाने वाले किसी खनन क्रिया परमिट में ऐसी निम्नलिखित अन्य शर्तें अंतर्विष्ट हो सकेंगी जिसे आवश्यक समझा जाय यथा—
  - (क) लगान तथा रॉयल्टी के भुगतान की समय सीमा, ढंग तथा स्थान;
  - (ख) परमिट द्वारा अच्छादित भूमि के नुकसान के लिए छतिपूर्ति;
  - (ग) पेड़ों को गिराने के लिए वन क्षेत्रों की दशा में प्रमंडलीय वन अधिकारी के परामर्श से तथा अन्य क्षेत्रों की दशा में अपर समाहर्ता के परामर्श से;
  - (घ) किसी प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किसी क्षेत्र में सतह प्रचालन पर रोक;
  - (ङ०) दुर्घटनाओं को प्रतिवेदित करना ;
  - (च) तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति;
  - (छ) अवधि का निर्धारण जिसके भीतर लघु खनिज निकाले और प्रेषण करेंगे एवं अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर अथवा लघु खनिज, जिसके के लिए परमिट वैध हो, की मात्रा के हटाए जाने पर भूमि कब्जा का परिदान;
  - (ज) परमिट के रद्दकरण के बाद बची हुई संपत्ति की जप्ती; तथा
  - (झ) परमिट की समाप्ति के बाद स्टॉक स्थल में खनिजों का निपटारा।
- (3) दिए गए परमिट के अध्यक्षीन किसी शर्त के भंग होने की दशा में खनन अधिकारी अपने द्वारा निर्गत परमिट को रद्द कर सकेगा। परमिट के रद्दकरण पर, भूमि पड़ी खनन क्रिया की गई खनिज सामग्री जिससे वह निकाली गई हो, सरकार की अनन्य संपत्ति हो जाएगी और खनन अधिकारी द्वारा लोक नीलामी द्वारा बेची जा सकेगी।
- (4) खनन अधिकारी, जाँच पड़ताल तथा सत्यापन के बाद विहित अवधि के अंत में अधिक मात्रा के लिए रॉयल्टी और शास्ति की राशि का निर्धारण करेगा।
- (5) प्रत्येक परमिट धारक नियम 18(2) में यथा विनिर्दिष्ट पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करेगा।
- (6) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी (परमिटधारी) निम्नलिखित शर्तों का भी अनुपालन करेगा :—
  - (i) ईट निर्माण, पथ निर्माण, तटबंध निर्माण आदि के प्रयोजनार्थ ईट मिट्टी और साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन से संबंधित क्रियाकलाप में विस्फोटक का प्रयोग नहीं होगा।
  - (ii) खनन/ उत्खनन क्रियाकलाप में कार्य स्थल पर सामान्य धरातल स्तर के 3 मीटर के नीचे अधिकतम गहराई के संबंध में प्रतिबंध रहेगा।
  - (iii) खनन/ उत्खनन संबंधी क्रियाकलाप कार्य स्थल पर भूजल स्तर से ऊपर किया जाएगा।
  - (iv) खनन/उत्खनन संबंधी क्रिया-कलाप क्षेत्र के सामान्य जल निकासी के प्रतिरूप (पैटर्न) को परिवर्तित नहीं करेगा।
  - (v) खोदे गए/ उत्खनित गड्ढा (पिट) को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोगी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा।
  - (vi) खोदे गए/ उत्खनित गड्ढा के चारों ओर समुचित घेराबंदी कर दी जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।
  - (vii) ढुलाई के दौरान खोदी गई/उत्खनित मिट्टी के फैलने से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए उपाय किए जायेंगे।
  - (viii) मिट्टी के खनन/उत्खनन के कारण सृजित जल निकायों में रोगवाहकों (वेक्टर) के प्रजनन के कारण स्वास्थ्य खतरों के विरुद्ध सुरक्षा मानक अपनाये जायेंगे।
  - (ix) कामगारों/मजदूरों को पेयजल और सफाई संबंधी सुविधायें प्रदान की जायेगी।
  - (x) प्रस्तावित उत्खनन की गहराई के कम से कम आधे के बराबर चौड़ाई रखने वाले सटे मैदानों की सीमा से पटरी छोड़ दी जायेगी।
  - (xi) किसी उत्खनन क्षेत्र की परिधि से किसी असैनिक संरचना की दूरी कम से कम

15 मीटर रखी जायेगी।

- (xii) राष्ट्रीय पार्कों और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलो मीटर के अन्दर उत्खनन के क्षेत्र के मामले में "ईट मिट्टी" अथवा साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन की अनुमति नहीं दी जायेगी:

परन्तु अनुज्ञापत्रधारी (परमिटधारी) द्वारा इस संबंध में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किसी अन्य शर्त अथवा निर्गत किसी अनुदेश का पालन किया जाएगा।

- 37 (1) **भवन/संरचना/विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्राप्त खनिज के लिए खनिज निपटान परमिट दिया जाना**—इस नियमावली किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, जहाँ कोई खनिज किसी भवन निर्माण अथवा विकास योजना की प्रक्रिया में प्राप्त हो और उस परियोजनाओं की प्रक्रिया में निकाला गया हो तो समाहर्ता, संबंधित खनन अधिकारी के प्रतिवेदन पर, वैसी किसी विनिर्दिष्ट भूमि से, जो पहले खनन के लिए किसी व्यक्ति को पहले लीज बंदोबस्त न की गई हो, ऐसे किसी लघु खनिज को हटाने एवं उसका उपयोग करने के लिए परमिट दे सकेगा। उक्त अनुमति विनिर्दिष्ट मात्रा तथा अनधिक तीन माह के लिए अग्रिम सरकार के लिए स्वामिस्व तथा अन्य प्रकार के भुगतान पर दी जा सकेगी।
- (2) **सिंचाई विभाग द्वारा नहर तथा जल निकास प्रणाली के संधारण की प्रक्रिया में निष्कासित खनिजों के लिए खनिज निपटाव परमिट दिया जाना**— इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहाँ किसी नहर या जल निकासी प्रणाली अथवा जल निकास की सफाई, संधारण और रख-रखाव की प्रक्रिया में किसी गाद या बालू या साधारण मिट्टी या किसी अन्य खनिज को निकाला जाता है वहाँ समाहर्ता, संबंधित खनन अधिकारी के प्रतिवेदन पर वैसी किसी लघु खनिज को हटाने और उपयोग करने का परमिट दे सकेगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता उक्त खनिज के निपटाव के लिए परमिट निर्गत करने हेतु खनन अधिकारी के समक्ष एक आवेदन देगा। उक्त अनुमति सरकार को लागू स्वामिस्व तथा अन्य प्रकार के अग्रिम भुगतान पर विनिर्दिष्ट मात्रा तथा अनधिक तीन माह के लिए दी जा सकेगी।
- (3) **विनिर्दिष्ट आपात स्थितियों के लिए परमिट**— इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समाहर्ता उस क्षेत्र से लघु खनिज निष्कासन के लिए परमिट दे सकेगा जो वैसी सरकारी विभाग अथवा किसी सरकारी एजेन्सी अथवा किसी व्यक्ति को, जिसे आपात दशा में मानव एवं मवेशी जीवन की सुरक्षा के लिए आपात बाढ़ सुरक्षा कार्य अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा अन्य दबावकारी परिस्थितियों से संबंधित कार्य निष्पादन के लिए खनिज की आवश्यकता हो। उक्त अनुमति सरकार को लागू स्वामिस्व तथा अन्य प्रकार के अग्रिम भुगतान पर दी जा सकेगी।

नियम 37(1), (2) और (3) के अधीन सभी आवेदन प्रपत्र—'ड.' में होंगे परमिट प्रपत्र—'च' में दिए जाएंगे।

#### अध्याय— VIII

ईट भट्टों से राजस्व संग्रहण तथा विनियमन।

38. **ईट मिट्टी पर समेकित स्वामिस्व का निर्धारण—**

- (1) इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार इस नियमावली की अनुसूची—III ख में यथोल्लिखित प्रति वर्ष प्रति ईट भट्टा से समेकित स्वामिस्व या भुगतान पट्टा के स्वामी/ ईट मिट्टी हटाने वाले से प्राप्त करेगी एवं प्रत्येक वर्गीकृत क्षेत्र के लिए ईटों की नियत संख्या पर समेकित स्वामिस्व निर्धारित करेगी जो तीन वर्षों में एक बार पुनरीक्षित की जा सकेगी, विनिश्चित कर सकेगी।

परन्तु राज्य सरकार, इस प्रकार दी जाने वाली स्वामिस्व की समेकित राशि विनिश्चित करने के लिए प्रयोजनार्थ स्थान को उन तथ्यों का ध्यान रखते हुए जिसे राज्य सरकार उचित समझे, विभिन्न कोटि में वर्गीकृत कर सकेगी।

- (2) **कार्रवाई करने हेतु अनुमंडल अधिकारी तथा अंचलाधिकारी को प्राधिकृत करना**—संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल अधिकारी तथा अंचलाधिकारी को इस नियम के अधीन उपबंधित रीति से कार्य करने हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत होंगे।

- (3) **ईट मिट्टी के लिए खनन क्रिया परमिट दिया जाना**— किसी आवेदक द्वारा खनन पदाधिकारी को आवेदन दिए जाने और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति बिहार राज्य प्रदूषण



नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उत्सर्जन सहमति आदेश तथा इस नियमावली की अनुसूची-III'ख' के अनुसार रॉयलिटी की समेकित राशि के साथ साथ इस नियमावली के नियम 34 में यथा विहित अपेक्षित दस्तावेजों को सुपूर्द करने पर वे अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर किसी विनिर्दिष्ट भूमि से किसी विशिष्ट ईट मौसम के लिए किसी ईट भट्टा के संबंध में उत्खनन एवं ईट मिट्टी हटाने के लिए प्रपत्र 'घ' में खनन क्रिया परमिट दे सकेगा।

- (4) **भुगतान का रीति**— ईट भट्टा स्वामी/ईट मिट्टी हटाने वाला राज्य सरकार को अनुसूची-III'ख' के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति भट्टा समेकित राशि का भुगतान नीचे सारणी में विशिष्ट ईट मौसम के लिए दर्शायी गयी तिथि के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के लिए करेगा:-

क्र०	समेकित स्वामिस्व राशि जमा करने की तिथि	भुगतेय राशि
1	30वीं नवम्बर तक	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 95 प्रतिशत्
2	31वीं दिसम्बर तक	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 100 प्रतिशत्
3	31वीं जनवरी तक	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 105 प्रतिशत्
4	28/29 वीं फरवरी तक	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 110 प्रतिशत्
5	31 वीं मार्च तक	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 115 प्रतिशत्
6	30 वीं जून तक	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 150 प्रतिशत्
7.	30 वीं जून के बाद	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 200 प्रतिशत्

- (5) **भुगतान में चूक के लिए कार्रवाई**— यदि ईट मिट्टी हटाने वाला/ ईट भट्टा स्वामी उस विशिष्ट मौसम की इस प्रकार विहित रीति में रॉयलिटी की समेकित राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे व्यवसाय चालू रखने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी उस व्यवसाय को रोक देने हेतु सक्षम होगा।

**स्पष्टीकरण — इस नियम के प्रयोनार्थ —**

- (क) “व्यवसाय” से अभिप्रेत और शामिल है ईट मिट्टी हटाने वाले/ईट भट्टा स्वामी द्वारा ईट बनाना, पकाना और बेचना तथा ऐसा अन्य क्रियाकलाप जो ईट विनिर्माण से सहयुक्त हो।
- (ख) इस नियम के प्रयोजनार्थ ईट मिट्टी हटाने वाले से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है वह व्यक्ति जिसके द्वारा अथवा जिसकी ओर से ईट विनिर्माण के लिए ईट मिट्टी हटाई जाती है।
- (ग) इस नियम के प्रयोजनार्थ भट्टा स्वामी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो ईट भट्टा का स्वामी है अथवा जिसकी ओर से उस भट्टा में ईटों का विनिर्माण किया जाता है और इसमें उस व्यक्ति का प्रबंधक, एजेन्ट और लीज धारक शामिल है।
- (6) **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार से अपेक्षित अनापत्ति समर्पित नहीं करने वाले ईट भट्टों के विरुद्ध कार्रवाई**— यदि ईट मिट्टी हटाने वाला/ईट भट्टा स्वामी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार से अपेक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति और/या बिहार राज्य नियंत्रण बोर्ड से अपेक्षित उत्सर्जन सहमति आदेश समर्पित करने में असफल रहता है तो सक्षम अधिकारी /अनुमंडल अधिकारी/अंचल अधिकारी व्यवसाय रोक देगा और नियमों के उल्लंघन के लिए दंड प्रावधानों को आरंभ करने के लिए मामला पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार/ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

#### अध्याय— IX

#### पट्टा धारित क्षेत्र से बाहर लघु/वृहद खनिजों का भंडारण

39

- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी लीज धारित क्षेत्र से बाहर लघु /वृहद खनिज का व्यवसाय चलाता है, खनन अधिकारी से प्रपत्र—“ट” में भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा जिसे व्यवसाय के सहजदृश्य स्थल पर दर्शाया जाएगा और सभी ऐसे खनिजों क्रय और विक्रय का समुचित लेखा एक रजिस्टर में प्रपत्र “ज” में संधारित किया जाएगा। जिसके निरीक्षण के लिए खान आयुक्त, निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान एवं उपनिदेशक, खान या खनन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष

उपस्थापित किया जाएगा प्रपत्र "ट" में लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ 10,000/- (दस हजार) रुपये की फीस संलग्न की जाएगी।

(क) प्रत्येक ऐसा अनुज्ञप्ति एक कलेन्डर वर्ष के लिए वैध होगा।

(ख) अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन के साथ 2000/- का फीस संलग्न करना होगा।

(2) **उपनियम (1)** यथोल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति प्रपत्र-“छ” में अथवा विहित प्रपत्र में परिवहन चालान प्रत्येक वाहक को अपने स्टॉक से खनिजों को प्रेषित करते समय निर्गत करेगा।

(3) **उपनियम (1)** यथोल्लिखित व्यक्ति यदि प्रपत्र “ज” में एक रजिस्टर संधारित करने अथवा प्रपत्र “ट” में लाईसेन्स प्राप्त करने अथवा प्रपत्र “झ” में अथवा विहित प्रपत्र में चालान निर्गत करने में असफल रहता है वह साधारण कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा खनिज मूल्य के साथ 10,000/- (दस हजार) रु0 तक बढ़ाया जा सकेगा से अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

(4) किसी भी व्यक्ति को पट्टा क्षेत्र के बाहर किसी स्टोन क्रशर लगाने, प्रतिष्ठापित करने या प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परन्तु क्रशर के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर खनिज के लिए धारित विद्यमान भंडारण अनुज्ञप्ति, सभी सुसंगत नियमों/विधि के प्रावधानों/ अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्तों/बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जारी स्थापना हेतु सहमति/संचालनार्थ सहमति में वर्णित शर्तों के पालन करने पर उनके अनुज्ञप्ति अवधि की वैधता तक प्रचालन में रहेगा अन्यथा उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।

परन्तु विभाग लीजधारक को अथवा विभाग द्वारा यथा विनिश्चित शर्तों पर निर्माण क्रियाकलाप में सीधे लगा हुआ व्यक्ति को पट्टा क्षेत्र सीमा के 500 मीटर की परिधि के भीतर मोबाइल क्रशर सहित किसी क्रशर के प्रतिष्ठान की स्वीकृति दे सकेगा।

#### अध्याय-X

##### ई-अपेक्षाएँ।

40. **इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के उपयोग-** खान आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, सभी खनिज समानुदान धारक अथवा किसी अन्य पणधारी से अपनी विवरणी (रिटर्न), विवरण तथा क्रियाकलाप इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने तथा इलेक्ट्रॉनिक रीति से सभी अथवा किसी कार्य की जिम्मेवारी लेने की अपेक्षा कर सकेगा। विभाग के कार्य प्रणाली को ई0 ऑफिस प्रणाली में परिवर्तित किया जायेगा ताकि कागज रहित व्यवस्था सुचारु रूप से लागू हो सके।

41. **ई-चालान।**-(1) लघु खनिजों का संचलन का, चाहे खनिज समानुदान धारक द्वारा हो या निगम द्वारा, अनुश्रवण प्रपत्र-“छ” में अथवा विहित ई-चालान के माध्यम से किया जाएगा।

42. **खनन एम.आई.एस.**-(1) विभाग सभी खनिज समानुदान धारक, निगम, और लघु खनिजों के परिवहन और व्यापार में लगे अन्य व्यक्तियों से, इस नियमावली के उपबंध के अधीन आने तथा विभाग द्वारा विकसित किए गए खनन एम.आई.एस. प्रणाली के अनुसार अपनी गतिविधियाँ की जिम्मेवारी लेने के लिए, अपेक्षा करेगा।

(2) विभाग अपने एम.आई.एस. के लिए विस्तृत मार्गदर्शन अधिकथित करेगा।

#### अध्याय-XI

**खनिजों के संचलन के लिए पारगमन पास/चालान/ ई-चालान दिया जाना।**

43. **परिवहन पर निषेध-** कोई भी व्यक्ति कोई अयस्क/खनिज का निकलने वाले स्थान से किसी साधन द्वारा पट्टा क्षेत्र या खनिजों के एक स्टॉक से अन्य स्थान पर इस नियमावली के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रपत्र-“छ” में या विहित प्रपत्र में वैध पारगमन पास/चालान/ई-चालान अपने पास रखे बिना, परिवहन नहीं करेगा या करवाएगा अथवा ले जाएगा।

44. **खनिजों को ले जाने वाले वाहनों पर निर्बंधन-** राज्य सरकार किसी लघु खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकेगी और उनके कतिपय विनिर्देशनों पर दृढ़ रहने की अपेक्षा कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार परिवहन यानों जी0 पी0एस0 अथवा ऐसी अन्य युक्ति जो आवश्यक अधिष्ठापित करने तथा ऐसे निदेश देने, जिसे उचित समझे, देने की अपेक्षा कर सकेगा।

45. **खनिजों के संचलन विनियमित करने की शक्ति।**- अधिसूचना के माध्यम से विभाग, राज्य से अन्य राज्यों में खनिजों के निर्यात को नियंत्रित कर सकता है। इस क्रम में विभाग चेक पोस्ट, बैरियर धर्मकांटा इत्यादि अधिष्ठापित कर सकेगा।

यदि विभाग का विचार हो कि विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना खनिजों का परिवहन एवं भंडारण के रोकने की दृष्टि से वैसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा राज्य के भीतर

किसी स्थान या स्थानों पर चेक पोस्ट लगाने या बैरियर स्थापित करने अथवा दोनों के लगाने हेतु निदेश करेगा।

46. **रजिस्टर, रिटर्न और साईन बोर्ड।—**

- (1) प्रत्येक खनिज समुदानधारक प्रपत्र “ज” में एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें दिन-प्रतिदिन का संव्यवहार दर्ज किया जाएगा। वह साईन बोर्ड भी प्रदर्शित करेगा।
- (2) प्रत्येक खनिज समानुदान धारक प्रत्येक माह सक्षम अधिकारी को प्रपत्र “झ” में खनिजों के लिए एक सत्य एवं सही रिटर्न जिस माह से वह संबंधित हो उसके अगले माह की 15वीं तिथि तक प्रत्येक समर्पित करेगा।
- (3) प्रत्येक खनिज समानुदान धारक इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र “ञ” में वार्षिक रिटर्न प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में समर्पित करेगा।
- (4) प्रत्येक खनिज समानुदान धारक खनन अधिकारी या खान निदेशक, खान अपर निदेशक या खान उपनिदेशक अथवा समाहर्ता द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को खनिज लेखाओं का निरीक्षण, सत्यापन एवं चेक करने की सभी युक्ति युक्त सुविधाएँ देगा।
- (5) खनिज समानुदान धारक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो खनिजों को हटाया हो, प्रस्तुत किया लेखा, रिटर्न तथा अन्य साक्ष्य यदि किसी प्राधिकृत अधिकारी की राय में पूर्णतः, या अंशतः अशुद्ध, अपूर्ण अथवा अविश्वासनीय हो तो संबंधित अधिकारी खनन अधिकारी को प्रतिवेदित करेगा जो बंदोबस्तधारी से बकाए स्वामिस्व की राशि अपनी सर्वोत्तम विवेक वृद्धि से निर्धारण करने हेतु अग्रसर होगा :  
परन्तु यदि खनन अधिकारी स्वयं अपनी राय बना ली हो बंदोबस्तधारी से बकाए की स्वामिस्व की राशि का निर्धारण अपने सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से करने हेतु तुरंत अग्रसर होगा:
- (6) राज्य सरकार लेखा/रिटर्न या अन्य साक्ष्य के अतिरिक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी यथा—ऐरियल सर्वे/ग्राउन्ड सर्वे या अद्यतन किसी रीति लगाकर प्रासंगिक समानुदान अवधि के दौरान उत्खनित खनिज की वास्तविक मात्रा विनिश्चित करने हेतु निदेश भी दे सकेगी।

*अध्याय—XII*

**खनिज समुदान का रद्दकरण**

47. **खनिज समानुदान स्थगित अथवा रद्द करने की शक्ति—**

- (1) समाहर्ता अपने जिला में किसी खनिज समानुदान धारक का कोई खनन पट्टा रद्द/स्थगित करने के लिए सक्षम होगा।
- (2) समाहर्ता राज्य सरकार द्वारा यथा विहित प्रतिबंधों के अधीन सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी खनिज समानुदान को स्थगित अथवा रद्द कर सकेगा और उनकी प्रतिभूति जमा/अग्रधन जमा राशि जप्त कर सकेगा:—
  - (क) यदि खनिज समानुदान प्राप्त करने के लिए गलत दस्तावेज समर्पित किया जाता है, अथवा
  - (ख) यदि खनिज समानुदान अंतरित या उप पट्टा किया जाता है अथवा उसके धारक द्वारा शिकमी दिया जाता है; अथवा
  - (ग) यदि उसके धारक द्वारा देय खनन राजस्व का सम्यक् रूप से भुगतान नहीं किया जाता है; अथवा
  - (घ) ऐसे पट्टाधारी अथवा उसके अभिव्यक्त अथवा विवक्षित अनुमति से उसके सेवक अथवा अभिकर्ता अथवा उसकी ओर से कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे खनिज समानुदान, के किसी निबंधन और शर्तों को भंग करने की दशा में;
  - (ङ.) यदि खनिज समानुदान धारक अथवा उसका अभिकर्ता अथवा कर्मचारी अधिनियम अथवा इस नियमावली अथवा खनन विषयों अथवा खनन राजस्व से संबंधित विषयों से जुड़े और सुसंगत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय अपराध अथवा किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन किसी संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध में सिद्धदोष हो;
  - (च) जिस उद्देश्य के लिए खनिज समानुदान स्वीकृत किया गया था वह यदि अस्तित्वहीन हो जाय;
  - (छ) यदि दुर्यपदेशन अथवा कपट से खनिज समानुदान प्राप्त किया गया हो।
  - (ज) यदि खनिज समानुदान धारक इस नियमावली में उल्लिखित किसी शर्तों का उल्लंघन किया हो।
  - (झ) यदि कोई खनिज समानुदान धारक पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असफल रहता है या उसमें उल्लिखित किसी शर्त का अतिक्रमण करता है।
  - (ञ) यदि खनिज समानुदान धारक खनन प्रचालन, करार हस्ताक्षर करने के तिथि से

तीन माह के भीतर, आरंभ करने में असफल रहता है;

(ट) यदि, किसी अन्य कारण से समाहर्ता का प्रथमदृष्टया यह समाधान हो जाये कि खनिज समानुदान रद्द किए जाने के योग्य है।

- (3) उपनियम (1) के अधीन की गई किसी कार्यवाई के लिए, खनिज समानुदान धारक किसी क्षतिपूर्ति या वापसी जो कुछ भी हो, का पात्र नहीं होगा।
  - (4) ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम, इस नियमावली और खनन पट्टा के किसी अन्य शर्त के किसी प्रकार के उल्लंघन का पता लगने की स्थिति में, राज्य सरकार या समाहर्ता उक्त खनन पट्टा को रद्द करने के अलावा उपयुक्त वित्तीय शास्तियाँ और/या आपराधिक अभियोजन भी अधिरोपित कर सकेंगे।
  - (5) ऐसी कोई भी शास्ति का उद्ग्रहण लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (अधिनियम 4/1914) के अधीन वसूलनीय होगा।
48. **प्रबंधन ग्रहण करने की समाहर्ता की शक्ति**— यदि कोई खनिज समानुदान धारक अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी नियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या उसपर अधिरोपित किसी शर्त का अनुपालन करने में चूकता है या इस नियमावली के अधीन समाहर्ता द्वारा निर्गत ऐसे युक्तियुक्त निदेशों का पालन करने से इंकार किए जाने पर या खनन पट्टा—अवधि की समाप्ति या वापसी होने पर, समाहर्ता, किसी भी समय, ऐसे खनन पट्टा या विशेषाधिकार रद्द करते हुए या उसके रद्दकरण के बिना —
- (1) उस स्थापना के स्वामी की हानि और जोखिम पर ऐसे खनन कार्यों का प्रबंधन ग्रहण कर सकेगा; या
  - (2) उस स्थापना के स्वामी की हानि और जोखिम पर ऐसे स्थापना का प्रबंधन ग्रहण कर सकेगा; या
  - (3) खनन पट्टा या विशेषाधिकार की अनवसित अवधि के लिए उस स्थापना को, उसके स्वामी की हानि और जोखिम पर, किसी अन्य व्यक्ति या निगम को अंतरित कर सकेगा।
49. **लघु खनिज अधिग्रहण करने की समाहर्ता की शक्ति**—ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, किसी प्राकृतिक आपदा या भारी कमी या ऐसी अन्य आकस्मिकताओं की स्थिति में अथवा बफरस्टॉक बनाए रखने के लिए समाहर्ता खनिज समानुदान धारक से लघु खनिज की एक विनिर्दिष्ट मात्रा का उत्पादन अथवा उत्खनन करने एवं ऐसे स्थान एवं ऐसे दर पर वितरण करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।
50. **खनिज समानुदान धारक द्वारा कारोबार छोड़ने का विकल्प**—
- (1) कोई खनिज समानुदान धारक यथास्थिति, खनन पट्टा अवधि के किसी भी समय समाहर्ता को छः महीने का नोटिस देते हुए कारोबार छोड़ने का विकल्प दे सकेगा। फिर भी, यह विकल्प वैसे खनिज समानुदान धारक के लिए नहीं है जिन्होंने अपनी बोली की रकम या बंदोबस्ती की रकम का भुगतान नहीं किया है अथवा खनन पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन किया है।
  - (2) समाहर्ता ऐसे खनिज समानुदान धारक को कारोबार छोड़ने की अनुमति दे सकेगा और यथा वसूलनीय ऐसे किसी बकायों की कटौती कर खनिज समानुदान धारक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि वापस कर सकेगा।
  - (3) समाहर्ता, तदनंतर, यथास्थिति एक नई बिडिंग के लिए व्यवस्था की शुरुआत करेगा।
  - (4) धोखाधड़ी या खनन अथवा पर्यावरणीय शर्तों के उल्लंघन या प्रतिवेदित की गई किसी अन्य अनियमितताओं की स्थिति में, कारोबार छोड़ने का कोई विकल्प खनिज समानुदान धारक को उपलब्ध नहीं रहेगा और उनकी प्रतिभूति जमा जप्त हो जाएगी।

### अध्याय—XIII

#### खनन राजस्व

#### 51. लगान/रॉयलिटी तथा निर्धारण—

- (1) जब खनिज समानुदान दिया अथवा नवीकृत किया जाएगा :—
  - (क) अनुसूची—II विनिर्दिष्ट दरों पर नियत लगान प्रभारित किया जाएगा;
  - (ख) अनुसूची—III 'क' में विनिर्दिष्ट दरों पर स्वामिस्व प्रभारित की जाएगी; तथा
  - (ग) पट्टाधारी द्वारा अधिभोग या उपयोग में लाए गए क्षेत्र समाहर्ता द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट दर पर सतह—लगान प्रभारित किया जाएगा।
- (2) इस नियमावली के आरंभ की तिथि को एवं से उपनियम (1) के प्रावधान ऐसे आरंभ की तिथि के पूर्व दिए गए अथवा नवीकृत किए गए और इस तिथि की कायम पट्टों पर भी लागू होंगे।
- (3) यदि खनिज समानुदान धारक इसी क्षेत्र में एक खनिज से अधिक खनिज का कार्य करने

की अनुज्ञा देता है तो समाहर्ता प्रत्येक खनिज के संबंध में पृथक नियत लगान को परिवर्तित कर सकेगा।

परन्तु लीजधारी प्रत्येक खनिज के संबंध में नियत लगान अथवा रॉयलिटी, जो उच्चतर राशि हो, का भुगतान करने का दायी होगा।

- (4) पट्टा के किसी लिखित में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खनिज समानुदान धारक अनुसूची-II और अनुसूची-IIIक में समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर पर लिए गए/निकाले अथवा हटाये गये किसी लघु खनिज के संबंध में लगान/रॉयलिटी का भुगतान करेगा।
- (5) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस दर में बढ़ोत्तरी या कमी के संबंध में अनुसूची II, IIIक एवं IIIख का संशोधन कर सकेगी ताकि जिस पर लगान /रॉयलिटी, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से किसी लघु खनिज के संबंध में भुगतेय होगी।
- (6) खनन अधिकारी, ऐसी जाँच पड़ताल तथा सत्यापन के बाद जिसे वह लीजधारी द्वारा प्रपत्र "झ" में मासिक रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक समझे। वार्षिक रिटर्न प्रपत्र "ज" में लीजधारी द्वारा विहित अवधि के अंत में भुगतेय लगान /रॉयलिटी की राशि निर्धारित करेगा।
- (7) इस नियमावली में ये अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लघु खनिजों की नीलामी की दशा में रॉयलिटी नीलामी की राशि होगी। जहाँ रॉयलिटी प्रेषित मात्रा पर नीलामी राशि से अधिक हो वहाँ निकाले गए खनिजों की अधिक मात्रा के लिए अतिरिक्त रॉयलिटी भी भुगतेय होगी।
- (8) खनिज समानुदान धारक समय-समय पर राज्य सरकार के प्राधिकारी द्वारा आंकलित, अधिरोपित तथा सभी लोक मॉगों का भी भुगतान करेंगे।

52. **एकल बैंक खाता—**

- (1) सभी खनिज समानुदान धारक आवश्यक रूप से उक्त पट्टे या संचलन अनुज्ञापत्र से संबंधित अपने सभी प्रचालन के लिए केवल एकल बैंक खाता प्रचलित करेंगे।
  - (2) खनिज समानुदान धारक आवश्यक रूप से उक्त बैंक खाते की जानकारी समाहर्ता, जिले के खनन पदाधिकारी, खान निदेशक तथा खान आयुक्त को देंगे।
  - (3) कोई व्यक्ति, जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, अभियोजित किया जायेगा।
53. **बैंक खाता फ्रिज करने की शक्ति—** जहाँ समाहर्ता को खनन अधिकारी के प्रतिवेदन पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी खनिज समानुदान धारक के बैंक खाता को सरकारी राजस्व की सुरक्षा करने अथवा अभियोजन की सहायता करने के लिए फ्रिज करना है तो वह तुरंत संबंधित बैंक को अगले आदेश तक उस बंदोबस्तधारी/अनुज्ञापिधारी के बैंक खाता को फ्रिज करने हेतु निदेश देते हुए आदेश करेगा।

54. **कैसे शुल्क तथा पेशगी जमा की जाएगी—** इस नियमावली के अधीन भुगतेय कोई राशि कोषागार में कागजी चालान अथवा इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण के माध्यम से संदत्त की जाएगी।

55. सरकार अधिनियम अथवा इस नियमावली के किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी लगान स्वामिस्व अथवा फीस या सरकार की बकाया राशि पर वार्षिक 24 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्रभारित कर सकेगी।

**अध्याय-XIV**

**अपराध और शास्तियाँ।**

56. **लघु खनिजों के अप्राधिकृत निष्कासन एवं हटाये जाने के लिए शास्ति—**

- (1) जो कोई भी लघु खनिजों को निष्कासित या हटाते हुए पाया जाता है अथवा जिसकी ओर से ऐसा निष्कासन या हटाया जाता है जो इस नियमावली के प्रतिकूल हो चाहे वह एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी, ठीकेदार या उप पट्टाधारी हो, लघु खनिज के अविधिपूर्ण हटाये जाने का पक्षकार माना जाएगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति साधारण कारावास से जिसे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा जुर्माने से जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।
- (2) कोई भी वाहन का प्रभारी कोई व्यक्ति खनिज ले जाते समय यदि प्रपत्र 'छ' में या विहित प्रपत्र में चालान प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसे चालान का निरीक्षण, निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान, उपनिदेशक, खान या खनन अधिकारी या खान निरीक्षक या समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा करने से इन्कार करता है तो वह अधिकारी वाहन के प्रभारी व्यक्ति से जुर्माने के साथ, जिसे दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, खनिज का मूल्य वसूल कर सकेगा।

**प्रपत्र-छ** में वैध चालान के बिना खनिज के परिवहन की दशा में खनिज के कुल मूल्य और जुर्माना, जिसे दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, वाहन के प्रभारी व्यक्ति से वसूला जाएगा और सरकारी शीर्ष में जमा किया जा सकेगा। शास्त्रों के संग्रहण और जमा की रीति एवं औपचारिकताएँ विभाग द्वारा, समय-समय पर विनिश्चित की जाएगी :

परन्तु जब वाहन में लदा हुआ खनिज की मात्रा चालान में उल्लेखित मात्रा से भिन्न हो तो प्राधिकृत अधिकारी उस जुर्माने के साथ, जिसे दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा केवल अंतर की मात्रा के लिए खनिज के मूल्य की वसूली कर सकेगा। मूल्यांकन की गई मात्रा का निर्धारण केवल नेत्रानुमान से न कर धर्मकाँटा से किया जायेगा।

अधिरोपित दण्ड की राशि के संग्रहण/जमा करने हेतु विभाग द्वारा मनी रसीद संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को निर्गत किया जायेगा जो दण्ड की राशि मनी रसीद के माध्यम से प्राप्त कर सरकारी कोष में जमा करेंगे।

- (3) जो कोई भी वैध लीज/परमिट के बिना लघु खनिज हटाता है अथवा जिसकी ओर से इस नियमावली के विरुद्ध ऐसा हटाया जाता है वह ऐजेंट, प्रबंधक ठीकेदार, उपपट्टाधारी लघु खनिज का अविधिमान्य हटाए जाने का पक्षकार होना और उसका मूल्य चुकाने का दायी होगा और सरकार उस व्यक्ति से उस अवधि के लिए जिसके दौरान भूमि इस व्यक्ति के अधिभोग किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना इस नियमावली या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे विरुद्ध की जानेवाली अन्य कार्रवाई के प्रतिकूल के बिना यथा स्थिति, लगान, स्वामिस्व अथवा कर की वसूली कर सकेगी।
57. **सरकारी परियोजनाओं मालिकाना फीस-**
- (1) सभी सरकारी विभाग, विशेषकर अपनी स्कीम या परियोजनाओं के लिए किसी लघु खनिज का उपयोग करने हेतु मालिकाना फीस की कटौती अपने आपूर्तिकर्ता या संवदेक से करेंगे।
  - (2) ऐसी मालिकाना फीस की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10(दस) प्रतिशत फ्लैट दर पर कार्य विभागों द्वारा अपने आपूर्तिकर्ता/ कार्य ठीकेदारों से की जाएगी और जिले के खनन अधिकारी के पास जमा की जाएगी।
- राज्य सरकार, समय-समय पर मालिकाना फीस में बढ़ोतरी या कमी कर सकेगी।
58. **लघु खनिजों का विक्रय मूल्य-** अंतिम उपभोक्ता या जनता के लिए खनिजों का विक्रय मूल्य बाजार बल द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

#### अध्याय-XV

##### अपराधों की पहचान, अनुसंधान तथा विचारण।

59. **प्रवेश निरीक्षण तलाशी लेने तथा जप्त करने की शक्ति-**
- (1) किसी खदान अथवा परित्यक्त खदान के संभावित स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से अथवा इस नियमावली से संबंधित अन्य उद्देश्य से काम करने की स्थिति निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई यथा-
    - (क) खान आयुक्त, खान निदेशक; या
    - (ख) समाहर्ता या समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी,
    - (ग) अपर निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, खनिज विकास पदाधिकारी और खान निरीक्षक निम्नलिखित कर सकेगा :-
      - (i) किसी खदान में प्रवेश और निरीक्षण;
      - (ii) किसी ऐसे खदान का सर्वे और माप करना ;
      - (iii) किसी खदान में उपलब्ध खनिज स्टॉक का वजन माप करना या माप लेना;
      - (iv) किसी खदान एवं स्थान उसपर पहचान चिन्ह से संबंधित या के नियंत्रण वाले किसी व्यक्ति के कब्जे वाले किसी दस्तावेज, पुस्त या रजिस्टर या अभिलेख की जाँच करना तथा उस दस्तावेज, पुस्त, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण लेना एवं उसकी प्रतियाँ तैयार करना;
      - (v) खंड (iv) में यथा निर्देशित किसी ऐसे दस्तावेज, पुस्त या रजिस्टर के उपस्थापन का आदेश देना ;

- (vi) किसी खदान पर नियंत्रण रखने वाले या से संबंधित किसी व्यक्ति की जाँच करना ;
- (vii) किसी दस्तावेज, नमूना, उपकरण, सवारी, जानवर, सामान, लघु खनिज सामग्री, कच्चे माल या संबंधित किसी अन्य वस्तुओं को जब्त करना।
- (2) ऐसी तलाशी और जब्ती की दशा में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के प्रावधान लागू होंगे।
60. **किसी वाहक, परिवहन या पात्र को रोकने और उसकी जाँच करने की शक्ति—**
- (1) नियम 59 में उल्लेखित पदाधिकारी लघु खनिज से लदे हुए ले जाने वाले वाहन को जाँच करने के लिए रोक सकेगा।
- (2) यदि पदाधिकारी प्रथम दृष्टया में पाता है कि वाहन का भार अनुमत मात्रा और/या परिवहन चालान में निर्धारित मात्रा के अनुरूप नहीं पाता है तो वह निकटतम धर्मकोटा से वनज करा सकेगा एवं इसका खर्च ड्राईवर अथवा मालिक द्वारा वहन किया जाएगा।
- (3) यदि कोई व्यक्ति खनिज पदाधिकारी की विधिसंगत समादेश का पालन करने से इंकार करता है, तो उसे इस नियमावली के अधीन अभियोजित किया जायेगा।
61. **लिखित शिकायत पर संज्ञेय अपराध—** प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से अन्याय को कोई न्यायालय इस नियमावली के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा और कोई न्यायालय सक्षम अधिकारी या उप निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान, निदेशक, खान अथवा सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप में की गई लिखित शिकायत के सिवाय इस नियमावली के अधीन किसी अपराध को संज्ञान नहीं लेगा।
62. **अपराध का शमन—** सक्षम अधिकारी, समाहर्ता के अनुमोदन से किसी व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी मामले का उसके निदेशन पर यदि शिकायत संस्थित की गई हो और उस राशि के सरकारी खाते में भुगतान पर, जो अपराध के लिए भुगतेय विनिश्चित की जाय, शमन कर सकेगा।  
परंतु जहाँ कोई मामला उप निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान, निदेशक, खान अथवा सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा संस्थित किया गया हो वहाँ वह आयुक्त के अनुमोदन से, किसी व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी मामले को शमन कर सकेगा।
63. **गिरफ्तारियों, जब्तियों और तलाशियों के प्रतिवेदन—** प्रत्येक खनिज पदाधिकारी कोई गिरफ्तारी, तलाशी या जब्ती करने पर इसका प्रतिवेदन चौबीस घंटे के अन्दर समाहर्ता को एक प्रतिवेदन सौंपेगा।
64. **विशेष न्यायालय—**
- (1) अधिनियम की धारा 30 ख के अधीन प्रदत्त शक्ति के निबंधनों के अनुसार, राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन सभी या किसी अपराधों के विचारण के प्रयोजनों के लिए यदि जनहित में आवश्यक समझती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिला में विशेष न्यायालय या तो नियुक्त या अभिहित कर सकेगी।
- (2) विशेष न्यायालय विशेष न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली होगी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम 2) के अधीन सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश हों या रहे हों।
- (3) विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध के इस अधिनियम के अधीन विचारण का किसी अन्य न्यायालय (जो विशेष न्यायालय न हो) में अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर अग्रता होगी और ऐसे अन्य मामलों के विचारण को अधिमानता में तय की जायेगी।
65. **मामलों को नियमित न्यायालयों में अंतरित करने की शक्ति—** जहाँ इस नियमावली के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात कोई विशेष न्यायालय यह समझता है कि इस अपराध का विचारण इस न्यायालय में करने योग्य नहीं है, तो वह इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अपराध का विचारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय के पास नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम 2) के अधीन क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय के पास मामला अंतरित कर सकेगा और जिस न्यायालय के पास मामला अंतरित किया गया है वह अपराध के विचारण को इस प्रकार आगे बढ़ाएगा मानो इस अपराध का संज्ञान उसी ने लिया हो।
66. **अपील—** कोई भी व्यक्ति, जो विशेष न्यायालय के किसी आदेश से व्यथित है तो वह आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

## अध्याय—XVI

## अपील और पुनरीक्षण।

## 67. अपील—

- (1) खनन अधिकारी द्वारा पारित सभी अंतिम आदेश, आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर समाहर्ता के समक्ष अपीलीय होंगे।
- (2) समाहर्ता द्वारा पारित सभी अंतिम आदेश, आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर खान आयुक्त के समक्ष अपीलीय होंगे।
- (3) सभी अपील दाखिल किये जाने की तिथि से तीन माह के भीतर निपटाए जाएंगे। उस नियम में सभी अपील प्रपत्र 'ठ' में होंगे।

## 68. पुनरीक्षण—

- (1) खान आयुक्त किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से और यदि इस नियमावली के अधीन समाहर्ता द्वारा पारित किसी आदेश से व्यक्ति आदेश के संसूचन की तिथि से 60 दिनों के भीतर और उस तिथि से 75 दिनों के भीतर जिस तिथि को कोई आवेदन समाहर्ता द्वारा नामंजूर किया गया समझा जाता है, यदि वैसे नामंजूरी की कोई संसूचना नहीं दी जाती है, कोई आवेदन दाखिल करता है, आदेश के पुनरीक्षण के लिए कार्यवाही आरंभ कर देंगे :

परन्तु पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन यथा उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय के बाद भी ग्रहण किया जा सकेगा यदि आवेदक खान आयुक्त का यह समाधान कर देता है कि उसके पास समय पर आवेदन नहीं दाखिल करने का पर्याप्त कारण था।

- (2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन और उसकी प्रतियाँ प्राप्त होने पर, खान आयुक्त आवेदन की एक प्रति और उपनियम (1) के अधीन स्वप्रेरणा से उसके द्वारा कार्यवाही आरंभ की गई हो वहाँ वह कार्यवाही आरंभ करने तथा उसके कारण की सूचना, पक्षकार बनाए गए प्रत्येक पक्षकार को वह तिथि विनिर्दिष्ट करते हुए यदि कोई हो, पुनरीक्षण आवेदन के विरुद्ध दे सकेगा, भेज देंगे।
- (3) उपनियम (2) के निदेशित अभिलेखों पर विचार करने के बाद खान आयुक्त उस आदेश को संपुष्ट (संशोधित) या खारिज कर सकेगा अथवा उसके संबंध में ऐसा अन्य आदेश, खान आयुक्त उपयुक्त एवं उचित समझें, पारित कर सकेंगे और उनका आदेश अंतिम होगा।
- (4) पुनरीक्षण के लिए किसी आवेदन के अंतिम निपटारे के लंबित रहते हुए खान आयुक्त, पर्याप्त कारणों से, उस आदेश का निष्पादन को स्थगित कर सकेंगे जिसके विरुद्ध कोई पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया हो।

## अध्याय—XVII

## प्रवर्तन।

69. राज्य स्तरीय खनन कार्यबल— (1) एक राज्य स्तरीय खनन कार्यबल निम्नवत् गठित किया जाएगा : —

(क)	मुख्य सचिव	—	अध्यक्ष
(ख)	विकास आयुक्त	—	सदस्य
(ग)	प्रधान सचिव, गृह	—	सदस्य
(घ)	पुलिस महानिदेशक	—	सदस्य
(ङ.)	प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन	—	सदस्य
(च)	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार	—	सदस्य
(छ)	प्रधान सचिव, उद्योग	—	सदस्य
(ज)	प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग	—	सदस्य
(झ)	प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग	—	सदस्य
(ञ)	प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	—	सदस्य
(ट)	प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	—	सदस्य
(ठ)	प्रधान सचिव, वाणिज्य—कर विभाग	—	सदस्य
(ड)	अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्	—	सदस्य
(ढ)	प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	—	सदस्य
(ण)	निदेशक, खान	—	सदस्य—सचिव।

- (2) मुख्य सचिव किसी अन्य अधिकारी या विशेषज्ञ को उपस्थित होने तथा राज्य स्तरीय खनन कार्य बल की बैठक में भाग लेने और योगदान करने हेतु सहयुक्त या आमंत्रित कर सकेंगे। आधे सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।



70. **संवीक्षा समिति**— राज्य स्तरीय खनन कार्यबल, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में, इन सदस्यों के साथ, जैसा वह उचित समझे, एक संवीक्षा समिति गठित करेगा। संवीक्षा समिति राज्य स्तरीय खनन कार्यबल के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
71. **राज्य स्तरीय खनन कार्यबल के कृत्य**— राज्य स्तरीय खनन कार्य बल इस नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा और राज्य में लघु खनिजों के उत्खनन, व्यापार तथा उपलब्धता की संवीक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित भी करेगा —
- (1) अधिनियम तथा इन नियमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन का उपबंध करेगा।
  - (2) इन नियमों को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक नीतियों एवं मार्गदर्शनों का निर्माण करेगा।
  - (3) ऐसी कार्रवाई का जिम्मा लेने हेतु किसी अन्य विभाग निदेश जारी करेगा जो अधिनियम तथा इस नियमावली के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक हो।
  - (4) यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिकथित पर्यावरणीय रक्षोपत्तियों के अनुसार खनन क्रियाकलाप चलाया जा रहा है।
72. **प्रमंडल स्तरीय खनन कार्यबल**— (1) प्रमंडल स्तरीय खनन कार्यबल निम्नवत् गठित किया जायेगा :—
- |      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
| (क)  | प्रमंडलीय आयुक्त                         | — | अध्यक्ष     |
| (ख)  | सीमावर्ती प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्त  | — | सदस्य       |
| (ग)  | प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक             | — | सदस्य       |
| (घ)  | सीमावर्ती प्रमंडलों के पुलिस महानिरीक्षक | — | सदस्य       |
| (ङ.) | वन संरक्षक                               | — | सदस्य       |
| (च)  | प्रमंडल के सभी समाहर्ता                  | — | सदस्य       |
| (छ)  | प्रमंडल के सभी पुलिस अधीक्षक             | — | सदस्य       |
| (ज)  | प्रमंडल के सभी जिला वन अधिकारी           | — | सदस्य       |
| (झ)  | प्रमंडल के सभी खनन पदाधिकारी             | — | सदस्य       |
| (ञ)  | प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव                 | — | सदस्य—सचिव। |
- (2) प्रमंडलीय आयुक्त ऐसे सदस्यों को, जैसा उचित समझे, अतिरिक्त रूप से सह—युक्त कर सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त ऐसे जिलों के समाहर्ताओं एवं पुलिस अधीक्षकों को भी जिनकी सीमाएँ प्रमंडल के साथ हैं, आमंत्रित कर सकेंगे।
  - (3) आधे सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।
  - (4) यह माह में एक बार बैठक करेगी।
73. **प्रमंडल स्तरीय खनन कार्यबल के कृत्य**— प्रमंडल स्तरीय खनन कार्यबल इन नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा और प्रमंडल लघु खनिजों के उत्खनन, व्यापार तथा उपलब्धता की संवीक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त यह निम्नलिखित भी करेगा:—
- (1) प्रमंडल के जिलों एवं प्रमंडल के सीमावर्ती जिलों के बीच अंतर्जिला समन्वय सुनिश्चित करेगा।
  - (2) प्रमंडल के भीतर और बाहर के जिलों के आर—पार लघु खनिजों के अवैध खनन एवं अवैध परिवहन को रोकने हेतु समन्वित कार्य—योजना तैयार करना और प्रारंभ करना।
74. **जिला स्तरीय खनन कार्यबल**— (1) जिला स्तरीय खनन कार्यबल निम्नवत् गठित किया जायेगा:—
- |      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
| (क)  | समाहर्ता  | — | अध्यक्ष     |
| (ख)  | पुलिस अधीक्षक   | — | सदस्य       |
| (ग)  | सभी अनुमंडलीय अधिकारी   | — | सदस्य       |
| (घ)  | सभी अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी   | — | सदस्य       |
| (ङ.) | प्रमंडलीय वन अधिकारी  | — | सदस्य       |
| (च)  | पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता | — | सदस्य       |
| (छ)  | जिला परिवहन अधिकारी   | — | सदस्य       |
| (ज)  | जिला खनन पदाधिकारी  | — | सदस्य—सचिव। |
- (2) समाहर्ता जिला स्तरीय खनन कार्यालय की बैठक में उपस्थित होने और योगदान करने हेतु किसी अन्य अधिकारी या विशेषज्ञ को सह—युक्त कर सकेंगे।
  - (3) आधे सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।
  - (4) यह बैठक निश्चित रूप से माह में एक बार या विभाग द्वारा निदेशित पूर्व क्रम (frequency) पर होगी।

75. **जिला स्तरीय खनन कार्यबल के कृत्य-** जिला स्तरीय खनन कार्य बल इन नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा और जिले में लघु खनिजों के उत्खनन, व्यापार तथा उपलब्धता की संवीक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित भी करेगा:-
- (1) यह सुनिश्चित करना कि खनन पट्टे की शर्तों के अनुसार सभी खनन क्रिया-कलाप किया जा रहा है।
  - (2) यह सुनिश्चित करना कि लघु खनिजों का कोई अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओभरलोडिंग, जमाखोरी तथा काला बाजारी नहीं किया जा रहा है।
  - (3) लघु खनिजों का सभी फुटकर कारबार इन नियमों के अनुसार किया जा रहा है।
  - (4) दूसरे विभागों को यह निदेश जारी कर सकेगा कि वे नियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे कदम उठाये जो आवश्यक हों।
  - (5) यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिकथित पर्यावरणीय रक्षोपाय के अनुसार खनन क्रियाकलाप चलाया जा रहा है।

### अध्याय-XVIII

#### छूट

76. **इस नियमावली के उपबंधों से लघु खनिजों को छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति-** राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा या तो पूरे राज्य में या राज्य के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, किसी विनिर्दिष्ट अवधि या अवसर के लिए या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के लिए और ऐसे प्रयोजनों के लिए, किसी लघु खनिज को पूर्णतः या अंशतः और वैसे शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन, जिसे विहित करना उचित समझे इस नियमावली के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकेगी।
77. **इस नियमावली के किसी उपबंध के प्रवर्तन को शिथिल करने की सरकार की शक्ति-**
- (1) राज्य सरकार इस नियमावली के एक या अनेक उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल कर सकेगी यदि सरकार के विचार से ऐसी शिथिलता लोक हित में आवश्यक हो।
  - (2) इस नियमावली में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, राज्य सरकार ऐसे मामले में, जिसमें सरकार लोक हित में उचित समझती है तो, खनन पट्टा/खनन बंदोबस्ती की मंजूरी दे सकेगी, और लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से, इस नियमावली में विहित शर्तों एवं निबंधनों से भिन्न शर्तों एवं निबंधनों पर किसी को उत्खनन अनुज्ञापत्र / संचलन अनुज्ञापत्र की मंजूरी को प्राधिकृत कर सकेगी:  
परन्तु राज्य सरकार इस नियमावली में विहित शर्तों एवं निबंधनों से भिन्न शर्तों एवं निबंधनों पर किसी सरकारी विभाग अथवा राज्य स्वामित्व वाले निगम को अपने क्षेत्राधिकार के अधीन किसी इलाके में खनन पट्टा/बंदोबस्ती की मंजूरी दे सकेगी।
78. **किसी कार्य विभाग को खनन पट्टा आदि-**
- (1) इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी कार्य विभाग को, जिलों के विनिर्दिष्ट संख्या में किसी विशिष्ट योजना के लिये विनिर्दिष्ट समयावधि के लिये अनुज्ञप्ति/पट्टा मंजूर कर सकेगी।
  - (2) उक्त कार्य विभाग को बकाया स्वामित्व तथा ऐसी अन्य फीस, जो इस नियमावली के अधीन लागू हो, देनी होगी।

### अध्याय-XIX

#### विविध।

79. **प्रत्यक्ष गलतियों का सुधार करने की शक्ति-** इस नियमावली के अधीन सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकार अथवा इस नियम के अन्तर्गत पदाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में पाई गई किसी लिपिकीय अथवा गणितीय गलती और आकस्मिक भूल-चूक या लोप के कारण उसमें उत्पन्न किसी भूल का सुधार आदेश की तिथि से दो साल के अन्दर राज्य सरकार के प्राधिकार या अधिकारी यथा स्थिति कर सकेंगे;  
परन्तु किसी व्यक्ति के प्रतिकूल कोई आदेश तब तक नहीं पारित किया जाएगा जब तक कि उसे अपना मामला अधिकथित करने का अवसर न दे दिया गया हो।
80. **पट्टा की प्रति प्रस्तुत करना-** इस नियमावली के आरंभ के पूर्व से किसी प्राईवेट व्यक्ति से खनन पट्टा अथवा उप पट्टा धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस खनन अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में उस पट्टा या उप पट्टा द्वारा आच्छादित क्षेत्र या क्षेत्र अवस्थित हो या ना हो, पट्टा या उप पट्टा की सत्यापित या सच्ची प्रति समर्पित करेगा।
81. **खनन पट्टा का निर्वचन-** प्रत्येक लीज, लीज से संबंधित लीजधारी द्वारा विवाद के किसी प्रश्न अथवा किसी अन्य विषय या चीज/लीज में निर्माण के निर्बंधन और शर्त अथवा लीज में विनिर्दिष्ट

लघु खनिजों के खनन से संबंधित कोई बात अथवा खान या खनन क्रिया का सक्रियता अथवा असक्रियता तथा रॉयलिटी या नियत लगान या खनन अधिकारी को भुगतान की उसकी रीति का समाहर्ता के विनिश्चय के लिए प्रावधान करेगी जो अंतिम होगा और लीजधारी पर आबद्धकर होगा।

82. **इस नियमावली के अधीन भुगतान, रॉयलिटी तथा शस्ति की वसूली की रीति—**लगान रॉयलिटी या शास्ति बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन लोक मांग के रूप में वसूलनीय होगी।

83. **सतह अधिकार आदि के स्वामी को प्रतिकर का भुगतान—**

- (1) लघु खनिज धारक जिस भूमि पर खनिज समुदान धारित करता है इस भूमि के सतह के अधिभोगी को वह प्रतिकर भुगतान करने का दायी होगा जो समाहर्ता द्वारा विनिश्चित किया जाय।
- (2) कृषि भूमि के मामले में वार्षिक कर की राशि पूर्ववर्ती 03 वर्षों के लिए समकक्ष भूमि की खेती के लिए औसत वार्षिक वास्तविक आय के आधार पर निकाली जाएगी।
- (3) गैर कृषि भूमि के मामले, वार्षिक प्रतिकर की राशि पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए समकक्ष भूमि के औसत वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर निकाली जाएगी।
- (4) उपनियम (1) में निर्देशित वार्षिक प्रतिकर का भुगतान उस तिथि के पूर्व किया जाएगा जो समाहर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

84. **निदेश जारी की शक्ति—**

- (1) विभाग, खनिज जमा, के सुव्यवस्थित विकास के हित में खनिजों के संरक्षण, वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण के सतत विकास और सुरक्षा के लिए खनन लीज/बंदोबस्ती के स्वामी, ऐजेन्ट या प्रबंधक को निदेश जारी कर सकेगा।
- (2) उपनियम(1) के अधीन जारी प्रत्येक निदेश का पालन यथास्थित, खनन लीज/बंदोबस्ती के स्वामी, ऐजेन्ट या प्रबंधक द्वारा किया जाएगा, जो ऐसे निदेश प्रभावी करने में किसी कठिनाई की दशा में ऐसे निदेश के उपांतरण अथवा विखंडन के लिए आवेदन कर सकेगा और इस संबंध में विभाग द्वारा वैसा प्राधिकृत अधिकारी या तो उस निदेश उपांतरित अथवा विखंडित कर सकेगा अथवा उसे संपुष्ट कर सकेगा।

85. **पदाधिकारियों का लोक सेवक होना—**

- (1) अधिनियम अथवा इस नियमावली के अधीन किसी शक्ति का उपयोग करने या किन्हीं कार्यों को करने में सक्षम सभी पदाधिकारी और व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45) की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।
- (2) इस अधिनियम या इस नियमावली या खनन राजस्व से संबंधित तात्कालिक रूप से लागू किसी अन्य कानून के अनुपालन में सद्भावपूर्वक किये गये किसी कार्य या करने हेतु दिये गये आदेश के लिए राज्य सरकार या किसी खनन पदाधिकारी के विरुद्ध क्षति के लिए किसी सिविल न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं होगी।
- (3) इस नियमावली के अनुसरण में कुछ करने या किये जाने के आरोप के संबंध में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी वाद पर कोई सिविल न्यायालय विचारण नहीं करेगा, और पूर्व अनुशास्ति को छोड़कर, कोई दण्डाधिकारी किसी खनन पदाधिकारी के विरुद्ध इस नियमावली के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गये किसी आरोप का संज्ञान नहीं लेगा।

86. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण—**किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस नियमावली के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए नहीं होगी।

87. **आदेशों का लागू रहना—**बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972, (समय-समय पर यथा संशोधित) बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण निवारण) नियमावली, 2003, बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 या खान आयुक्त, समाहर्ता, राजस्व पर्षद या खनन के मामलों से संबंधित उन नियमावलियों और जो उनकी समाप्ति के तत्काल पूर्व लागू थीं के अधीन नियुक्त किसी अन्य खनन पदाधिकारी के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश अधिसूचना, नियम या विनियम, जहाँ तक ऐसे आदेश या अधिसूचना या नियम या विनियम अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हों, अविराम लागू और अधिनियम तथा इस नियमावली के अधीन निर्मित समझे जाएंगे।

88. **निरसन और व्यावृत्तियाँ—**

- (1) बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972, बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 और बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 एतद् द्वारा निरसित की जाती है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली तथा नीति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम तथा इस नियमावली के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझा जाएगा।
- (3) ऐसे निरसित नियमावली के किन्हीं उपबंधों के सभी संदर्भ इस नियमावली के तत्संबंधी उपबंधों के संदर्भों के रूप में समझे जाएँगे।
- (4) इस नियमावली के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व किसी पदाधिकारी, प्राधिकार या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियाँ (अन्वेषण के माध्यम से की गयी कार्यवाहियों सहित) ऐसे प्रारंभ पर इस नियमावली के अनुसार इसके समक्ष लंबित कार्यवाही समझी जाएँगी और तदनुरूप कार्रवाई की जाती रहेंगी।

89. **कठिनाई दूर करने की शक्ति—** इस नियमावली के उपबंधों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा उपबंध कर सकेगी जिसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

90. **नियमावली का रखा जाना—**यह नियमावली जैसे ही बनाई जाय, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
सुशील कुमार,  
सरकार के अवर सचिव।

अनुसूची-I  
[नियम 2(x) देखें]

1	खनन लीज के लिए आवेदन	प्रपत्र-क
2	खनन लीज के विलेख	प्रपत्र-ख
3	खनन क्रिया परमिट के लिए आवेदन	प्रपत्र-ग
4	खनन क्रिया परमिट	प्रपत्र-घ
5	खनिज निपटान परमिट देने हेतु आवेदन	प्रपत्र-ड०
6	खनिज निपटान परमिट के लिए फारम	प्रपत्र-च
7	ई०चालान का प्रपत्र	प्रपत्र-छ
8	लीजधारी/परमिट धारक द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर	प्रपत्र-ज
9	मासिक रिटर्न	प्रपत्र-झ
10	वार्षिक रिटर्न	प्रपत्र-ञ
11	स्टॉकिस्ट लाइसेन्स	प्रपत्र-ट
12	अपील के लिए फारम	प्रपत्र-ठ

अनुसूची-II  
[नियम 51(1)(क) देखें]  
अनिवार्य लगान

अवधि	अनिवार्य लगान की दर (रुपये में)
1	2
पट्टा की सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रति वर्ष की दर	50,000.00 रु० प्रति एकड़ प्रति वर्ष

अनुसूची-III क  
[नियम 51(1)(ख) देखें]

क्रमांक	रॉयल्टी खनिजों का नाम	प्रतिघनमीटर दर, रुपये में।
1	2	3
1	(क) बोल्टर, ग्रेवेल अथवा पत्थर चाहे जिस नाम से परिभाषित हो (ख) नीलामी की रीति से बंदोबस्त पत्थर	150.00 नीलामी की दशा में नीलामी की राशि।
2	(क) निर्माण प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया साधारण बालू (ख) नीलाम घाटों का साधारण बालू	75.00 नीलामी की दशा में नीलामी की राशि।
3	ईट मिट्टी (400 मानक ईटों के बराबर)	18.00
4	साधारण मिट्टी/क्ले जिसका उपयोग बौध, सड़क, रेलवे, भवन, आदि के निर्माण के प्रयोजन में भरने तथा लेवल करने आदि तथा अन्य वाणिज्यिक कार्य हेतु जिसका उपयोग किया जाता हो।	33.00
5	लाईम सेल, लाईम स्टोन तथा कंकड़ जिसका उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में किल्ल हेतु चूना के विनिर्माण के लिए किया जाता हो तथा चूना का उपयोग बटन के विनिर्माण के लिए किया जाता हो।	165.00
6	मोरम	83.00
7	कैल्सीडोनी कंकड़ जिसका उपयोग केवल बॉल मिल के प्रयोजनार्थ होता है।	95.00
8	ग्रेडलर मिट्टी	83.00
9	क्वार्ट्ज जिसका उपयोग भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ या सड़क बनाने के लिए किया जाता है।	150.00

क्रमांक	रॉयलिटी खनिजों का नाम	प्रतिघनमीटर दर, रुपये में।
1	2	3
10	रेह मिट्टी	34.00
11	साल्ट पीटर	38.00
12	स्लेट तथा सेल जब उसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है।	110.00
13	फूलर्स मिट्टी (अर्थ)	124.00
14	स्टोन जिसका उपयोग ग्रिन्डिंग स्टोन सहित घरेलू बर्तन बनाने के लिए होता हो।	95.00
15	स्टोन सेट तथा स्टोन ब्रिक प्रति सैकड़ा	95.00
16	स्टोन डस्ट	30.00
17	ग्रेनाइट डिकोरेटिंग स्टोन के लिए उपयोग की दशा में प्रति सैकड़ा— (I) 60से0मी0 से अधिक ब्लॉक (II) 60 से0मी0 से कम ब्लॉक	709.00 355.00
18	क्वार्टज	73.00
19	बालू (अन्य)	75.00
20	सिलिका बालू	75.00
21	स्टीटाईट अथवा टाल्क या सोप स्टोन	मूल्यानुसार आधार पर विक्रय मूल्य का तीस प्रतिशत्।
22	अगेट	
23	बालक्ले	
24	बारिट्स	
25	काल्केरियस बालू	
26	कैल्साइट	
27	चॉक	
28	चइना क्ले	
29	क्ले (अन्य)	
30	कोरन्डम	
31	डिअयसपोर	मूल्यानुसार आधार पर विक्रय मूल्य का तीस प्रतिशत्।
32	डोलोमाईट	
33	डूनिट अथवा पाईरोक्सेनाईट	
34	फेल्साइट	
35	फेल्सपार	
36	फायर क्ले	
37	फुसाईट क्वार्ट्जाईट	
38	जिप्सम	
39	जस्पर	
40	कायोलीन	
41	लैटेराइट	
42	माईका	
43	ओक्रे	
44	पाइरो काइलाईट	
45	सभी अन्य खनिज	

**नोट:— (I)** बिहार खनिज समानुदान (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 या अन्यथा में प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, बंदोबस्तधारी नीलामी राशि के समकक्ष से अधिक उत्खनित तथा प्रेषित पत्थर की मात्रा के लिए अतिरिक्त रॉयलिटी का भुगतान करेगा।

**नोट:— (II)** बंदोबस्तधारी नीलामी राशि के समकक्ष से अधिक उत्खनित तथा प्रेषित बालू की मात्रा के लिए अतिरिक्त रॉयलिटी का भुगतान करेगा।

**नोट:— (III)** साधारण मिट्टी के गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई रॉयलिटी उगाही नहीं जाएगी।

**अनुसूची-III ख**

[नियम 38(1) देखें]

बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 38(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के अन्तर्गत स्थित विभिन्न क्षेत्रों, जनसंख्या, असैनिक निर्माण कार्य की स्थिति, औद्योगिक निर्माण कार्य की स्थिति, शहरीकरण की अवस्था एवं औद्योगिक विकास की गति को ध्यान में रखते हुए बिहार के राज्यपाल विभिन्न क्षेत्रों को श्रेणियों में विभाजित करते हुए प्रत्येक स्थायी चिमनी एवं बंगला ईट भट्टों के लिए ईंटों की संख्या और उस पर ईट भट्टा मालिकों/ईट मिट्टी हटाने वालों द्वारा प्रति भट्टा प्रति वर्ष राज्य सरकार को देय समेकित स्वामिस्व की राशि निर्धारित करते हैं जो निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है :-

**तालिका**

क्रमांक	क्षेत्र की श्रेणी	जिला का नाम तथा क्षेत्र	क्षमता स्तंभ 3 में दिखाये गये क्षेत्र में स्थित प्रति स्थायी चिमनी अथवा बंगला ईट भट्टा के निर्मित ईट।	स्वामिस्व-प्रति भट्टा प्रतिवर्ष देय स्वामिस्व की राशि जो स्तंभ 4 में निर्धारित ईट की संख्या पर देय है (रूपये में)।
1	2	3	4	5
1.	I	पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, जिलों का शहरी क्षेत्र।	45 लाख ईट	रु0 2,02,500.00 / -
2.	II	अन्य शहरी क्षेत्र	35 लाख ईट	रु0 1,57,500.00 / -
3.	III	ग्रामीण क्षेत्र	25 लाख ईट	रु0 1,12,500.00 / -
4.	IV	बंगला भट्टा	01 (एक लाख) ईट	रु0 4,500.00 / -

टिप्पणी (I)– “शहरी क्षेत्र” से अभिप्रेत किसी नगर निगम या नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थानीय सीमा के भीतर के क्षेत्रों से है और, यथास्थिति, उस नगर निगम या नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति की सीमा रेखा से चार किलोमीटर की बाहरी दूरी की भीतर पड़ने वाले क्षेत्र भी इसमें शामिल है।

टिप्पणी (II)– अव्यवसायिक, व्यक्तिगत उपयोग हेतु बंगला भट्टा में निर्मित ईट/ईट मिट्टी पर कोई स्वामिस्व भुगतान नहीं होगा।

## प्रपत्र-क

[नियम 24(2) देखें]

लघु खनिजों के लिए खनन लीज हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

समाहर्ता,

.....

महाशय,

मैं/हमें बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के प्रावधानों के अधीन खनन लीज देने के लिए ससम्मान आवेदन किया गया है।

प्राप्ति की तिथि-.....

(लघु हस्ताक्षर)

उक्त नियमावली के नियम 24(3) के अधीन भुगतान इस आवेदन के संबंध में भुगतान की गई फीस की राशि -.....रुपयें ..... (कोषागार अथवा कोषागार व्यवसाय करने वाला भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का नाम) में जमा कर दिया है सुसंगत चालान इसके साथ संलग्न है।

अपेक्षित विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं :-

1. आवेदन करने वाले व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी का नाम-
2. व्यक्ति की नागरिकता अथवा फर्म या कंपनी के निगमन के रजिस्ट्रीकरण का स्थान;
3. व्यक्ति का व्यवसाय अथवा फर्म या कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय का स्थान;
4. व्यक्ति, फर्म या कंपनी का पता-
5. खनिज जिसका या जिनका आवेदक खनन करने का उसका आशय हो;
6. अवधि जिसके लिए खनन लीज अपेक्षित हो;
7. उस क्षेत्र व्यौरा जिसके संबंध में वह लीज अपेक्षित हों;
  - (i) जिला-..... (ii) जे0एल0 संख्या-.....
  - (iii) प्लॉट संख्या-..... (iv) कुल क्षेत्र-.....
8. उपर्युक्त 7 में उल्लिखित क्षेत्र आच्छादित करने वाले 16'' = 1 किलोमीटर के स्केल पर नक्शा या योजना की विशिष्टियाँ, संलग्न करें। जिस क्षेत्र के संबंध में लीज अपेक्षित हो उसकी पहचान समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी दी जाएगी।
9. क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण-.....;
10. राज्य सरकार की अधिकारिता के भीतर क्षेत्र और खनिज जिनके लिए आवेदन या कोई व्यक्ति हितबद्ध हो खनिज..... क्षेत्र..... तालुका..... जिला.....
  - (क) पहले से कोई लीज धारित करता है;
  - (ख) पहले आवेदन किया था किंतु कोई लीज नहीं दी गई-
  - (ग) लगातार आवेदन किया है;
11. यदि उपर्युक्त 10 के अधीन हो तो संयुक्त हित की प्रकृति-
12. प्रथम वर्ष के दौरान निकाले जाने वाले खनिजों की संभावित अनुमानित मात्रा-
13. साधन जिनके द्वारा खनिजों को निकाला जाना हो उदाहरणार्थ- हस्तश्रम से या यांत्रिक या विद्युत शक्ति से और यांत्रिकरण की मात्रा यदि अपेक्षित हों-
14. निदेश की जाने वाली प्रस्तावित धन राशि-
15. खनन व्यवसाय में आवेदक का पूर्व का अनुभव-
16. वह रीति जिस रीत से निकाले गए खनिजों का उपयोग किया जाएगा, संभावित उपभोक्ता तथा खनिज के उपभोग का स्थान-
17. कोई अन्य विशिष्टियाँ जिसे आवेदक देना चाहे अथवा जिसकी अपेक्षा समाहर्ता द्वारा की जाय-
18. इस नियमावली में विहित आवेदन फीस के भुगतान की रीति तथा व्यौरा -

(नोट I)- शीर्ष ..... के अधीन राज्य सरकार के खाते में भुगतान की जाने वाली)

मैं/ हमलोग घोषणा करते हैं कि उपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं तथा मैं/हमलोग लीज अनुदान के पूर्व आपके द्वारा यथापेक्षित वास्तविक योजना तथा प्रतिभूति जमा इत्यादि सहित कोई अन्य व्यौरा देने के लिए तैयार हूँ/हैं।

स्थान-

तिथि-

आपका विश्वासभाजन

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर तथा पदनाम।



प्रपत्र-ख

[नियम 26(1) देखें]

लघु खनिजों के खनन पट्टा का आदर्श प्रपत्र।

यह एकरारनामा एक ओर बिहार-राज्यपाल (इसमें आगे राज्यपाल के रूप में निर्दिष्ट जिस पद के अन्तर्गत, जहाँ संदर्भ के अनुसार ऐसा माना जा सकता हो; उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी समझें जाएंगे) और दूसरी ओर,

1. जब पट्टाधारी कोई एक व्यक्ति हो—..... (व्यक्ति का नाम), पिता का नाम—....., निवास स्थान—..... (पता और पेशा), (इसमें आगे पट्टाधारी के रूप में निर्दिष्ट जिस पद के अन्तर्गत, जहाँ संदर्भ के अनुसार ऐसा माना जा सकता हो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समानुदेशिती भी समझें जाएंगे)।
2. जब पट्टाधारी एक से अधिक व्यक्ति हो—..... (व्यक्ति का नाम), निवास स्थान—....., (पता एवं पेशा)—..... (व्यक्ति का नाम), निवास स्थान—....., (पता एवं पेशा), (इसमें आगे पट्टाधारियों के रूप में निर्दिष्ट जिस पद के अन्तर्गत, जहाँ संदर्भ के अनुसार ऐसा माना जा सकता हो, क्रमशः उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी समझें जाएंगे)।
3. जब पट्टाधारी कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म या सिंडिकेट हो—..... (व्यक्ति का नाम), निवास स्थान (पता), और..... निवास स्थान (व्यक्ति का नाम), ..... (पता), जो सभी भारतीय पार्टनरशिप ऐक्ट, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत ..... (फर्म या सिंडिकेट का नाम) नाम और अभिनाम से ..... (फर्म या सिंडिकेट का पता) में सह-भागीदारी में कारबार कर रहे हैं, (इसमें आगे पट्टाधारियों के रूप में निर्दिष्ट जिस पद के अन्तर्गत, जब संदर्भ के अनुसार ऐसा माना जा सकता हो, उक्त फर्म के सभी भागीदारों, उनके प्रतिनिधि, वारिस, निष्पादक, प्रशासक और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझें जाएंगे)।
4. जब पट्टाधारी को रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो—..... (कम्पनी का नाम), जो ..... (उस अधिनियम का नाम जिसके अधीन वह निगमित हो) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ..... (पता) में है (इसमें आगे पट्टाधारियों के रूप में निर्दिष्ट, जिस पद के अन्तर्गत, जहाँ संदर्भ के अनुसार ऐसा माना जा सकता हो, उसके उत्तरवर्ती और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझें जाएंगे) के बीच (आज ता0 ..... 20.....को) किया गया।

चूँकि पट्टाधारी/ पट्टाधारियों ने इसके नीचे लिखित अनुसूची (इसमें आगे उक्त अनुसूची के रूप में निर्दिष्ट) के भाग 1 में वर्णित भूमि के संबंध में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (इसमें आगे उक्त नियमावली के रूप में निर्दिष्ट) के अनुसार, ..... (खनिजों का नाम) के खनन पट्टे के लिए बिहार सरकार (इसमें आगे राज्य सरकार के रूप में निर्दिष्ट) के पास आवेदन किया है और खनन पट्टे के लिए प्रतिभूति के रूप में ..... रू0 की राशि राज्य सरकार के पास जमा कर दी है।

अब यह एकरारनामा इस बात का साक्षी है कि इस विलेख और उक्त अनुसूची में अंतर्विष्ट लगानों, स्वामिस्वों, प्रसंविदाओं तथा करारों के पट्टाधारी/ पट्टाधारियों द्वारा और उसकी/ उनकी ओर से किये जाने वाले भुगतान, पालन और संपादन के प्रतिफल स्वरूप, राज्यपाल इसके पट्टेधारियों को ..... (यहाँ खनिज या खनिजों का नाम दें), (इसमें आगे और उक्त अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में निर्दिष्ट) की सभी खानों, संस्तरों, शिराओं/ परतों को, जो उक्त अनुसूची के भाग-I में उल्लिखित और वर्णित भूमि में या उसके नीचे स्थित या पड़ी हो, इसके संबंध में प्रयोज्य और उपभोग्य स्वातंत्र्यों, शक्तियों और विशेषाधिकारों के साथ जो उक्त अनुसूची के भाग-II में उल्लिखित है, और ऐसे स्वातंत्र्यों, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग के संबंध में उक्त अनुसूची के भाग-III में यथा उल्लिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्वधीन, किन्तु उक्त अनुसूची के भाग-IV में उल्लिखित उन स्वातंत्र्यों, शक्तियों और विशेषाधिकारों को पट्टाकरण में बचाकर राज्य सरकार के लिए सुरक्षित रखते हुए पट्टे पर देते हैं, ताकि इसके द्वारा पट्टाकृत परिसर को पट्टाधारी ता0 ..... से ..... आगामी पाँच वर्षों की अवधि के लिए धारण करें और उसके लिए उक्त अनुसूची के भाग-VI में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्वधीन, उक्त अनुसूची के भाग-ट में उल्लिखित लगान और स्वामिस्व उसमें विनिर्दिष्ट समयों पर चुकाए तथा पट्टाधारी इसके द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है / करते हैं जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-टII में अभिव्यक्त है और राज्य सरकार इसके द्वारा पट्टाधारी / पट्टाधारियों के साथ प्रसंविदा करती है जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-VIII में अभिव्यक्त है और इसके द्वारा इसके पक्षकार इसपर परस्पर सहमत हैं जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-IX में अभिव्यक्त है।

इसके साक्ष्य में, यह विलेख इसके नीचे वर्णित रीति से, पहले उपर लिखित तारीख को और वर्ष में निष्पादित किया गया।

## ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची।

## भाग I

## पट्टा का अवस्थिति एवं क्षेत्र।

रजिस्ट्रीकरण जिला ..... अनुमंडल-..... और थाना..... के परगना ..... में ..... (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) स्थित सभी भूभाग, जिनकी भूकर सर्वेक्षण सं० ..... है और जिनका क्षेत्रफल ..... या उसके लगभग है तथा जो इसके साथ अनुबद्ध रेखांक कर चित्रित और उसपर ..... रेखाओं से चिह्नित ..... से रंगे हुए है तथा जिनकी सीमाएँ निम्नलिखित हैं:-

उत्तर-.....  
दक्षिण-.....  
पूरब-.....  
पश्चिम-.....

इसमें आगे “उक्त भूमि” के रूप में निर्दिष्ट।

## भाग II

भाग III में उल्लिखित निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए पट्टाधारी/पट्टाधारियों द्वारा प्रयोजन और उपभोग्य स्वतंत्र्य, शक्ति और विशेषाधिकार।

22. **भूमि पर प्रवेश करना तथा खोज करना, प्राप्त करना, कार्य करना आदि-**  
उक्त भूमि पर प्रवेश करने तथा उक्त खनिज/ खनिजों की खोज करने के लिए खनन, बोर, खुदाई, ड्रिल करने, प्राप्त करने, कार्य करने, ड्रेस करने, प्रसंस्कृत करने, ले जाने, बदलने तथा निपटारा करने के लिए एतद्वारा अवधि के दौरान सभी समय स्वातंत्र्य तथा शक्ति।
2. **गड्ढा, शॉफ्ट, तथा आनति बनाना-** इस भाग में उल्लिखित किस प्रयोजन या उसके उक्त भूमि में कोई गड्ढा, शॉफ्ट, आनति, ड्रिफ्ट, लेबल, वाटरवेज, एयरवेज तथा अन्य कार्य, खोदने, संचालित करने, बनाने, संधारित करने हेतु (तथा उक्त भूमि में इस प्रकार की प्रकृति के किसी विद्यमान कार्यों का उपयोग, अनुरक्षण करने, गहरा करने अथवा विस्तार करने की) स्वातंत्र्य और शक्ति।
3. **मशीनरी एवं उपकरणों आदी लाना एवं उनका उपयोग करना-** इस भाग में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए या से संबंधित उक्त भूमि पर या के अधीन उपयोग करने, इंजन, मशीनरी, प्लांट, ड्रेसिंग प्लोर, फरनेस, कोक ओयन, ब्रिक किल्न, कार्यशाला, भंडारण गृह, बंगला, गोदाम, शेड तथा अन्य भवन खड़ा करने, निर्माण या अनुक्षित करने तथा उक्त भूमि पर इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं का उपयोग करने की स्वतंत्रता एवं शक्तियाँ।
4. **सड़क एवं रास्ता आदि बनाना और विद्यमान सड़कों एवं रास्तों का उपयोग करना :-** इस भाग में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए अथवा से संबंधित कोई सूचना ट्रामवेज, रेलवे, एयरक्राफ्ट लैंडिंग ग्राउन्ड तथा अन्य रास्ता उक्त भूमि में या पर बनाने तथा उपयोग, अनुरक्षण करने तथा उसपर घोड़ों, मवेशी वैगन, एयरक्राफ्ट, लोकोमोटिव या अन्य यानों के साथ या बिना (अथवा उक्त भूमि में/पर किसी विद्यमान ट्रामवेज, रेलवेज, सड़क तथा अन्य रास्तों यथा सहमत शर्तों पर जाने की स्वतंत्रता एवं शक्तियाँ।
5. **धारा आदि के जल का उपयोग करना-** इस भाग में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए या से संबंधित स्वतंत्र एवं शक्तियों का किसी विद्यमान अथवा भावी लीज धारियों के किसी अधिकार के अध्यधीन तथा उक्त भूमि में अथवा पर किसी धारा, जलमार्ग, झरना अथवा अन्य स्रोत को विनियोजित तथा उपयोग करने हेतु उपायुक्त की किसी अनुमति से किसी ऐसी धारा या जल मार्ग पर कार्रवाई, बाँध हेतु तथा किसी ऐसे जल का संग्रहता परिबद्ध करना तथा किसी जलमार्ग कल्मर्ट, नाला या जलाशय बनाने, निर्माण तथा अनुरक्षण करने किंतु किसी कृषिकर्म भूमि, ग्राम, भवन अथवा पशुओं के लिए यथा पूर्व परम्परागत युक्तियुक्त जलापूर्ति के लिए जलप्रदायी स्थानों से वंचित करने अथवा किसी धारा, झरना को किसी प्रकार से कूट कर्म अथवा प्रदूषित नहीं करना इस हेतु स्वतंत्रता एवं शक्तियाँ बशर्ते कि लीजधारी राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना किसी नाव्य धारा में नौचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ऐसी धारा मोड़ेगा।
6. **ढेर लगाने, संचय करने या जमा करने के प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग करना-** उक्त भूमि पर प्रवेश करने तथा उसकी सतह के पर्याप्त भाग पर ढेर लगाने, संचय करने या खान के उत्पादों के भंडारण तथा जमा करने के प्रयोजनार्थ कोई कार्य जारी रखने तथा इस भाग में उल्लिखित दायित्वों एवं शक्तियों के अधीन खोदे या निकाले गये तत्वों एवं किसी औजार, उपकरण, मिट्टी का उपयोग करने हेतु स्वातंत्र्य एवं शक्ति।
7. **उत्पादन की लाभदायकता तथा परिवहन करना-** उक्त भूमि उत्पादित किसी खनिज को लाभदायक बनाने तथा ऐसे लाभदायक बने खनिजों को ले जाने हेतु उक्त भूमि के पर्याप्त भाग पर प्रवेश करना तथा उपयोग करने की स्वातंत्र्य तथा शक्ति।

8. **झाड़ियों को साफ करना तथा पेड़ों आदि को काटना और उपयोग करना—**  
इस भाग में उल्लिखित प्रयोजन के लिए या से संबंधित स्वतंत्रता तथा शक्तियाँ तथा अन्य के विद्यमान अधिकारों के अध्यक्षीन तथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय

### भाग—III

भाग—II में स्वतंत्रता, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के संबंध में निर्बंधन और शर्तें।

1. **कतिपय स्थानों पर कोई निर्माण आदि नहीं किये जाएँगे—** किसी सार्वजनिक विहार स्थल, श्मशान, कब्रग्राह अथवा व्यक्तियों के किसी घर या ग्राम स्थल, सार्वजनिक सड़क या अन्य स्थान जिसे राज्य सरकार सार्वजनिक स्थल विनिश्चित करे, पर कोई भवन खड़ा नहीं किया जाएगा अथवा कोई सतह प्रचालन इस रीति से नहीं किया जाएगा, जिससे किसी भवन, कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकार की उपहति या प्रतिकूलतः प्रभावित करता हो और किसी भूमि का उपयोग ऐसे सतह प्रचालन के लिए नहीं किया जाएगा जो पहले से राज्य सरकार से अन्यथा व्यक्तियों द्वारा इस लीज में शामिल नहीं किए गए कार्यों या प्रयोजन के लिए उपभोग में हो। पट्टाधारी मार्ग, कुँआ या तालाब संबंधी किसी अधिकार में भी हस्तक्षेप नहीं करेगा।
2. **वैसे भूमि में, जो पहले से उपयोग में न हों, सतह प्रचालन के लिए अनुमति—** सतह प्रचालन के लिए किसी भूमि के उपयोग के पूर्व, जिसका उपयोग ऐसे प्रचालन के लिए नहीं किया गया हो, लीजधारी/लीजधारीगण जिले के उपायुक्त को, वैसा उपयोग किए जाने की प्रस्तावित भूमि के नाम, या अवस्थिति का अन्य विवरण तथा विस्तार तथा उस प्रयोजन, जिसके लिए उसकी आवश्यकता हो, विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित रूप में दो कलेन्डर माह की पूर्व सूचना देगा और उस भूमि का इस प्रकार उपयोग तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि उस सूचना की प्राप्ति के बाद दो माह के भीतर उपायुक्त द्वारा यदि कोई आपत्ति निर्गत नहीं की जाती तबतक वैसी आरंभ की गई आपत्तियाँ राज्य सरकार के निर्देश पर बालित या अवैध घोषित नहीं की जाएगी।
3. **अनारक्षित भूमि पर स्थित वृक्ष काटना—** पट्टाधारी/पट्टाधारीगण समाहर्ता के अभिव्यक्त मंजूरी के बिना, उक्त भूमि पर खड़े किसी इमारती लकड़ी के पेड़ों या पेड़ों को नहीं काटेंगे या आहत करेंगे किंतु ऐसी मंजूरी के बिना वैसी किसी झाड़ी अथवा झाड़ झंखाड़ साफ कर सकेंगे जो उनके द्वारा प्राधिकृत किसी प्रचालन में हस्तक्षेप करते हों। समाहर्ता पट्टाधारी/पट्टाधारीगण से उनके द्वारा किसी पेड़ या इमारती लकड़ी के पेड़ को गिराने तथा उनके उपयोग के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग में, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर, भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा।
4. **आरक्षित वनों में प्रवेश नहीं करना—** इस अनुसूची में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पट्टाधारी/पट्टाधारीगण उक्त भूमि में शामिल किसी आरक्षित वन में प्रवेश नहीं करेंगे अथवा किसी इमारती लकड़ी के पेड़ों या पेड़ों को गिरा, काट अथवा उसका उपयोग नहीं करेंगे।
5. **लोक निर्माण आदि के 50 मीटर के भीतर खनन संक्रिया नहीं की जायेगी—** पट्टाधारी/पट्टाधारीगण, संबंधित रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के सिवाय किसी रेलवे लाइन अथवा किसी रोपवे के स्वामित्व वाले प्राधिकारी की लिखित अनुमति के सिवाय अथवा के अनुसार किसी रोपवे या किसी रोपवे, टकटकी या पड़ाव के नीचे या भीतर अथवा उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के सिवाय तथा सामान्य या विशेष ऐसे अनुदेशों, निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार जो ऐसी अनुमति के साथ संलग्न हो, किसी जलाशय, नहर या अन्य लोक निर्माण, जैसे सार्वजनिक सड़क तथा भवन अथवा वास स्थल से 50 मीटर पर अथवा की दूरी के भीतर किसी जगह पर किसी खनन प्रचालन का कार्य नहीं करेगा या चलाएगा अथवा कार्य करने या चलाने की स्वीकृति नहीं देगा। उक्त 50 मीटर की दूरी की मापी रेलवे, जलाशय अथवा नहर की दशा में, यथास्थिति, बाहरी किनारे अथवा कटिंग को बाहरी किराने से क्षैतिज रूप से तथा भवन की दशा में, उसकी नींव से क्षैतिज रूप से की जाएगी। ग्रामीण सड़कों की दशा में, उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय तथा ऐसे सामान्य या विशेष निदेशों, निर्बंधनों और शर्तों, जो ऐसी अनुमति के साथ संलग्न की जाय, से अन्यथा कटिंग बाहरी किनारे से 10 मीटर की दूरी के भीतर कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण:—** इस खंड के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति “रेलवे प्रशासन” से अभिप्रेत है भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में इस अधिनियम की धारा 3 के खंड (6) द्वारा यथा परिभाषित। “सार्वजनिक सड़क” से अभिप्रेत है वैसी सड़क जो जिला फोरम के रूप में लगातार उपयोग के कारण कृत्रिम सतह द्वारा निर्मित हो गया हो। “ग्रामीण सड़क” में राजस्व अभिलेख में ग्रामीण सड़क के रूप में दिखाया गया कोई रास्ता शामिल है।

6. **निकटतम सरकारी अनुज्ञप्तियों/पट्टों के लिए सुविधाएँ—** पट्टाधारी/पट्टाधारीगण ऐसी किसी भूमि पर, जो पट्टाधारी/पट्टाधारियों द्वारा धारित भूमि में अंतर्विष्ट हो या उसके निकट हो या जिसपर पट्टाधारी द्वारा धारित भूमि होकर पहुँचा जा सकता हो, सरकार अनुज्ञप्ति या पट्टाधारण करने वाले विद्यमान या भावी पट्टेधारियों को उसपर पहुँचने की युक्तियुक्त सुविधा देगा।

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों या पट्टाधारियों द्वारा इस प्रस्तुतीकरण के अधीन पट्टाधारी/पट्टाधारियों के प्रचालन के प्रति कोई सारवान बाधा या हस्तक्षेप किया जाएगा और आपसी सहमति या असहमति की दशा में राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित न्याय संगत प्रतिकर पट्टाधारी/पट्टाधारियों को इस स्वतंत्र के प्रयोग के कारण पट्टाधारी/पट्टाधारियों को हुए घाटे या नुकसान के लिए दिया जाएगा।

#### भाग-IV

##### राज्य सरकार के लिए आरक्षित स्वतंत्र्य, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार

1. **अन्य खनिजों का कार्य करना**— राज्य सरकार अथवा पट्टाधारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए, इस भूमि पर प्रवेश करने तथा उक्त खनिजों से अन्यथा खनिजों तथा किसी अन्य तत्वों की खोज करने, विन करने कार्य, खुदाई करने, उठाने, सज्जित, प्रसंस्कृत करने, बदलने तथा ढो ले जाने हेतु तथा इस प्रयोजनार्थ खोदने, चलाने, बनाने, खड़ा करने, ऐसे पिट्स, शैपट, इनक्लाइनस्, ड्रिपट, लेवल तथा अन्य लाइन, वाटरवेज, एयरवेज, जलधाराओं, नालों, जलाशयों, इंजन, मशीनरी, प्लांट, भवन, नहरों, ट्रामवेज रेलवेज, रोडवेज तथा अन्य कार्य तथा ऐसी प्रसुविधाओं के लिए, जिसे आवश्यक तथा सुगम समझा जाय, स्वतंत्रता तथा शक्तियाँ :

परन्तु ऐसी स्वतंत्रता और शक्तियों के प्रयोग में इन प्रस्तुतीकरणों के अधीन किसी पट्टाधारी/पट्टाधारीगण की स्वतंत्रता, शक्तियों एवं विशेषाधिकारों में कोई सारवान बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा और कि न्याय संगत प्रतिकर (यथा परस्पर सहमति पर अथवा असहमति की दशा में राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित) पट्टाधारी/पट्टाधारियों को, ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्तियों के प्रयोग के कारण या फलस्वरूप पट्टाधारी/पट्टाधारीगण को हुई सभी हानि या नुकसान के लिए दिया जाएगा।

2. **रेलवे पटरी तथा सड़क बनाना**— राज्य सरकार या किसी पट्टाधारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के लिए, उक्त भूमि पर प्रवेश करने तथा इन प्रस्तुतीकरणों के भाग II में उल्लिखित प्रयोजनों से अन्यथा किसी प्रयोजन के लिए उस पर अथवा इसके जरिए कोई रेलवेज, ट्रामवेज, रोडवेज, विद्युत लाइन, टेलिफोन लाइन अथवा पाईप लाइन का निर्माण करने तथा ऐसे रेलवेज, ट्रामवेज सड़कों तथा विद्यमान रेलवेज, ट्रामवेज तथा सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए इस भूमि से पत्थर, ग्रेभल, मिट्टी तथा अन्य खनिजों को लेने तथा ऐसी रेलवेज, सड़कों, लाइन पर तथा सभी प्रयोजनों के लिए एवं अवसरों की आवश्यकता के अनुसार अन्य तरीके से घोड़ों, मवेशी या अन्य पशुओं, गाड़ी वैगन, वाहन, ट्रक, कार, रेल इंजन या यानों के साथ अथवा इनके बिना सभी समय जाने और पुनः गुजरने की स्वतंत्रता एवं शक्तियाँ परन्तु ऐसे अन्य पट्टाधारी या व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता एवं शक्तियों के प्रयोग में कोई सारवान बाधा या हस्तक्षेप पट्टाधारी की स्वतंत्र्य, शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रति नहीं किया जाएगा और ऐसी पट्टाधारी अथवा व्यक्ति द्वारा की ऐसी स्वतंत्रता, शक्तियों एवं विशेषाधिकारों के प्रयोग के कारण अथवा के फलस्वरूप पट्टाधारी को हुई हानि अथवा नुकसानी के लिए इस प्रावधान के अध्याधीन कि जहाँ केवल विद्युत अथवा टेलीफोन लाइन अथवा वैसी ही अन्य लाइनें पट्टा के अधीन इस भूमि में या पर ले जायी गयी हैं, कोई प्रतिकर भुगतान नहीं समझा जाएगा।
3. **भूल से किया गया पट्टा**— पट्टाधारी का इस पट्टा में शामिल की गई भूमि के संबंध में, जो पहले ही किसी पूर्व पट्टा में शामिल की गई हो, किसी प्रतिकर अथवा नुकसानी के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा किंतु भूमि के संबंध में, जो पट्टा के लिए उपलब्ध नहीं हो और इसकी जानकारी बाद में तो निर्धारण की आनुपातिक कमी का हकदार होगा।
4. **बहुमूल्य खनिज पाए जाने की दशा में कार्रवाई**— किसी भी समय यह विश्वास करने के कारण की दशा में किन जिसके लिए यह पट्टा दी गई है। उन खनिजों के साथ बहुमूल्य खनिज विद्यमान हैं तो समाहर्ता उस पट्टाधारी के अनुपालन के लिए ऐसा आदेश जिसे समाहर्ता उचित समझे उस खनिज की, जिसके लिए यह लीज दी जा रही है, सफाई अथवा स्क्रीन या जमा पट्टाधारी को यह लीज दिया जाना हमेशा समाहर्ता के उस पट्टा को समाप्त करने का अधिकार पूर्वाग्रह के बिना होगा यदि पट्टाकृत खनिज में किसी भी समय कोई बहुमूल्य खनिज अंतर्विष्ट हो जिसके पृथक्करण, समाहर्ता की राय में, आसानी से संभव न हो अथवा पट्टाधारी के साधनों से संभव न हो।

#### भाग V

##### इस पट्टा द्वारा आरक्षित लगान एवं स्वामिस्व

1. **अनिवार्य/मृत लगान या स्वामिस्व, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना**— पट्टाधारी, पट्टा के प्रथम वर्ष को छोड़कर, प्रत्येक वर्ष के लिए इस भाग के खंड 2 में विनिर्दिष्ट अनिवार्य/मृत लगान का भुगतान करेगा:  
परन्तु पट्टाधारी प्रत्येक खनिज के संबंध में अनिवार्य/मृत लगान अथवा स्वामिस्व, जो भी राशि में अधिक हो किंतु दोनों नहीं, का भुगतान करने का दायी होगा।

2. **अनिवार्य/मृत लगान की दर एवं भुगतान की रीति**— इस भाग के खंड 1 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, दिनांक ..... से पट्टा के अस्तित्व के दौरान, पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण समाहर्ता को ..... के माह की तिथि.....को चार समान त्रैमासिक रूप से चार किस्तों में अथवा प्रत्येक वर्ष की तिथि..... को दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में इस नियमावली की अनुसूची-II राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय पुनरीक्षण के अध्वधीन इस अनुसूची के भाग-I में यथावर्णित प्रति एकड़ भूमि की निम्नलिखित दर से कतिपय वार्षिक अनिवार्य/मृत लगान का भुगतान करेगा।
3. **स्वामिस्व/बंदोबस्ती राशि के दर एवं भुगतान की दर एवं रीति**— इस भाग के खंड I के प्रावधानों के अध्वधीन, पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण इस पट्टा के अस्तित्व के दौरान, राज्य सरकार को, इस समय और उस रीति से जो राज्य सरकार विहित करे, पट्टाकृत क्षेत्र से अपने द्वारा हटाए गए किसी खनिज/ खनिजों के संबंध में उक्त नियमावली की अनुसूची-IIIक में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से बंदोबस्ती राशि/ स्वामिस्व के किस्तों का भुगतान करेंगे।
4. **सतही लगान एवं जल (उपकर) का भुगतान**— पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण उस भूमि के, जिसका अधिभोग या उपयोग समय-समय पर, इस प्रस्तुतीकरणों के प्राधिकारी के अधीन पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा किया जाएगा, के सतह के सभी भागों के संबंध में, राज्य सरकार को, उस अधिभोग या उपयोग किए क्षेत्र का प्रतिवर्ष प्रतिकड़ क्रमशः ..... रुपये और ..... रुपये की दर से और ऐसे अधिभोग या उपयोग के आरंभ से जब तक कि वैसे क्षेत्र का वैसे अधिभोग या उपयोग समाप्त न हो जाय, और यथा संभव वैसे उपयोग की गई भूमि की सतह भूमि अपनी मूल दशा में प्रत्यावर्तित न हो जाय, की अवधि के दौरान एक एकड़ से कम किसी क्षेत्र के लिए उसी अनुपात में लगान और जल उपकर का भुगतान किया जाएगा: परन्तु ऐसा लगान/ जल उपकर उस क्षेत्र के अधिभोग/ उपयोग के संबंध में भुगतेय नहीं होगा और किसी सड़क या रास्ते में जिसपर आमजन की पहुँच का पूर्ण अधिकार हो इसमें शामिल हो।

#### भाग VI

#### लगान तथा स्वामिस्व से संबंधित प्रावधान।

1. **लगान एवं स्वामिस्व आदि कटौतियों से मुक्त होंगे**—इस अनुसूची के भाग-V में उल्लिखित लगान, जल उपकर तथा रॉयल्टियों का भुगतान किसी कटौती से मुक्त राज्य सरकार को उस (स्थान) ..... तथा उस रीति से किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय। रॉयल्टी की गणना की रीति।
2. **स्वामिस्व की संगणना की रीति**— उक्त स्वामिस्वयों की गणना करने के प्रयोजनार्थ, पट्टाधारी/पट्टाधारीगण उत्पादित तथा प्रेषित खनिज/खनिजों का शुद्ध लेखा रखेंगे। स्टॉक में खनिज/खनिजों के लेखा के साथ-साथ वनज अथवा निर्यात की प्रक्रिया की जाँच राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत की जाएगी। यदि लगान तथा स्वामिस्व समय पर संदत्त न तो कार्रवाई की रीति।
3. **मासिक लेखा राज्य सरकार को भेजा जायेगा**—यदि पट्टाधारी/पट्टाधारीगण द्वारा विहित समय के भीतर इस प्रस्तुतीकरणों के निर्बंधनों और शर्तों के अधीन राज्य सरकार को किसी लगान रॉयल्टी अथवा अन्य बकाए राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे इसपर अठारह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के साथ, इस अधिकारी के प्रमाण पत्र पर, जो राज्य सरकार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, विहित किया जाय, भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूल की जा सकेगी।
4. **बकाया भुगतान पर ब्याज** — पट्टाधारी राज्य सरकार को देय किसी भी रकम पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज चुकाने का भागी होगा।
5. **लगान और स्वामिस्व समय पर न चुकाये जाने पर की जानी वाली कार्रवाई**— यदि पट्टाधारी/पट्टाधारियों देय लगान, स्वामिस्व या अन्य देय रकम का भुगतान राज्य सरकार को वर्तमान शर्त एवं प्रावधान के अनुसार नियत समय पर नहीं किया जाता है तो 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी कानूनी अधिनियम अथवा उसकी नियमावली के अधीन पावना राज्य सरकार वसूल कर सकेगा।

#### भाग-VII

#### पट्टाधारी/पट्टाधारियों की प्रसंविदाएँ

1. **पट्टाधारी द्वारा लगानों, स्वामिस्व तथा करों आदि का भुगतान करेगा**— पट्टाधारी/पट्टाधारीगण इस लीज द्वारा आरक्षित लगानों, करों तथा स्वामिस्वयों का भुगतान इन प्रस्तुतीकरणों के भाग V एवं VI में उपबंधित समय पर तथा रीति से करेंगे और करों, उपकरों एवं निर्धारणों एवं अधिरोपणों का लोक मांग की प्रकृति रूप में जो भी हो तथा जो केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्राधिकारों द्वारा भू-राजस्व के लिए मांग को छोड़कर संयुक्त रूप से अन्य परिसरों तथा समान कार्य प्रकृति के अनुसार पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण के परिसरों तथा कार्य प्रकृति के संबंध में, समय-समय पर प्रभारित,

निर्धारित अथवा अधिरोपित किए जाएंगे का भी भुगतान करेंगे।

2. **सीमा चिन्हों को अच्छी दशा में बनाए रखना**— पट्टाधारी/पट्टाधारीगण अपनी खर्च पर इस पट्टा के साथ संलग्न प्लान में दर्शाए गए चिह्नांकनों के अनुसार सीमांकनों तथा परिसरों को खड़ा करेगा, हर समय अनुरक्षण तथा मरम्मत करेंगे। ऐसे चिह्नों तथा पीलरों को आसानी से पहचान के लिए झाड़ियों तथा अन्य बाधाओं से पर्याप्त रूप से साफ रखा जाएगा।
3. **सक्रिया तीन माह के भीतर आरंभ कर दी जाएगी तथा कार्य कारगर ढंग से किया जाएगा**— पट्टाधारी/पट्टाधारीगण पट्टा निष्पादन की तिथि से तीन माह के भीतर प्रचालन आरंभ करेंगे तत्पश्चात अपनी लीज जारी रहने के दौरान सभी समय ऐच्छिक बंदी के बिना कौशलपूर्ण तथा कर्मकर जैसी रीति तथा खंड 12 के अधीन यथा विहित रीति से उक्त भूमि की सतह या उसपर फसलों, भवनों, संरचनाओं या अन्य सम्पत्ति अनावश्यक अथवा परिहार्य नुकसान किए अथवा उसके लिए अनुमति दिए बिना उक्त खनिजों की खोज करेंगे वीन कार्य करेंगे अथवा विकास करेंगे। इस खंड के प्रयोजनार्थ प्रचालन में मशीनरी खड़ा करना, ट्रामवे बिछाना अथवा खान के संबंध सड़कों का निर्माण शामिल हैं।
4. **सभी दावों के लिए सरकार को क्षतिपूर्ति की जायेगी**— पट्टाधारी/पट्टाधारीगण सभी नुकसान, क्षति अथवा व्यवधान जो इस लीज द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग में उनके द्वारा किए जायें, के लिए विषयों पर लागू विधि के अनुसार विधिपूर्ण प्राधिकारी यथा निर्धारित युक्तियुक्त समाधान करेंगे तथा प्रतिकर का भुगतान करेंगे और सभी दावों के विरुद्ध, जो नुकसान, क्षति या व्यवधान तथा उससे संबंधित सभी खर्च एवं व्यय के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए जाय, की क्षतिपूर्ति करेंगे और राज्य सरकार को पूर्ण रूप से तथा पूर्णतः सुरक्षित करेंगे।
5. **सभी गड्डों, कूपों आदि को भरना एवं अच्छी दशा में सुरक्षित रखना**— पट्टाधारी/पट्टाधारीगण, इस लीज के अस्तित्व के दौरान इमारती लकड़ी अथवा सभी पिट्स, शैपट्स तथा कार्य के अन्य टिकाऊ साधन जिन्हें उक्त भूमि में बनाया जाय या जिनका उपयोग किया जाय, अच्छी तरह पर्याप्त रूप से सुरक्षित करेंगे और खुला रखेंगे और ऐसे पिट्स, शैपट्स अथवा प्रचालन चाहे वह परित्यक्त हो या नहीं, के चारों तरफ केन्द्र या राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी के समाधान प्रद रूप में पर्याप्त धेराबंदी करेंगे और अनुरक्षित करेंगे और उसी अवधि के दौरान उक्त भूमि में सभी प्रचालन, सिवाय ऐसे को छोड़कर जो यथा संभव परित्यक्त हो जाय, जल और गंदी हवा से मुक्त हो, बनाए रखेंगे।
6. **खानों को आवश्यक सीमा तक मजबूत करना तथा अवलंब देना**— पट्टाधारी /पट्टाधारीगण, यथास्थिति, संबंधित रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में खान के किसी भाग को, जिसे उसकी किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण और संरचना को सुरक्षा के लिए ऐसी मजबूतीकरण या सहारा देने की आवश्यकता हो, मजबूत करेंगे एवं सहारा देंगे।
7. **कार्य—चालान का निरीक्षण करने की अनुमति देना**— पट्टाधारी/पट्टाधारीगण केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को, किसी भवन, उत्खनन या लीज में शामिल भूमि सहित परिसरों में निरीक्षण, परीक्षण, सर्वे, पूर्वक्षण करने तथा उसका प्लान बनाने, नमूना लेने, किसी द्वारा संग्रहण के प्रयोजनार्थ स्वीकृति देंगे और लीजधारी/लीजधारीगण अपने द्वारा नियोजित तथा खानों तथा प्रभावकारी रूप से कार्यों से परिचित एवं उचित व्यक्ति के साथ ऐसे अधिकारी, एजेंट, सेवक, एवं मजदूरों को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण संचालित करने में सहायता करेंगे और खानों के कार्यों से संबंधित सभी सुविधाएँ तथा जानकारी, जिनकी उन्हें युक्तियुक्त रूप से आवश्यकता हो, उन्हें मुहैया करेंगे तथा सभी आदेशों एवं विनियमों का अवश्य पालन करेंगे जिसे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण अथवा अन्यथा के फलस्वरूप समय-समय पर, अधिरोपित करना उचित समझे।
8. **दुर्घटनाओं को प्रतिवेदित करना**— पट्टाधारी/पट्टाधारीगण, बिना विलंब किए, मृत्यु अथवा गंभीर शारीरिक क्षति या सम्पत्ति को गंभीर क्षति धारित करने वाली अथवा जीवन और सम्पत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या खतरे में डालने वाली किसी भी दुर्घटना, जो इस लीज के अधीन प्रचालन के दौरान घटित हो, को यथास्थिति, समाहर्ता/सक्षम अधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।
9. **अन्य खनिजों का पता चलने की रिपोर्ट करना**— पट्टाधारी/पट्टाधारीगण पट्टाकृत क्षेत्र में किसी खनिज की खोज को, जो पट्टा में विनिर्दिष्ट न हो, ऐसी खोज के साथ-साथ ऐसी प्रत्येक खोज की प्रकृति एवं स्थिति की पूर्ण विशिष्टियों साठ दिनों के भीतर, यथास्थिति, समाहर्ता/समक्ष अधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे। यदि किसी खनिज की जो पट्टा में विनिर्दिष्ट न हो, खोज लीज क्षेत्र में हुई हो तो पट्टाधारी/पट्टाधारीगण उस खनिज का विन एवं निपटारा तबतक नहीं करेंगे जबतक वह खनिज पट्टा में शामिल नहीं कर लिया जाता अथवा उसका एक पृथक लीज प्राप्त नहीं कर ली जाती।

10. **उत्पादन एवं कर्मचारियों आदि के संबंध में अभिलेख तथा लेखा रखना—** पट्टाधारी/पट्टाधारीगण उक्त कार्यकाल के दौरान सभी समय उक्त भूमि पर अवस्थित या के नजदीक एक कार्यालय में शुद्ध एवं स्पष्ट लेखा—पुस्त, जिसमें समय—समय पर दर्शाई गई निम्नलिखित सही प्रविष्टियाँ अंतर्विष्ट हों, रखेंगे या रखवायेंगे :—
- (1) उक्त भूमि से निकाले गए उक्त खनिज/ खनिजों की मात्रा एवं गुणवत्ता;
  - (2) परिष्कृत या संपरिवर्तित विभिन्न क्वालिटी के खनिजों का परिमाण;
  - (3) पृथकरूप से विक्रय या निर्यात किए गए उक्त खनिज/खनिजों की विविध गुणवत्ताओं की मात्रा
  - (4) अन्यथा निपटाए गए उक्त खनिज/ खनिजों की विविध गुणवत्ताओं की मात्रा तथा ऐसे निपटान की रीति तथा प्रयोजन
  - (5) उक्त खनिज/ खनिजों की कीमत तथा सभी बिक्रयों की सभी अन्य विशिष्टियाँ
  - (6) खानों में अथवा भूमि पर कार्यों में नियोजित व्यक्तियों की उनकी राष्ट्रीयता, अर्हता तथा तकनीकी कर्मियों को वेतन विनिर्दिष्ट करते हुए संख्या
  - (7) ऐसे अन्य तथ्य, विशिष्टियाँ एवं परिस्थितियाँ जिनकी राज्य सरकार, समय—समय पर, अपेक्षा करे तथा ऐसे अधिकारियों को उस समय जो राज्य सरकार नियत करे, ऐसे सभी या किसी लेखा पुस्त का सत्य एवं शुद्ध उद्दहरण तथा पूर्वोक्त सभी या किसी विषय से संबंधित ऐसी जानकारी एवं रिटर्न, जिसे राज्य सरकार विहित करे, मुफ्त भेजेंगे और सभी युक्तियुक्त समय पर ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्रवेश करने और उक्त लेखा पुस्तों, प्लान तथा अभिलेखों के परीक्षण एवं निरीक्षण करने एवं उनकी प्रतियाँ तैयार करने तथा उनसे उद्दहरण लेने के प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, प्रवेश करने हेतु स्वीकृति देंगे।
11. **प्लान आदि संधारित करना—** पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण उक्त अवधि के दौरान हर समय खान कार्यालय में शुद्ध, स्पष्ट अद्यतन एवं पूर्ण प्लान तथा उक्त भूमि में खान सेक्शनों को संधारित करेंगे। वे पट्टा के अधीन सभी प्रचालन एवं कार्यों तथा अपने द्वारा चलाए गए प्रचालन के क्रम में किए गए सभी खंदकों, पिट्स एवं ड्रिलिंग तथा की गई कोताही तथा अन्य बाधाओं को दर्शाएंगे एवं भूतत्विक द्वारा तथा सभी प्लान तथा सेक्शन संशोधित किए जाएंगे तथा बारह महीने अथवा समय—समय पर विनिर्दिष्ट किसी अवधि के अंत में इस प्रयोजनार्थ किए जाने वाले वास्तविक सर्वे द्वारा या से भरे जाएंगे और पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण राज्य सरकार को ऐसे प्लान तथा सेक्शनों की जब कभी आवश्यकता हो, की सत्य एवं शुद्ध प्रतियाँ मुफ्त भेजेंगे। सभी खंदकों, पिट्स एवं ड्रिलिंग के सही अभिलेख निम्नलिखित दर्शाएंगे :—
- (क) उपमिट्टी तथा स्ट्राटा जिसके माध्यम से वे गुजरते हैं
  - (ख) संघर्ष किया गया कोई खनिज
  - (ग) हित का कोई अन्य विषय तथा राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, अपेक्षित सभी डाटा पट्टाधारी/पट्टाधारीगण राज्य सरकार के किसी अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समय पर उसका निरीक्षण करने की स्वीकृति देंगे। वह वे राज्य सरकार, महानिदेशक, भारत भूतत्व सर्वे, महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा मांग किए जाने पर आरक्षित गुणवत्ता वार मात्रा के साथ सभी परतों मोटाई, गहराई, झुकाव आदि को दर्शाते हुए क्षेत्र का संयुक्त प्लान की आपूर्ति भी करेंगे।
- 11 क पट्टाधारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, विहित न्यूनतम मजदूरी से अन्यून मजदूरी का भुगतान करेंगे।
- 11 ख पट्टाधारी खान अधिनियम, 1952 जब भी लागू हो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करेंगे।
- 11 ग पट्टाधारी वृक्षारोपण, भूमि जीर्णोद्धार, प्रदूषण नियंत्रण उपायों के उपयोग जैसे पर्यावरण की सुरक्षा के उपाय तथा ऐसे अन्य उपाय अपने खर्च पर करेंगे जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर विहित किए जायें।
- 11 घ पट्टाधारी भू-अधियोगी को उस तिथि को तथा उस रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय, प्रतिकार का भुगतान करेंगे।
- 11 ड पट्टाधारी, नियोजन के मामले में, जनजाति तथा वैसे व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगे जो खनन प्रचालन करने के कारण विस्थापित हो गए हों।
12. **1957 का अधिनियम 67—** पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण उन नियमों से आबद्ध होंगे जो खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (1957 का अधि-67) की धारा 15 के अधीन भारत सरकार द्वारा, समय—समय पर, निर्गत किए जाय तथा इस नियमावली में यथा विहित के सिवाय किसी रीति से उक्त पट्टा के अधीन खनन अथवा अन्य प्रचालन नहीं करेंगे।

13. **तोल मशीन उपलब्ध करना**— राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से जब तक छूट प्राप्त न हो, पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण ऐसे पिट हेतु अथवा प्रत्येक पिट हेड्स पर या के नजदीक जहाँ उक्त खनिज जमा करने के लिए लाए जाते हों, एक उचित रूप से निर्मित तथा दक्ष तोल मशीन उपलब्ध करेंगे और इसपर जमा करने विक्रय करने निर्यात तथा परिवर्तित करने हेतु, समय-समय पर, लाए गए उक्त खनिजों तथा परिवर्तित उत्पादों को भी तोलेंगे अथवा तोलवाएंगे और प्रत्येक दिन के बंद होने पर, कुल वजन करवाएंगे, उक्त खनिजों, अयस्कों को चौबिस घंटे पूर्व के दौरान ऐसे साधनों द्वारा विनिश्चित उत्पादित, विक्रय, निर्यात, परिवर्तित किए गए उत्पादों को पूर्वोक्त लेखा पुस्तों में दर्ज कराएंगे। पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण राज्य सरकार को उक्त अवधि के दौरान सभी समय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को यथा पूर्वोक्त खनिजों को तोलते समय उपस्थित रहने तथा उनका लेखा रखने एवं लीजधारी/ लीजधारीगण द्वारा रखे गए लेखा को चेक करने हेतु नियोजित करने की अनुमति देंगे।
14. **तोलन मशीन की जाँच की अनुमति देना**—पट्टाधारी/पट्टाधारीगण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति/व्यक्तियों उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय यथा पूर्वोक्त उपलब्ध किए गए तथा रखे गए प्रत्येक तोल मशीन तथा उसके साथ उपयोग किए गए वाटों को यह निश्चित करने के लिए कि क्रमशः वे शुद्ध और अच्छी तरह मरम्मत एवं चालू दशा में हैं, का परीक्षण एवं जाँच के लिए स्वीकृति देंगे और यदि किसी ऐसे तोल मशीन या वाटों के ऐसे परीक्षण एवं जाँच पर यदि वे अशुद्ध या मरम्मत के लायक या अच्छी दशा में नहीं पाए जाएंगे तो राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि उसे समायोजित, मरम्मत तथा कामयाब स्थिति में पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण के खर्च पर रखा जाय और यदि वैसा किए जाने के बाद चौदह दिनों के भीतर वैसी अपेक्षाओं का पालन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार उन तोल मशीनों और वाटों को समायोजित, मरम्मत एवं कामयाब करवाएगी तथा वैसा करने का खर्च मांग किए जाने पर पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा एवं जाँच में यदि कोई त्रुटि किसी तोल मशीन या वाटों को राज्य सरकार के प्रतिकूल पाया जाता है तो इस त्रुटि को, उसके चलने से पूर्ववर्ती तीन कलेन्डर माह से अथवा इस तीन माह की अवधि के भीतर वैसा अवसर की दशा में उस तोल मशीन एवं वाटों के उस परीक्षण एवं जाँच के अंतिम अवसर से विद्यमान माना जाएगा और लगान तथा रॉयलिटी संदत्त की जाएगी तथा तदनुसार लेखापित की जाएगी।
15. **तृतीय पक्षकारों की क्षति के लिए प्रतिकर देना**— पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण इस प्रस्तुतीकरण द्वारा दी गई स्वतंत्रता एवं शक्तियों के प्रयोग में पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा अथवा की ओर से किसी व्यक्ति की सम्पत्ति के नुकसान, क्षति अथवा बाधाओं के लिए युक्तियुक्त समाधान तथा प्रतिकर का भुगतान करेंगे तथा सभी समय राज्य सरकार को सभी वादों, दावों तथा मांगों से या के विरुद्ध जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी नुकसान, क्षति या बाधा के संबंध में लाए अथवा किए जाय सुरक्षा देंगे और क्षतिपूर्ति करेंगे।
16. **अन्य खनिजों के कार्यों में बाधा नहीं डालना**— पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण एतद् द्वारा दी गई स्वतंत्रता एवं शक्तियों का प्रयोग इस रीति से करेंगे कि इस पट्टा में शामिल नहीं किए किन्हीं खनिजों की उक्त भूमि के भीतर विकास एवं कार्य को कोई अनावश्यक, अथवा युक्तियुक्त नजर अंदाज किए जाने योग्य बाधा या छेड़छाड़ न हो तथा सभी समय राज्य सरकार को और खनन पट्टाधारकों को, यथास्थिति, उक्त भूमि से जुड़ी किसी भूमि के भीतर किसी ऐसे खनिजों के संबंध में, उसे प्राप्त करने, कार्य करने, विकसित तथा ढो ले जाने के प्रयोजनार्थ इस खनिज को उक्त भूमि पर एवं आर-पार पहुँच के युक्तियुक्त साधन तथा सुरक्षित एवं सुविधाजनक रास्ता देंगे परंतु पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण किसी नुकसान या क्षति के लिए, जो इसे/उन्हें इस लीजधारी द्वारा इस रास्ते के उपयोग के कारण अथवा फलस्वरूप उठानी पड़े, युक्तियुक्त प्रतिकर प्राप्त करेंगे।
17. **पट्टा हस्तांतरण—**  
 (1) पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण समाहर्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना—  
 (क) खनन पट्टा अथवा उसमें किसी अधिकार, हक या हित को समनुदेशित, भाड़े पर या बंधक अथवा किसी भी रीति से हस्तांतरण नहीं करेंगे, या  
 (ख) कोई ऐसा करार, संविदा या समझौता नहीं करेंगे जिसके द्वारा पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सारवान विस्तार तक वित्त पोषित हो जिसके द्वारा/अधीन पट्टाधारी का प्रचालन या उपक्रम पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण से अन्यथा किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय द्वारा नियंत्रित होगा अथवा हो,  
 परन्तु समाहर्ता निम्नलिखित के संबंध में तब तक अपना अनुमोदन नहीं देगी जब तक कि —  
 (क) पट्टाधारी खनन पट्टा के हस्तांतरण के लिए आवेदन के साथ एक शपथ पत्र जिसमें राशि जिसे उसने अतिरिती से ले लिया है या बयाना के रूप में प्रस्ताव कर लिया है, विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत न कर दे



- (ख) खनन पट्टा का अंतरण व्यक्ति अथवा सीधे खनन प्रचालन उपक्रम को न किया जाना हो।
- (2) पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 65 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र में परित्यक्त कार्यों के सभी योजनाओं की मूल या अभिप्रमाणित प्रतियाँ अंतरिती को उपलब्ध कर देंगे।
- (3) समाहर्ता, लिखित रूप में आदेश द्वारा, किसी भी समय पट्टा विनिश्चित कर सकेंगी यदि पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण ने उपर्युक्त किसी प्रावधानों को भंग किया जा सकेगा:  
परन्तु ऐसा कोई आदेश पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण को अपने मामले का कथन करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।
18. **किसी न्यास, निगम, फर्म या व्यक्ति द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित नहीं किया जायेगा—** राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी न्यास, सिंडिकेट, निगम, फर्म, या व्यक्ति द्वारा लीज नियंत्रित नहीं की जायेगी और पट्टाधारी/पट्टाधारीगण स्वयं को नियंत्रित कराने हेतु स्वीकृति नहीं देंगे। पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण ऐसा करार, संविदा, समझौता नहीं करेंगे, जिसके द्वारा पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्त पोषित होंगे या हों जिसके द्वारा/के अधीन पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण के प्रचालन या उपक्रम किसी न्यास, सिंडिकेट, निगम, फर्म या व्यक्ति के द्वारा/के लाभ के लिए अथवा के नियंत्रण के अधधीन तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करार, संविदा या समझौता किए जाने के पूर्व राज्य सरकार की लिखित मंजूरी न दे दी गई हो और पूर्वोक्त कोई अथवा प्रत्येक ऐसा करार, संविदा या समझौता यथा पूर्वोक्त ऐसी मंजूर से ही किया जाएगा और सदैव उसके अन्य पक्षकार या पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रत्यक्ष ऐसी शर्त के अधधीन होंगे कि यह समाप्त करने योग्य होंगे यदि राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप में ऐसी अपेक्षा की जाय और ऐसी अध्ययेक्षा किए जाने पर तुरंत पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा तदनुसार समाप्त कर दिये जाएंगे।
19. **पट्टाधारी आवश्यक कोई अतिरिक्त राशि जमा करेगा—** जब कभी भी प्रतिभूति जमा ..... रूपये अथवा उसका कोई भाग अथवा इसके बाद उसके स्थान पर समाहर्ता के पास आगे जमा कोई राशि, राज्य सरकार द्वारा एतत्पश्चात् इस निमित्त घोषित शक्तियों के अनुशरण में, जप्त अथवा उपयोजित कर ली जायेगी और लीजधारी/ लीजधारीगण समाहर्ता के पास आगे ऐसी राशि जमा करेंगे जो पूर्ण प्रतिभूति जमा राशि के बराबर राशि तक राज्य सरकार के पास जमा में राशि लाने हेतु उसके अविनियोजित भाग के लिए पर्याप्त हो।
20. **पट्टा समाप्ति के बाद अच्छी दशा में खदानों को राज्य सरकार को दिया जाना—** पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण उक्त अवधि अथवा उसके किसी नवीकरण की समाप्ति अथवा विनिश्चय पर सभी खान, पिट्ट, शैपट्स इनवाईन्स, ड्रिप्ट, लेवल, वाटरवेज, तथा अभी विद्यमान अथवा एतत्पश्चात् उनको छोड़कर जो राज्य सरकार की मंजूरी से परित्यक्त हो गए हों, उक्त भूमि पर किए जाने वाले अथवा के अधीन संक, सभी अन्य कार्य तथा सामान्य तथा निष्पक्ष कार्य के क्रम में सभी इंजन, मशीनरी, प्लांट, भवन, संरचना, अन्य कार्य तथा प्रसुविधाएँ जो उक्त अवधि के आरंभ पर उक्त भूमि पर या के अधीन थे और पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा भूमि के भीतर लगाई गई सभी मशीनरी जो खानों की क्षति पहुँचाए बिना नहीं हटाई जा सकती हों अथवा उक्त भूमि के अधीन कार्य (उन्हें छोड़कर जिन्हें राज्य सरकार की मंजूरी से अनुपयोगी हो गए हों) तथा सभी भवन तथा भूमि की सतह के उपर मरम्मत लायक स्थिति तथा उक्त खानों तथा उक्त खनिजों के आगे कार्य के लिए सभी के संबंध में उपयुक्त पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा खड़ा की गई ईट एवं पत्थर की संरचनाएँ राज्य सरकार को दे देंगे।
21. **पूर्व क्रय का अधिकार—** (क) राज्य सरकार को, समय-समय पर, उक्त अवधि के दौरान सभी समय (पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण को लिखित सूचना देकर प्रयोग किया जाएगा) उक्त भूमि में या पर पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण के नियंत्रणाधीन पड़े उक्त खनिजों तथा उनके सभी उत्पादों का अग्रक्रयाधिकार होगा तथा पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण सभी संभव शीघ्रता से, इस प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा क्रय किए सभी खनिजों या उत्पादों अथवा अन्य खनिजों का परिदार उस समय की इस यात्रा, रीति तथा उस स्थान पर कर देगा जो उक्त अधिकार का प्रयोग करने वाली सूचना विनिर्दिष्ट किए गए हों।
- (ख) इस वर्तमान प्रावधान द्वारा प्रदत्त अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग किया जाएगा तथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की ओर से उपाप्त किए गए खनिजों या उनके उत्पादों को ले जाने के लिए कोई चार्टर्ड जलयान लादने के स्थान पर, डिमरेज पर ठहराये जाएंगे तथा पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण ऐसे जलयान के चार्टर्ड पक्ष की शर्तों के अनुसार विलंब शुल्क (डमरेज) के लिए सम्यक् भुगतान तब तक करेंगे जबतक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाय कि विलंब लीजधारी/ लीजधारीगण के नियंत्रण के बाहर के कारणों से न हुआ हो।
- (ग) एतद् द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा अग्रक्रयाधिकार में लिए गए सभी खनिजों अथवा उनके उत्पादों के लिए संदत्त की जाने वाली कीमत अग्रक्रय के समय

प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा बशर्त कि उक्त उचित बाजार मूल्य तक पहुँचने में के क्रम में पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण, यदि आवश्यक हो, सरकार की गोपनीय जानकारी के लिए, विशिष्टतः अन्य ग्राहकों को विक्रय किए गए उक्त खनिजों या उनके उत्पादों की मात्रा, विवरण तथा कीमतों तथा उसकी गाड़ी तथा भाड़े के लिए प्रविष्ट किए गए घोषणा पत्र (चार्टर्ड) राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे और ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को जिन्हें राज्य सरकार निदेशित करें, संविदा तथा ऐसे खनिजों या उत्पादों के विक्रय या भाड़े के लिए प्रविष्ट किए गए घोषणा पत्र, संविदा की मूल या अधिप्रमाणित प्रतियाँ उपस्थापित करेंगे।

- (घ) युद्ध एवं आपात की विद्यमान की दशा में भारत के राष्ट्रपति एकमात्र निर्णायक होंगे तथा उसका सबूत इस आशय की अधिसूचना होगी) राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की सहमति से, उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर, एवं सभी समय पट्टाधारी/पट्टाधारीगण की लिखित रूप में अनुमति सूचना द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार प्राप्त होगा तथा इस लीज के अधीन उक्त भूमि अथवा प्रचालन पर या के संबंध में पट्टाधारी/पट्टाधारीगण के कार्यों, प्लांट मशीनरी तथा परिसरों का तुरंत कब्जा ले लेगी तथा ऐसे कब्जा और नियंत्रण के दौरान केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा या की ओर से ऐसे कार्यों, प्लांट, परिसरों तथा खनिजों के उपयोग अथवा नियोजन के संबंध में दिए गए निदेशों के अनुरूप पालन करेंगे बशर्त कि उचित प्रतिकर जो राज्य सरकार द्वारा करार के व्यतिक्रम में विनिश्चित किया जाएगा, लीजधारी/ लीजधारीगण को, उसको/ उनको इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण अथवा फलस्वरूप हुई सभी हानि या नुकसान के लिए दिया जाएगा और भी कि सभी शक्तियों का प्रयोग एतद् द्वारा दी गई अवधि और इस प्रस्तुतीकरण के निर्बंधनों और शर्तों तथा प्रावधानों को आगे जो इस खंड के प्रावधानों को प्रभावी करने हेतु आवश्यक हो, विनिश्चित नहीं करेगी।
22. **विदेशी राष्ट्रीयों का नियोजन** — पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण, खनन प्रचालन के संबंध में, किसी ऐसे व्यक्ति को, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, नियोजित नहीं करेंगे जो भारतीय न हो।
23. **राज्य सरकार द्वारा उपगत खर्च की वसूली**— यदि कोई कार्य या मामला जो इस निमित्त प्रसंविदा के अनुसार एतत्पूर्व अंतर्विष्ट न हो, पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा पालन किए जाने वाले हों तो इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर पालन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार उनका पालन करायेगी और पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण मांग पर सभी खर्च जो उनका पालन करने में उपगत होंगे, का भुगतान राज्य सरकार को करेंगे तथा ऐसे खर्च के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
24. **भूतत्त्विक डाटा प्रस्तुत करना**— पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण,
- (क) खनन प्रचालन के दौरान खनन क्षेत्रों या अभियंत्रण तथा भूजल सर्वे, जैसे — विसंगति नक्शा, सेक्शन, प्लान, संरचना, कंटूर मैप, लौगिंग से संबंधित अपने द्वारा संग्रहित सभी भू-भौतिकी द्वारा राज्य सरकार तथा महानिदेशक भारत के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग को भेज देंगे।
- (ख) खनन प्रचालन के दौरान अपने द्वारा संग्रहित रेडियाधर्मी (रेडियाएक्टिव) खनिजों के अनुसंधान से संलग्न सभी जानकारी सचिव, परमाणु उर्जा विभाग, नई दिल्ली तथा राज्य सरकार को भेज देंगे।
- ऊपर निर्देशित द्वारा या जानकारी, खनन लीज अवधि के आरंभ की तिथि से गणना प्रत्येक वर्ष भेजी जाएगी।
25. **विस्फोटकों का भंडारण एवं उपयोग**— किसी विस्फोटक का भंडारण एवं उपयोग केवल तत्समय प्रवृत्त भारतीय विस्फोटक अधिनियम, मेटालिफेरस माइन्स रेगुलेशन तथा खनन निरीक्षक के विधिपूर्ण निदेशों के अनुसार किया जाएगा। पट्टाधारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होगा कि खान के लिए आशयित किसी विस्फोटक का लीज क्षेत्र के भीतर खनन के सिवाय पट्टा क्षेत्र के भीतर या बाहर चुराने या दुरुपयोग के लिए नहीं किया जाता है।
26. **सीमा विवाद**— यदि कोई सीमा विवाद अथवा अधिकार या रास्ता के संबंध में विवाद अथवा कोई अन्य विवाद पट्टा में किसी निर्बंधन या शर्त के निर्माण से संबंधित जो कुछ भी पट्टाधारी और समान निर्बंधन के अधीन पहले लीज कृत किसी ब्लॉक के पट्टा अथवा जो पश्चात्तर्वर्ती पट्टा की गई हो के बीच उत्पन्न हो तो पट्टाधारी वैसे विवाद को समाहर्ता अथवा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के निर्णय के लिए प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होंगे। उक्त अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रमंडल के आयुक्त के समक्ष संस्थित होगी और इस पर प्रमंडल आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा और पट्टाधारियों पर आबद्धकर होगा।
27. **नियमों तथा विनियमों का पालन किया जाना**— पट्टाधारी वैसे सभी विद्यमान विधियों तथा नियमों एवं विनियमों का पालन करेंगे जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाय अथवा

सभी ऐसी विधियों, नियम तथा विनियम जो, समय-समय पर, खान एवं खनिजों के कार्य तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पट्टाधारी के कर्मचारियों या आमजन के विश्वास को प्रभावित करने वाले अन्य विषय के संबंध में लागू किए जायें। राज्य सरकार से अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से खान के कार्यों के संबंध में अविधिपूर्ण या अनियमित किसी कार्य से संबंधित किसी नोटिस पर पट्टाधारी, पट्टाधारक या उसके कर्मचारी द्वारा किए गए किसी अविधिमान्य या अविधिपूर्ण कार्य के चलते सभी हानि के लिए राज्य सरकार को प्रतिकर का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

28. पट्टाधारी पट्टा रद्दकरण का दायी होगा यदि पट्टाधारी खान का कार्य या खनन क्रिया सक्षम अधिकारी या समाहर्ता की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना लगातार एक वर्ष की अवधि तक रोक देना है :
29. यदि पट्टाधारी पट्टाकृत क्षेत्र के किसी भाग में लगातार छः माह अवधि तक जिसका समाहर्ता एक मात्र निर्णायक है, कार्य नहीं करता है तो समाहर्ता को पट्टा समाप्त करने तथा क्षेत्र का दुबारा कब्जा, करने की शक्ति होगी बशर्ते कि पट्टाधारी को उसके विरुद्ध कारण दर्शाने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।
30. यदि पट्टाधारी पट्टाकृत क्षेत्र के 10 प्रतिशत से अधिक भाग पर लगातार 6 माह से अवधि तक, जिसका समाहर्ता एक मात्र निर्णायक होगा, कार्य नहीं करता है तो समाहर्ता को पट्टा में समाविष्ट क्षेत्र के 75 प्रतिशत भाग का दुबारा कब्जा करने की शक्ति होगी बशर्ते कि पट्टाधारी को उसके विरुद्ध कारण दर्शाने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और उसके द्वारा कार्य किए गए क्षेत्र को शामिल करते हुए पट्टाधारी के साथ छोड़ा गया क्षेत्र एक कम्पैक्ट ब्लॉक होगा और मूल पट्टा के निर्बंधन, समाहर्ता द्वारा दुबारा कब्जा किए जाने की तिथि से उसके अंतिम आदेश के बाद, यथा उपांतरित समझें जाएंगे।
31. यह सुनिश्चित करना पट्टाधारी की जिम्मेवारी होगी कि किसी व्यक्तिगत/ सार्वजनिक/समानुदायिक संपत्ति, कृषि योग्य भूमि/संरचना, यथा-सड़क/मंदिर/ मजिस्द/ गुरुद्वारा/चर्च या किसी अन्य संपत्ति का नुकसान खनन के दौरान न हो, अन्यथा पट्टाधारी को संबंधित को प्रतिकर का भुगतान करना पड़ेगा और उसकी बंदोबस्ती इस आधारों पर रद्द की जा सकती है तथा सभी जमा राशि जब्त की जा सकती है।
32. समाहर्ता पट्टाकृत क्षेत्र को रद्द कर सकेगा यदि उक्त क्षेत्र भावी पुरातात्विक स्थल आरक्षित/सुरक्षित वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो।
33. सभी खनन प्रचालन लीजधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्यावरणीय निर्बंधन की अधीन दिए गए निर्बंधन और शर्तों के अनुसार होंगे।
34. बंदोबस्ती के अधीन कोई खनन प्रचालन पट्टाधारी द्वारा पूरी बंदोबस्ती अवधि के लिए तैयार किए गए अनुमोदित खनन योजना के निर्बंधन और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
35. पट्टाधारी को पूरी लीज अवधि के दौरान प्रत्येक कलेन्डर वर्ष विहित दर पर जिला खनिज फाउन्डेशन को भुगतान करना होगा।
36. पट्टाधारी को आयकर और सरचार्ज के रूप में प्रत्येक कलेन्डर वर्ष बंदोबस्ती राशि के 2.06 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।
37. पट्टाधारी का राज्य सरकार विरुद्ध खनिजों की अनुपलब्धता या सीमा विवाद अथवा परिवहन में कारित किसी बाधा के चलते प्रतिकर या नुकसान का कोई दावा नहीं होगा।
38. पट्टाधारी अन्य लीजधारियों को अपने नीलाम क्षेत्र से खनिज के परिवहन की स्वीकृति देगा।
39. पट्टाधारी, पट्टाधारी का नाम, पता, बंदोबस्ती की अवधि तथा स्थानीय प्रबंधक का नाम एवं पता प्रदर्शित करने वाला खनन स्थल पर एक साईन बोर्ड प्रदर्शित करेगा।
40. पट्टाधारी को श्रम अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अधीन खनन क्रिया स्थल पर शेल/आश्रय/पीने का पानी, पालना घर, प्राथमिक चिकित्सा किट इत्यादि का प्रबंध करना होगा।
41. पट्टाधारी समाहर्ता द्वारा अधिरोपित किसी अन्य शर्त का जिसे वह लोकहित के संबंध में आवश्यक समझे, पालन करेगा। यदि पट्टाधारी उपरिल्लिखित किसी निर्बंधनों और शर्त को भंग करता है तो पट्टाधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सकारण आदेश पारित करके बंदोबस्ती समाप्त कर सकेगा।
42. यदि पट्टाधारी किसी किस्त, जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रीकरण फीस का समय पर भुगतान करने व्यक्तिक्रम करता है तो समाहर्ता विहित समय सीमा के भीतर भुगतान करने हेतु उससे अपेक्षा करते हुए तीस दिनों का नोटिस पट्टाधारी को देगा और यदि उस अवधि के भुगतान नहीं किया जाता है तो समाहर्ता, किसी कार्यवाही, जो पट्टाधारी के विरुद्ध की जाती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बंदोबस्ती समाप्त कर सकेगा और पूरी प्रतिभूति जमा या उसके भाग को जब्त कर सकेगा।
43. पट्टाधारी को किसी डिपहोल ब्लास्टिंग के लिए खनन क्षेत्र में कोई एच0ई0एम0एम0 उपयोग करने के लिए मेटालिफेरॉस माइन्स रेगुलेशन, 1961 के विनियम 106(2)(ख) के अधीन डी0जी0एम0एस0 से

- अनुमति लेनी होगी।
44. पट्टाधारी को केवल मुख्य सड़क से, पी0एम0जी0 एस0 वाई सड़क से नहीं, खनिज से लदे वाहनों को भेजना होगा।
  45. पट्टाधारी की इस नियमावली में विहित समय सीमा के भीतर खान बंदी योजना प्रस्तुत करना होगा।
  46. पट्टाधारी को प्रत्येक वर्ष 31वीं दिसम्बर के पूर्व वार्षिक रिपोर्ट, अनुमोदित खान बंदी योजना में यथा परिकल्पित चलाए गए सुरक्षात्मक तथा पुनर्वासित विस्तार को दर्शाते हुए, प्रस्तुत करना होगा।
  47. पट्टाधारी नियमावली में विहित प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण लीज अवधि में अपने खर्च पर सीमा पीलरों को बनाए रखेगा।
  48. पट्टाधारी जिला दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किसी विस्फोटक का उपयोग एवं भंडारण करेगा। लीजधारी भारतीय विस्फोटक अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किसी विस्फोटक का उपयोग करेगा। विस्फोटकों की आपूर्ति समाहर्ता द्वारा अनुशंसित फर्मों द्वारा की जाएगी।
  49. पट्टाधारी का पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर पड़ी हुई किसी प्रकार की संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।
  50. पट्टा अवधि पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए वैध होगी। क्षेत्र को हस्तगत करने में विलंब के लिए कोई दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  51. पट्टा विलेख अपेक्षित फीस के भुगतान कर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी। पट्टा विलेख का रजिस्ट्रीकरण न होने की दशा में पट्टा रद्द की जा सकेगी।

### भाग—VIII

#### राज्य सरकार द्वारा की गई प्रसंविदाएँ

1. **पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण अधिकार को शांतिपूर्वक धारित एवं उसका उपयोग कर सकेगा—** एतद् द्वारा आरक्षित लगानों, करों, स्वामिस्वों का भुगतान तथा इसमें अंतर्विष्ट तथा पट्टाधारी/पट्टाधारीगण की ओर से अनुपालित तथा संपादित की जाने वाली प्रसंविदाओं और करारों का अनुपालन एवं संपादन करते हुए पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण एतद् द्वारा दी गई अवधि के लिए और के दौरान राज्य सरकार से या द्वारा अथवा इसके अधीन अधिकार पूर्वक दावा करने वाला कोई व्यक्ति बिना किसी विधिपूर्व हस्तक्षेप के एतद् द्वारा पट्टाकृत अधिकारों तथा परिसरों को शांतिपूर्वक धारित एवं उपयोग कर सकेगा।
2. **पक्षकारों की भूमि का अर्जन तथा उसका प्रतिकर—** इस अनुसूची के भाग—VII के खंड 4 के प्रावधानों के अनुसार यदि पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण उक्त भूमि के किसी भाग की सतह का कोई अधियोगी किसी नुकसान या क्षति के लिए, जो पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण के प्रस्तावित प्रचालन से उत्पन्न हो, प्रतिकर के भुगतान के लिए देगा तो उक्त अधियोगी राज्य सरकार के आरक्षित अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग की अपनी सहमति देने से इंकार कर देंगे और पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण राज्य सरकार को वह मामला प्रतिवेदित कर देंगे तथा ऑफर किया गया प्रतिकर की राशि उसके पास जमा कर देंगे और यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय ऑफर की गई प्रतिकर की राशि उचित एवं युक्तियुक्त नहीं है अथवा यदि इसका समाधान उस प्रकार नहीं होता है और पट्टाधारी/पट्टाधारीगण के ऐसी और राशि, जो राज्य सरकार उचित एवं युक्तियुक्त विचार करे, उसके पास जमा करनी होगी तब राज्य सरकार उस पट्टाधारी/पट्टाधारीगण को उक्त भूमि पर प्रवेश करने ऐसे प्रचालन, जो इस पट्टा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, करने की स्वीकृति अधियोगी को देने हेतु आदेश करेगी। ऐसा प्रतिकर की राशि के निर्धारण करने में राज्य सरकार भू-अर्जन अधिनियम के सिद्धांतों में मार्गदर्शित होगी।
3. **पट्टा समर्पण करने की स्वतंत्रता—** पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण किसी भी समय, यथास्थिति, समाहर्ता को लिखित रूप में न्यूनतम छः माह की सूचना की समाप्ति पर बशर्ते कि पट्टाधारी/पट्टाधारीगण ऐसी समाप्ति पर सभी लगानों, करों, स्वामिस्व नुकसान के लिए प्रतिकर तथा अन्य राशि, जो इस प्रस्तुतीकरण के अधीन पट्टाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का तब बकाया हो, का भुगतान कर देंगे और इस प्रस्तुतीकरण को राज्य सरकार को दे देंगे तब यह पट्टा तथा उक्त अवधि तथा एतद् द्वारा दी गई स्वतंत्रता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार अत्यंतिकरूप से अस्तित्व में नहीं रहेंगे और समाप्त हो जाएंगे किन्तु इस प्रस्तुतीकरण में अंतर्विष्ट किसी प्रसंविदा या करार के किसी भंग के संबंध में पट्टाकर्ता किसी अधिकर एवं उपचार के प्रतिकूल नहीं होंगे।
4. पट्टाधारी के आवेदन किए जाने पर समाहर्ता उसे अपनी पट्टा से, जो जमीन पर खनिजों के समूह के

लिए हो जों उक्त खनिजों की जमा समाप्त या पट्टाकृत इस हद तक हो गई हो कि खनिजों का कार्य रास्ता रहना संभव न हो तो पट्टाधारी निम्नलिखित शर्तों के अधधीन एक या अधिक खनिजों का समर्पण करने हेतु अनमति दे सकेगा

- (क) समर्पण के लिए आशाचित तिथि से कम से कम छः महीने पूर्व खनिज के ऐसे समर्पण के लिए आवेदन करता है तथा
  - (ख) यह वचनबंध देता है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे इस खनिज के लिए पश्चात्वर्ती खनन लीज दी गई हो, समर्पण किए गए खनिज के कार्यों में वह कोई बाधा नहीं करेगा।
5. **प्रतिभूति जमा की वापसी**— इस पट्टा की समाप्ति के बाद 12 कलेन्डर माह के भीतर उस तिथि को जिसका चयन राज्य सरकार करे, इस लीज के संबंध में भुगतान की गई प्रतिभूति जमा की राशि और तब राज्य सरकार के पास अधिशेष जमा तथा इस पट्टा में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए जो आवश्यक न हो, पट्टाधारी/पट्टाधारीगण को वापस कर दी जाएगी। प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नहीं होगी।

### भाग IX

#### सामान्य प्रावधान

1. **किसी शर्त का भंग** :— इस भाग के खंड 2 एवं 3 में उल्लिखित से अन्यथा इस पट्टा की किसी शर्त के भंग होने की दशा में, समाहर्ता पट्टाधारी अथवा उसके अंतरितीयो या समनुदेशितियों से शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो भाग V के खण्ड 2 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक अनिवार्य लगान की राशि से अधिक नहीं होगी।
2. **निरीक्षण में बाधा डालना**— यदि पट्टाधारी या उसका अंतरितीय या समनुदेशिती समाहर्ता या समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों के प्रवेश या उनके द्वारा निरीक्षण में बाधा डाले या उसकी अनुमति न दे तो ऐसी दशाओं में और अधिक नहीं होगी भाग III के खंड 1 और भाग VII के खंड 13, 14 तथा 2 में उल्लिखित पट्टा की शर्तों में से किसी एक के भंग किये जाने की दशा में समाहर्ता उस लीज को रद्द कर सकेगा और संपूर्ण प्रतिभूति जमा अथवा उसके भाग को जप्त कर सकेगा।
3. **किसी अन्य शर्त का भंग किया जाना**— यदि पट्टाधारी या उसका अंतरितीय, समनुदेशिती भाग III के खंड—3 तथा भाग VII के खंड 2, 3, 6, 10, 23 में विनिर्दिष्ट किसी शर्त को भंग करता है तब और किसी ऐसे मामले में समाहर्ता यथास्थिति, पट्टाधारी या उसके अंतरितीय या समनुदेशिती को नोटिस की तिथि 30 दिनों के भीतर भंग के उपचार के लिए उनको आदेश देते हुए लिखित नोटिस देंगे और यदि भंग का उपचार इस अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो समाहर्ता पट्टा समाप्त कर सकेगा परन्तु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात से समाहर्ता, पट्टाधारी या उसके अंतरितीय या समनुदेशिती समाहर्ता के विरुद्ध ऐसा कोई अन्य अधिकार या उपचार को लागू करने से विवर्जित न होगा जो समाहर्ता, इसमें अंतर्विष्ट किसी अन्य उपबंध के अधीन लागू कर सकता हो।
4. जिस पट्टाधारी को पूर्वोक्त नोटिस दिया गया हो, यदि वह प्रसंविदाओं और करारों को भंग करते तो उस दशा में समाहर्ता, नोटिस देने के बदले उतनी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो भाग V के खंड 2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनिवार्य लगान की रकम के चार गुने से अधिक न हो।
5. **दैवी आपत के चलते पट्टा के निबंधनों का पालन न किया जाना**— इस लीज के किसी निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में लीजधारी की ओर विफलता समाहर्ता को लीजधारी के विरुद्ध कोई दावा प्रदान नहीं करेगा अथवा इस लीज का भंग नहीं समझा जाएगा, जहाँ तक उक्त समाहर्ता द्वारा ऐसी विफलता “फोर्स मेजर” से उत्पन्न विचार की जाती और यदि फोर्स मेजर के माध्यम से लीजधारी द्वारा इस लीज के किसी निबंधन और शर्त को पूरा करने में विलंब किया जाता है तो विलंब ऐसी अवधि इस लीज द्वारा नियत की गई अवधि में जोड़ दी जाएगी। इस खंड में अभिव्यक्ति “फोर्स मेजर” से अभिप्रेत है ईश्वरीय कृत्य, युद्ध, विप्लव, दंगा, सिविल कमोसन, हड़ताल, भूकंप, ज्वार, तुफान ज्वार भाटा बाढ, बिजली गिरना, विस्फोट, अग्नि तथा अन्य हादशा जिसे लीजधारी युक्तियुक्त रोक या नियंत्रित न कर सके।
6. **पट्टाधारी पट्टा की समाप्ति पर अपनी संपत्ति हटा सकेगा**— पट्टाधारी पहले इस प्रस्तुतीकरण के कारण भुगतये लगन तथा रॉयलिटी का भुगतान एवं उन्मोचित कर उक्त अवधि की समाप्ति या

पर्यवसान पर अथवा उसके बाद छह कलेन्डर माह के भीतर अपने स्वयं के लाभ के लिए सभी या किसी मशीनरी, प्लांट, भवन तथा अन्य कार्य, संरचना, प्रसुविधाओं को, जो लीजधारी द्वारा उक्त भूमि पर खड़ा किए गए, लगाये गये या रखे गये हो, और जिसे लीजधारी इस अनुसूचि इस अनुसूची के भाग VII के खंड 18 के अधीन समाहर्ता को परिदत्त करने हेतु वचनबंध न हो/ हों और जिन्हें समाहर्ता क्रय करने की इच्छा न रखता हो, हटा सकेगा।

7. **पट्टा समाप्त होने के बाद छः महीने से अधिक समय तक छोड़ दी गई सम्पत्ति का समपहरण**— यदि उक्त अवधि की समाप्ति या पर्यवसान के बाद छः कलेन्डर माह के अंत तक अथवा इस तिथि के बाद, जो इस अनुसूचि के भाग VIII के खंड-4 में अंतर्विष्ट प्रावधान के अधीन उक्त भूमि के लीजधारी द्वारा कोई मशीनरी, प्लांट, भवन, संरचना तथा अन्य कार्य, संरचना एवं प्रसुविधाएँ या अन्य संपत्ति रह जाय तो उसका विक्रय या निपटारा, इस रीति से जिसे समाहर्ता उचित समझे, बिना किसी प्रतिकर के भुगतान अथवा उसके संबंध में पट्टाधारी के किसी हिस्सा के दायित्व के, किया जा सकेगा।
8. **लोक मांग अधिनियम के अधीन वसूली**— इस पट्टा अथवा किसी विधि के किसी प्रावधान द्वारा प्राधिकृत वसूली की किसी अन्य रीति के प्रतिकूल के बिना, पट्टाधारी के विरुद्ध इसके अधीन बकाया सभी राशि बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम अथवा प्रवृत्त किसी कानूनी अधिनियम या नियमावली के अधीन लोक मांग के रूप में वसूल की जा सकेंगी।
9. **स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रत्याशित स्वामिस्व**— स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रत्याशित स्वामिस्व ..... रुपये है।
10. **प्रबंध ऐजेटों का उत्तरदायित्व**— पट्टाधारी के प्रबंध ऐजेटों पट्टाधारी के समान ही उत्तरदायी और दायित्व के अधीन होगा।
11. **सूचना की तामिला**— पट्टाधारी को इस प्रस्तुतीकरण द्वारा दिए जाने हेतु अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में उक्त भूमि पर निवास करने वाले उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसे पट्टाधारी ऐसी सूचनाएँ प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त करे और ऐसी सूचना इस पट्टा में अभिलिखित पता पर अथवा भारत में ऐसे अन्य पता पर, जिसे पट्टाधारी, समय-समय पर लिखित रूप में समाहर्ता अथवा इस निमित्त समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी को नोटिस की प्राप्ति के लिए नामित करे, लीजधारी को संबोधित पता पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दी जाएगी और प्रत्येक ऐसी तामिला इस पट्टाधारी पर उचित एवं वैध तामिला मानी जाएगी उसके द्वारा वह प्रश्नगत अथवा आक्षेपित नहीं की जाएगी। साक्ष्य के रूप में जहाँ यह प्रस्तुतीकरण उसके अधीन पूर्व लिखित दिन, माह तथा वर्ष दी गई रीति से निष्पादित की गई है।
12. **स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ डिमाइज्ड भूमि से प्रत्याशित रॉयलिटी प्रतिवर्ष** ..... रुपये है। इसके साक्ष्य में पहले उपर लिखी गई तारीख को यह विलेख इसके अधीन वर्णित रीति से निष्पादित किया गया ।
  - 1 ..... की उपस्थिति में बिहार के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से ..... द्वारा हस्ताक्षरित
  2. .... की उपस्थिति में पट्टाधारी/पट्टाधारियों के लिए उनकी ओर से ..... द्वारा हस्ताक्षरित
  - 1.
  - 2.

प्रपत्र-ग

[नियम 34(1) देखें]

खनन क्रिया परमिट के आवेदन का प्रारूप।

संख्या....., दिनांक—

सेवा में,

सक्षम पदाधिकारी,

.....

महाशय,

मैं/हमलोगों का निवेदन है कि बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के अधीन खनन क्रिया परमिट मुझे/हमलोगों को दिया जाय। आवेदन के संबंध में 5000/— रुपये फीस की राशि जमा कर दी गई है (चालान की प्रति संलग्न है)।

निम्नलिखित विशिष्टियाँ संलग्न की गई हैं :—

- (i) खनन बकाया भुगतान के अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है,
- (ii) उन रैयतों की लिखित सहमति जिनसे खनिज निकाला जाना है यदि भूमि जिससे लघु खनिज जाना है रैयती भूमि हो;
- (iii) खनिज जिसे अवेदक का खदान क्रिया करने का आशय हो;
- (iv) उस भूमि का ब्यौरा जिससे खनिज खोदकर निकाला जाएगा।

मैं/हमलोग एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं और आपके द्वारा यथापेक्षित कोई अन्य ब्यौरा पेश करने के लिए मैं/हमलोग तैयार है। मैं/हमलोग एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि इस नियमावली में यथा इंगित निर्बंधनों और शर्तों का तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किसी अन्य शर्त का पालन करूंगा/करेंगे।

आपका विश्वासभाजन

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

तथा पदनाम।

**प्रपत्र-घ**  
[नियम 33(1) देखें]

बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के अधीन लघु खनिजों के लिए निर्गत किया जाने वाले परमिट का प्रारूप।

परमिट संख्या—.....

परमिट धारक का नाम एवं पता—

परिक्षेत्र का नाम, ग्राम प्लॉट संख्या आदि	परमिट समाप्ति की तिथि	लघु खनिजों के नाम एवं विवरण	प्रयोजन जिसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा।	खनिजों के संख्या एवं मात्रा	रॉयलिटी की दर	कुल संदत्त राशि
1	2	3	4	5	6	7

मुहर

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परमिट नीचे लिखे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है :—

- (1) खनिजों को विहित समय-सीमा के भीतर हटाना होगा।
- (2) खदान क्रिया सतह से 03 मीटर गहराई अधिक स्वीकार नहीं है।
- (3) परमिट द्वारा आच्छाति भूमि के नुकसान के लिए प्रतिकर, यदि कोई हो, देना होगा।
- (4) क्षेत्र जिसकी अधिकारिता में पड़ता हो उस सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व सहमति के बिना पेड़ों को गिराना स्वीकार्य नहीं है।
- (5) सतह प्रचालन किसी सार्वजनिक निषिद्ध तथा प्रतिबंधित स्थानों पर नहीं किया जाएगा।
- (6) प्रत्येक प्रकार की दुर्घटना, तुरंत सक्षम आयुक्त को रिपोर्ट की जाएगी।
- (7) तीसरे पक्षों के दावों की क्षतिपूर्ति के लिए पक्षकार दायी होगा।
- (8) परमिट के रद्दकरण के बाद बचे खनिज सरकार जप्त हो जाएगी और वह सरकारी संपत्ति मानी जाएगी।
- (9) इस परमिट से अधिक खनिजों की कोई अधिक मात्रा को पूर्व परमिट के बिना हटाया नहीं जाएगा अन्यथा परमिट धारक बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा।
- (10) निकाले और हटाने के लिए समुचित लेखा विहित प्रारूप में संधारित किया जाएगा और मासिक रिटर्न निकालना जिस माह से संबंधित हो इसके बाद वाले माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
- (11) क्षेत्र से प्रेषित या विक्रय किए गए खनिजों के लिए विहित प्रारूप में ई0चालन निर्गत करना होगा।

**नोट:—** उपरोक्त किसी शर्त का भंग परमिट के रद्दकरण, निकाले गए खनिजों की जप्ती तथा ऐसी अन्य कार्रवाई जो आवश्यक समझी जाय, का दायी होगा।



प्रपत्र-ड.

[नियम 37(1),(2) और (3) देखें]

नाले के जल निकास/नहर/नदी के अनुरक्षण की प्रक्रिया के दौरान निकाले गए अथवा भवन/संरचना के निर्माण मरम्मती या ध्वंस के दौरान उत्पादित अथवा बाढ़ के चलते जमा/उत्पादन क्रियाकलापों के माध्यम से बिखरे हुए खनिज के निपटान के लिए खनिज निपटान परमिट देने हेतु आवेदन पत्र।

सेवा में,

जिला खनन अधिकारी,  
खान एवं भूतत्व विभाग,

.....

महाशय,

अधोहस्ताक्षरी को नाले के जल निकास/नहर/नदी के अनुरक्षण प्रक्रिया के दौरान अथवा भवन/संरचना के निर्माण या मरम्मती या ध्वंस की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित अथवा बाढ़ के चलते जमा/.....  
..... (स्थल की अवस्थिति) पर उत्पादन क्रिया-कलापों के माध्यम से बिखरे लघु खनिजों को हटाना और परिवहन करना है। अनुमोदित स्थल योजना की प्रति संलग्न है। खुदाई /मरम्मती/ध्वंस खनिज यथा..... की प्रक्रिया में उपर्युक्त विकासशील क्रिया कलापों के आनुषंगिक खनिजों को भी निकालना है। उसे स्थल पर उपभोग करने अथवा निपटाने की आवश्यकता है जिसके लिए अनुमति की याचना है।

2. उस क्षेत्र का ब्यौरा जिसके लिए अनुमति की मांग की गई है निम्नवत् दिया जाता है—

- (क) क्षेत्र की अवस्थिति;
- (ख) प्रयोजन;
- (ग) कुल क्षेत्र/बना क्षेत्र;
- (घ) लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई देते हुए खुदाई के लिए अपेक्षित क्षेत्र का विस्तार;
- (ङ) हटाए जाने वाले खनिजों की मात्रा एवं विशिष्टियाँ;
- (च) भुगतये अग्रिम रॉयलिटी।

3. आवेदक आगे अधिकथित करता है कि—

- (i) इस नियमावली के अधीन विहित दरों पर रॉयलिटी फाउन्डेशन/बेसमेंट की खुदानई के आनुषंगिक उत्खनित/संरचना के ध्वंस/ नाला/नहर नदी के अनुरक्षण/बाढ़ के चलते जमा खनिजों पर अग्रिम भुगतान की जाएगी।
- (ii) वाणिज्यिक खनन के लिए उक्त स्थल से खनिजों खोदकर निकालने के लिए खुदाई का आशय नहीं है किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित फाउन्डेशन या बेसमेन्ट के लिए संरचना के ध्वंस या विकासशील क्रियाकलापों के लिए खुदाई की आशय है।
- (iii) खोदकर निकाले गए आनुषंगी खनिजों का निपटान केवल सक्षम अधिकारी/ जिला खनन अधिकारी द्वारा यथा आपूर्ति वैध ई0चालान /परिवहन पास के निर्गमन पर होगा।

दिनांक—

अनुलग्नक—यथोक्त

आवेदक का नाम एवं पता

- (i) भू-स्वामित्व का सबूत।
- (ii) विकासशील क्रियाकलाप या भवन निर्माण/ध्वंस आदि का जिम्मा लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/मंजूरी की प्रति के साथ स्थल योजना।

## प्रपत्र-च

[नियम 37(1)(2) और (3) देखें]  
खनिज निपटान परमिट देने के लिए प्रारूप।

खनिज निपटान परमिट संख्या—....., स्थान....., दिनांक—.....,  
चूँकि श्री ..... (नाम एवं पदनाम).....(लघु खनिजों के नाम),  
ग्राम....., अंचल....., जिला..... के खेसरा.....  
..... से ..... घनमीटर/टन/घनफीट का निपटान के लिए बिहार खनिज (समानुदान अवैध  
खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 37 के अधीन आवेदन किया है और ..... रुपये  
की आवेदन फीस की राशि तथा ..... रुपये की राशि अग्रिम रॉयलिटी जमा कर दी है।

2. (ग्राम)....., अंचल....., जिला—..... में इससे उपाबद्ध  
योजना में इंगित क्षेत्र से नाले /नहर/नदी के जल-निकास के अनुरक्षण के दौरान अथवा भवन/संरचना के निर्माण  
या मरम्मत/ध्वंस की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित अथवा बाढ़ के कारण जमा/उत्पादन क्रिया कलापों के माध्यम बिखरे  
खनिजों ..... को खोदकर निकालने, संग्रह करने, हटाने तथा परिवहन की  
अनुमति एतद् द्वारा दी जाती है।

3. खनिज निपटान परमिट ..... (अवधि) से ..... तक वैध होगा।

4. खनिज निपटान परमिट निम्नलिखित शर्तों द्वारा शासित होगा, यथा—

- (क) परमिट धारक क्षेत्र से हटाए गए और परिवहन किए गए खनिजों का पूर्ण एवं सही लेखा संधारित करेगा।
- (ख) परमिट धारक उपनिदेशक/खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक अथवा समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को स्थल निरीक्षक तथा लेखा-सत्यापन करने की स्वीकृति देगा।
- (ग) 30 दिनों अथवा पूर्ण समयावधि के भीतर जैसे ही अनुज्ञा प्राप्त मात्रा का परिवहन कर दिया जाय वैसे ही संबंधित विभाग द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित जमा हुई मात्रा का पूर्ण विवरण मंजूर करने वाले प्राधिकारी को भेज देगा।
- (घ) परमिट धारक उस क्षेत्र से /खनिजों के उत्खनन अथवा हटाए जाने के लिए लागू अधिनियम तथा नियमावली के अधीन सक्षम प्राधिकारी से सभी अनुमति/ सहमति प्राप्त कर लेगा।
- (ङ०) परमिट धारक प्रत्येक माह के 15वीं तिथि तक विहित प्रपत्र में एक रिटर्न जिला खनन अधिकारी/समाहर्ता को समर्पित करेगा।
- (च) कोई अन्य शर्त, जिसे मंजूर करने वाला प्राधिकारी उचित समझे।

अनुलग्नक— परमिट के अधीन दिए गए

क्षेत्र को दर्शाने वाली योजना।

कार्यालय मुहर के साथ सक्षम  
प्राधिकारी का हस्ताक्षर।

प्रपत्र-छ

[नियम 41 देखें]

खनिज परिवहन पास/ई0चालान

खान एवं विभाग,

बिहार सरकार

चालान /पास संख्या-.....

1. वर्ष-
2. घाट /खदान की अवस्थिति-
3. घाट /खदान की जी0पी0एस0 समन्वय-
4. घाट स्वामी /बंदोबस्तीधारक का नाम-
5. बंदोबस्तीधारक की मोबाईल संख्या-
6. बंदोबस्तीधारक का पूर्ण पता-
7. लीज समाप्ति की तिथि-
8. इस चालान निर्गमन की तिथि तथा समय-
9. यह चालान ..... तक वैध है-
10. ग्राहक का नाम-
11. ग्राहक की मोबाईल संख्या-
12. खनिज का नाम-
13. खनिज का भार (मेट्रिक टन में)-
14. खनिज की मात्रा (घनफीट में)-
15. पिट हेड पर वसूली गई राशि-
16. वाहन संख्या-
17. वाहन का प्रकार-
18. चालक का नाम-
19. चालक की मोबाइल संख्या-
20. गंतव्य स्थल-

नोट :- आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से विहित प्रपत्र में अतिरिक्त प्रविष्टियाँ दर्ज की जाएंगी।

[नियम 46(1) देखें]

(लीजधारी / परमिट धारक द्वारा संधारित किया जानेवाला रजिस्टर)

1. लीजधारी / परमिट धारक का नाम और पता— .....
2. खदान लीज / परमिट का ब्योरा— .....
3. क्षेत्र— .....
4. खनिज— .....
5. खदान स्थल की अवस्थिति— .....

[illegible]

प्रपत्र-झ

मासिक रिटर्न

नियम 46(2) देखे,

(पूर्ववर्ती माह के संबंध में प्रत्येक माह की 15 वीं तिथि के पूर्व समर्पित किया जाएगा)

- (1) माह का रिटर्न-..... (माह तथा वर्ष का नाम)
  - (2) पता के साथ लीजधारी का नाम-.....
  - (3) खनन लीज का ब्यौरा- .....
    - (क) मंजूरी आदेश संख्या एवं तिथि-.....
    - (ख) लीज निष्पादन की तिथि- .....
    - (ग) खनन लीज की अवस्थिति-.....
    - (घ) खनन लीज का क्षेत्र- .....
    - (ङ०) खनन लीज की अवधि-.....
  - (4) लघु खनिज का नाम-.....
  - (5) माह के प्रथम दिन पर आरंभ स्टॉक-.....
  - (6) उत्पादित मात्रा-.....
  - (7) उपयोग की गई मात्रा-.....
  - (8) माह के अंत में बंदी स्टॉक-.....
  - (9) पीट माउथ वाल्व- .....
  - (10) खनन कार्य दिवस की संख्या-.....
  - (11) खान में कार्य रूकावट दिवसों की संख्या ऐसे रूकावट के कारण इंगित करें-.....  
.....
  - (12) किए गए कार्य मेनडेज की संख्या-.....
  - (13) औसत दैनिक नियोजन-.....
  - (14) लगाए गई मशीनरी एवं उपकरणों का ब्यौरा-.....
  - (15) मात्रा के साथ उपयोग किए गए विस्फोटकों का ब्यौरा- .....
- अभ्युक्ति -  
दिनांक-  
स्थान-

लीजधारी अथवा उसके प्राधिकृत ऐजेंट या प्रबंधक  
का मुहर के साथ हस्ताक्षर।

## प्रपत्र-ज

## वार्षिक रिटर्न

[नियम 46(3) देखें]

(पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 30वीं अप्रैल तक समर्पित किया जाएगा)

1. वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न—.....  
(01लीं अप्रैल 20... से 31वीं मार्च 20..... तथा वर्ष का नाम)
2. लीजधारी का पता के साथ नाम—.....
3. खनन लीज का ब्यौरा— .....  
(क) मंजूरी आदेश संख्या एवं तिथि—.....  
(ख) लीज निष्पादन की तिथि— .....  
(ग) खनन लीज की अवस्थिति—.....  
(घ) खनन लीज का क्षेत्र— .....  
(ङ०) खनन लीज की अवधि—.....
4. लघु खनिज का नाम—.....
5. माह के प्रथम दिन पर आरंभ स्टॉक—.....
6. वर्ष के दौरान उत्पादित मात्रा—.....
7. (क) वर्ष के दौरान उपयोग की गई मात्रा—.....  
(ख) वर्ष के दौरान प्रेषित की गई मात्रा—.....
8. वर्ष के अंत में बंद स्टॉक—.....
9. औसत पीट्स माउथ मूल्य (रूपये में)—.....
10. संदत्त रॉयलिटी (रूपये में)/किस्त की राशि—.....  
(क) चालू वर्ष के लिए—.....  
(ख) पहले का बकाया मद—.....
11. संदत्त मृत लगान (रूपये में)—.....  
(क) चालू वर्ष के लिए—.....  
(ख) पहले का बकाया दर—.....
12. वर्ष के दौरान खान कार्य दिवसों की संख्या—.....
13. वर्ष के दौरान कार्यरोक दिवसों की संख्या  
ऐसे रोक के कारण सहित —.....
14. कार्य किए गए मैनेज की संख्या—.....
15. औसत दैनिक नियोजन—.....
16. दुर्घटना, यदि कोई हो —.....
17. लगाए गई मशीनरी तथा उपकरणों का ब्यौरा—.....
18. उपयोग की गई मात्रा के साथ विस्फोटको का ब्यौरा— .....

अभ्युक्ति —

दिनांक—

स्थान—

लीजधारी अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट  
या प्रबंधक का मुहर के साथ हस्ताक्षर।

**अनुज्ञप्ति हेतु प्रपत्र-ट**

[नियम 39(1) देखें]

मेसर्स / श्री / श्रीमति..... को ..... (स्थान का नाम) .....  
....., थाना-....., जिला-..... पर लघु खनिजों स्टॉक करने हेतु व्यक्ति होना  
अनुमोदित किया जाता है और वे बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली,  
2019 के प्रावधानों का पालन करेंगे।

सक्षम पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

**प्रपत्र-ठ**  
**अपील के लिए फारम**

[नियम 67(3) देखें]

1. व्यक्ति/व्यक्तियों/फर्म अथवा कंपनी का नाम और पता-.....
2. आदेश की संख्या एवं तिथि जिसके विरुद्ध  
अपील की गई हो। सत्यापित प्रति संलग्न करनी है.....
3. प्राधिकार का पदनाम जिसने आदेश पारित किया गया हो-.....
4. (i) नियम 67 के उपनियम (1)/(2) के निर्बंधनों के अनुसार आदेश  
के संसूचन की तिथि से 60 दिनों के भीतर क्या  
अपील दाखिल की गई है-.....  
(ii) यदि नहीं तो उसका कारण-.....
5. खनिज या खनिजों के नाम जिनके लिए अपील की गई हो-.....  
.....
6. क्षेत्र का ब्यौरा जिसके संबंध में अपील की गई  
हो (उसका प्लान संलग्न करना है)-.....  
(क) ग्राम/स्थान-.....  
(ख) पोस्ट ऑफिस/थाना-.....  
(ग) पिन कोड-.....  
(घ) प्रखण्ड/अनुमंडल/जिला-.....
7. अपील के आधार- (क) .....  
(ख) .....  
(ग) .....
8. अभियोजित पक्षकार/पक्षकारों के नाम एवं पता।  
उसे/उन्हें अभियोजित किएजाने का कारण उल्लिखित करना है-.....  
.....  
.....

दिनांक-  
स्थान-

आपका विश्वासभाजन

आवेदक का हस्ताक्षर।

*The 17<sup>th</sup> September 2019*

**No.-4/V.Mu-20-93/18-3174/M**, In exercise of the powers conferred under Section 15 read with Section 23C and Section 26 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act 67 of 1957), the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules-

**BIHAR MINERALS (CONCESSION, PREVENTION OF ILLEGAL MINING, TRANSPORTATION & STORAGE) RULES, 2019**

**CHAPTER-I**

**PRELIMINARY**

**1. Short Title, Extent and Commencement.—**

- (1) These rules may be called the **BIHAR MINERALS (CONCESSION, PREVENTION OF ILLEGAL MINING, TRANSPORTATION & STORAGE) RULES, 2019**
- (2) It shall extend to the whole State of Bihar.
- (3) It shall come into force on the day of its publication in the Official Gazette.

**2. Definitions—**(1) In these Rules, unless otherwise required in the context.—

- (i) **“Act”** means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act 67 of 1957);
- (ii) **“Collector”** means the Collector-cum-District Magistrate of a district or any person appointed by the Government to exercise the powers and perform the functions of the Collector-cum- District Magistrate;
- (iii) **“Competent Officer”** means.—
  - (a) in the case of grant of quarrying permits in land notified as reserved and protected forest under the Indian Forest Act, 1927 (Central Act XVI of 1927), where the actual mining operation involved is merely removal from the surface or from a depth not exceeding five feet and to a limit of 10,000 cubic feet only, Divisional Forest Officer of the reserved and protected areas concerned, and;
  - (b) In all other cases in respect of all lands, and sub-soil including any right in mines and minerals whether discovered and whether being worked or not, the Mining Officer of the District;
- (iv) **‘Competent authority’** means the authority for exercise of such powers and carrying out of such functions as specified in these rules and shall include officer authorised by the Central Government as per the Environment Impact Assessment Notification and Environment Protection Act in case of granting Environmental Clearance;
- (v) **‘Carrier’** means any mode or conveyance of facility by which Ore/mineral is transported from one place to another and it includes mechanized device, person, animal, Cart, Boats;
- (vi) **“Department”** means the Department of Mines and Geology, Government of Bihar;
- (vii) **“Divisional Commissioner”** means the Commissioner of a Division appointed as such by the State Government;



- (viii) **“Director of Mines”** means the Director of Mines appointed as such by the State Government;
- (ix) **“Export”** means to take out of the State of Bihar otherwise than across a customs frontier as defined by the Central Government;
- (x) **“Form”** means a form set out in schedule I appended to these rules;
- (xi) **“Government”** means the State Government of Bihar;
- (xii) **“Import”** means to bring into the State of Bihar otherwise than across a customs frontier as defined by the Central Government;
- (xiii) **“Local Authority”** means a Municipal Committee, District Board or other authority legally entitled to, or entrusted, by the Government with the control or management of a municipal or local fund;
- (xiv) **“Mines Commissioner”** means the Commissioner of Mines and Geology, Bihar, or any other Officer authorized in this behalf by the State Government to perform the duties of Commissioner under these rules;
- (xv) **“Minor Minerals”** means minor minerals as defined in clause(e) of Section 3 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and includes such minor minerals as notified by the Ministry of Mines in their Notification No. SO 423(E) dated 10.02.2015;
- (xvi) **“Mineral Concession”** means a mining lease or settlement in respect of minor minerals and includes quarrying permits, permitting the mining of minor mineral(s) in accordance with the provisions of these rules;
- (xvii) **“Mineral Concession Holder/ Settlee/Lessee”** means a person(as defined in these rules) holding a valid Mineral Concession for quarrying/raising stone, sand and other minor minerals from the settled/ lease hold area and would also include the plural there of;
- (xviii) **“Mining Plan”** means a plan prepared by a Recognized Qualified Person (RQP) on behalf of Department /mineral concession holder of minor minerals and includes progressive and final mine closure plans;
- (xix) **“Mining Officer”** means the officer as mentioned under these rules;
- (xx) **“Person”** means an individual, a firm, a company, an association or body of individuals, an institution or department of the State Government or Central Government;
- (xxi) **“Prescribed”** means prescribed by these rules or guidelines;
- (xxii) **“Public Demand”** means public demand as defined under Bihar & Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (Act 4 of 1914);
- (xxiii) **“Quarrying Permit”** means a permit granted under chapter VII of these rules to extract and remove any minor minerals in specified quantities from the specified areas;

- (xxiv) **“Recognized Qualified Person”** means a person who has been notified/empanelled as such by the Department;
  - (xxv) **“Sandghat”** means a sand bearing area from where sand may be extracted and transported by means of a carrier;
  - (xxvi) **“Settlement”** means a mining right given on behalf of the Government to quarry, win, work and carry away sand and other minor mineral(s) specified therein through a competitive bidding process as notified by the State Government;
  - (xxvii) **“Schedule”** means a schedule appended to these rules;
  - (xxviii) **“Transport”** means to remove from one place to another within the State of Bihar;
  - (xxix) **“Works Department”** means departments of the Central or State Government including Company, Corporation, Undertakings, Autonomous body of the Government engaging works contractors for any kind of construction on its behalf;
  - (xxx) **“Works Contractor”** means an individual, a firm, a company, an association or body of individuals who under an agreement, with the Works Department work for the said Department.
- (2) Words and expressions used but not defined in these Rules shall have the same meaning which is assigned to them in the Act.

#### **CHAPTER-II**

#### **ESTABLISHMENT AND CONTROL**

3. **Appointment of Mines Commissioner** -The State Government may, by notification, appoint a Mines Commissioner who shall be responsible for Administration of these rules at the State level.
4. **Appointment of Director Mines.**- The State Government may, by notification, appoint a Director Mines who shall be responsible for Administration of these Rules in the field offices at the district level.
5. **Role of the Collector.**—
  - (1) The Collector of the district shall be responsible for the complete implementation of the provisions of the Act and these rules.
  - (2) The Collector shall also be competent to exercise the powers of the Mining Officer under these rules;
  - (3) The Collector shall exercise direct control and superintendence over all the Mining Officers of the district.
  - (4) The State Government may, by notification, confer the powers of the Collector to any Officer, not below the rank of Mineral Development Officer of the Mines Department or any Officer, not below the rank of Deputy Collector of the Revenue Department, with such designations, powers and duties as the State Government may think fit.
6. **Role of the Superintendent of Police**—The Superintendent of Police shall.—
  - (a) Assist the Collector in ensuring implementation of the provision of the Act and these rules;
  - (b) work under direct control and superintendence of the Collector;

- (c) enforce and implement such lawful directions of the Collector or the Director Mines or the Mines Commissioner as issued under the Act and these rules;
  - (d) Submit such reports and in such manner as the Collector or the Director Mines or the Mines Commissioner may desire.
7. **Powers and functions of the Mines Commissioner.**—The Mines Commissioner.—
  - (a) Shall exercise over all control and superintendence over all Mining Officers in the State;
  - (b) may require any Mineral Concession holder by notice to produce or caused to be produced before him such documents, accounts or other evidence which may be deemed fit;
  - (c) may suo motto call for and examine the record of any proceeding conducted by any authority, officer or person subordinate to him under the Act and these rules and if he considers that any order passed therein is erroneous or is prejudicial to the interest of revenue, mining rules and environmental conditions, pass such order as he deems fit after giving the Mineral Concession holder or the person concerned an opportunity of being heard;
  - (d) shall monitor the activities of the Mineral Concession holder and if he is prima facie satisfied that any Mineral Concession holder has violated all or any of the condition of the lease/ settlement or is not complying to any lawful direction issued by any authority, he shall direct the Collector to take legal action against the Mineral Concession Holder.
8. **Power and function of Director Mines.**—
  - (1) He shall head the Directorate of Mines and shall exercise administrative control over all Mining Officers of the Department.
  - (2) He shall be responsible for the security of all mining operations in the State. He shall also be responsible for ensuring that the interest of the State are protected and all the Mineral Concession Holder, Corporation, other licensees operate as per the provisions of the Act and these rules.
  - (3) He shall be responsible for the collection of royalty and other revenues payable.
  - (4) There may be a Directorate of Security under him which shall employ adequate personnel on either deputation or recruitment from Civil / Police Personnel or retired Defense/Para Military/ Police Personnel.
  - (5) The Directorate of Security shall function under the control and supervision of Director and shall discharge such duties as may be assigned to it by the Director.
  - (6) The structure of the Directorate of Security shall be approved by the State Government.
9. **Mining Officers at the District Level.**—All districts of the State shall have a Mining Office headed by an appropriate Mining Officer to be appointed by the State Government.
10. **Persons with Special Powers.**—The State Government may, by

notification, and in order to implement the Act and these rules, empower any Government functionary not being a Mining Officer, with powers to perform all or any of the functions of any Mining Officer under these rules, and such person shall, in exercise of these functions, be deemed to be a Mining Officer.

### **CHAPTER - III**

#### **GENERAL RESTRICTION ON UNDERTAKING MINING OPERATION**

##### **11. Prohibition of mining operation without permit or mining lease.—**

- (1) No person shall undertake any mining operation in any area, except under and in accordance with the terms and conditions of a quarrying permit or, as the case may be, a mining lease, granted under these rules;

Provided that nothing in this sub-rule shall affect any mining or quarrying operations undertaken in any area in accordance with the terms and conditions of a mining lease or quarrying permit granted before the commencement of these rules which is in force at the time of such commencement.

- (2) No quarrying permit or mining lease shall be granted otherwise than in accordance with the provisions of these rules.

##### **12. Restriction on the grant of quarrying permit or mining lease.—**

- (1) No mineral concession shall be granted in respect of any land—
- (a) to a person who is not an Indian national except with the previous approval of the Government;
  - (b) in respect of land notified by Government as reserved for the use of the Government, local authorities or for any other public or for special purposes except with the previous approval of the Government;
  - (c) in reserved and protected forest area without consulting the Divisional Forest Officer concerned;
  - (d) in respect of any land within a distance of 50 meters from any village, bridge, national highway or reservoir except with the prior approval of the State Government.
  - (e) falling within 'forest' as identified by Environment & Forest Department according to its dictionary meaning except after obtaining clearance under the Forest Conservation Act, 1980;
  - (f) falling within protected areas, such as national parks, sanctuaries, community reserves, eco sensitive zone, notified wetlands and wild life corridors;
  - (g) falling within bio-diversity heritage sites as defined under the provisions of the Biological Diversity Act, 2002 (Central Act No.18 of 2003); and
  - (h) notified by the State Government from time to time as no mining zone.
- (2) No mining lease and quarry permit shall be granted for any such minor minerals as the State Government may notify in this behalf.

Provided that such notification may be for the whole State or any part thereof.

##### **13. Boundaries below the surface.—**Boundaries of the area covered by

a mineral concession shall run vertically downwards below the surface towards the center of the earth.

14. **Maximum and Minimum area for a Mining lease/ Settlement.—**
  - (a) No person shall acquire in the State in respect of any minor mineral one or more mineral concessions covering a total area of more than 200 (Two hundred) hectares.  

Provided that in case of settlement of sand this limit shall be applicable only for rivers mentioned in clause 5(i) of Bihar Sand Mining Policy, 2019.
  - (b) The minimum area for grant of a mineral concession shall be 5 (five) hectares.
15. **Mineral concession to be in a compact block.—**No mineral concession shall be granted in respect of any area which is not compact and contiguous.
16. **Duration of mineral concessions.—**The duration of the mineral concessions for minor minerals shall be 5 years.
17. **Mining Plan.—**Each Mineral Concession Holder/Government/ Corporation as the case may be shall have to submit a Mining Plan, to the Department/Mining Officer before commencing the mining operation. Such mining plan shall be prepared by any Recognized Qualified Person.
  - (1) **Essential Factors to be considered for preparation of Mining Plan.—**  

While preparing the Mining Plan the following issues should be taken into consideration:-

    - (i) Estimated level of production.
    - (ii) Estimated level of mechanization.
    - (iii) Type of machinery to be used.
    - (iv) Estimated quantity of diesel / fuel consumption.
    - (v) Estimated number of trees to be uprooted due to mining operation.
    - (vi) Previous level of the river-bed, quarry-bed to be ascertained by RQP and stated in the plan for calculation of mineable minerals.
    - (vii) Ascertaining water level at mine-site and stating same in mine plan to avoid mining below ground water level as well as for study of ground water level.
    - (viii) In case of mining of River-bed material calculation of Annual Rate of Replenishment for Sustainability of Sand Mining as per guidelines of MoEF & CC.
    - (ix) Study to show the Annual Replenishment of sand in mining lease area being sufficient to sustain mining operations at level prescribed in the mining plan.
  - (2) **Important aspects of Mining Plan.—**The said Mining Plan shall incorporate—
    - (i) The plan of the precise area showing the nature and extent of the minor mineral reserve;
    - (ii) Spot/ spots where the excavation is proposed and its extent;
    - (iii) A detailed cross section and detailed plan of spots of proposed excavation.

- (iv) Details of the geology of the precise area including minor mineral reserves of the area.
  - (v) The extent of manual mining/ mechanised mining in the precise area.
  - (vi) Measures under Mine Closure plan -Progressive and Final Mine Closure plan.
  - (vii) Annual programme and plan for excavation in the precise area from year to year for the entire mineral concession period.
  - (viii) Tree/Plants conservation and development plan.
  - (ix) Any other matter which the State Government may require to be provided in the mining plan.
- (3) **The mining plan shall be prepared by a person who shall possess the qualification and experience as specified below.—**
- (i) a degree in mining engineering or a post-graduate degree in geology granted by a University established or incorporated by or under an Act of Parliament or State Legislature or any institution recognized by the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act No. 3 of 1956) or any qualification equivalent thereto; and
  - (ii) Professional experience of five years of working in a supervisory capacity in the field of mining after obtaining the qualification as specified in clause (i):  
 Provided that the person is empanelled with State Government or other State Government or Central Government.
- (4) **Approval and submission of Mining Plan.—**All Mineral Concession Holders or the Government/Corporation as the case may be shall submit a mining plan duly prepared by an RQP and approved by the Director or any officer / person/academic institution/Govt. agency authorized by the Department in this regard within a period of three months from the date on which communication regarding grant of mineral concession is received or such other period as may be decided/ allowed by the department for the submission of the approved mining plan.  
 Provided that in case mine plan is prepared by the department through agencies, the cost shall be realized from the concerned Mineral Concession holder/ settlee.
- (5) **Period of validity of Mining Plan.—**The mining plan, once approved shall be valid for the entire mineral concession period unless revised/modified during the mineral concession period.
- (6) **Modification of Mining Plan.—**
- (i) The Director or any person authorized in this behalf by the Department may require the holder of a mineral

- concession to make such modifications in the mining plan or impose such conditions as it considers necessary by an order in writing if such modifications or imposition of conditions are considered necessary.
- (a) In light of the experience of operation of mines.
  - (b) On account of change in the technological development.
  - (c) In light of any change in the legal provisions or the orders of any court.
- (ii) A Mineral Concession Holder, desirous of seeking modifications in the approved mining plan, shall apply to the Department or any person authorized in this behalf setting forth the intended modifications and explaining the reasons for the same.
  - (iii) The Director or any officer/ person / academic institution/ Govt. agency authorized in this behalf by the Department may approve the modification or approve with such alterations as it may consider expedient within a period of sixty days from the date of receipt of such application for modification of mining plan.
  - (iv) Where no decision is communicated within the aforesaid period of sixty days, the mining plan or modified mining plan or scheme of mining, as the case may be, shall be deemed to have been provisionally approved, till such time a final decision in the matter is communicated.
  - (v) In case of any increase in lease area or production capacity prior approval of competent authority of MoEF & CC has to be obtained.
- (7) (i) **Mine Closure Plan-** Every mine shall have Mine Closure Plan which shall be of two types –Progressive Mine Closure Plan; and Final Mine Closure Plan.
- (ii) **Submission of Progressive Mine Closure Plan.—**
    - (a) The owner, agent or manager of a mineral concession shall submit a progressive Mine Closure Plan as a component of mining plan to the officer authorized by the Department in this behalf as the case may be for approval within a period of one year from the date of grant of such mineral concession.
    - (b) The officer authorized by the Department in this behalf shall convey his approval or refusal of the progressive mine closure plan within ninety days of the date of its receipt.
    - (c) If approval or refusal of the progressive mine closure plan is not conveyed to the owner, agent or manager of the mineral concession the progressive mine closure plan shall be deemed to have been provisionally approved, and such approval shall be subject to final decision whenever communicated.

(iii) **Submission of Final Mine Closure Plan.—**

- (a) The owner, agent or manager of a mineral concession shall submit a final mine closure plan to the officer authorized by the Department in this behalf for approval one year prior to the proposed closure of the mine.
- (b) The officer authorized by the Department in this behalf shall convey his approval or refusal of the final mine closure plan within ninety days of the date of its receipt to the owner, agent or manager of the mineral concession.
- (c) If approval or refusal of the final mine closure plan is not conveyed to the owner, agent or manager of the mineral concession, the final mine closure plan shall be deemed to have been provisionally approved and such approval shall be subject to final decision whenever communicated.
- (d) The essential factors for preparation of mine plan, modified mine plan and submission of final mine closure plan shall be subject to guideline issued from time to time by the State Govt./ Central Govt.

18. **Protection of Environment.—**

- (1) Every holder of a mineral concession shall take all possible precautions for the protection of environment and control of pollution, while conducting mining operation, beneficiation, crushing or any other allied activity.
- (2) **Environmental Clearance-** All Mineral Concession Holders or the Government/Corporation as the case may be shall obtain prior environmental clearance as per the prevailing Environmental Impact Assessment notification and latest instructions issued by the Competent Authority of the Ministry of Environment and Forest, Government of India in this regard and as per the provisions of the Environment Protection Act.

Provided further that the Mineral Concession Holder shall obey and comply with such other instructions, regarding environmental protection and Environmental Clearance issued from time to time by the Government of India, State Government, Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board and the Collector of the District.

- (3) **Mining operation to be in accordance with Environmental Clearance-** All mining operations shall be in accordance with the terms and conditions laid under the environmental clearance.

19. **Contribution to the District Mineral Foundation.—**

- (1) The mineral concession holder shall deposit or make payment to the District Mineral Foundation which is created as per the District Mineral Foundation Rules at the rate prescribed by the State Government for the benefit of the persons and areas affected by mining and quarrying.



- (2) The manner in which payment is required to be made and the mode of payment shall be prescribed by the State Government in the relevant rules.
20. **Mining in the Forest Areas.—**
  - (1) The minor minerals lying inside any forest area may be settled by the Collector with the condition that the prospective Settlee brings the due permission from the Forest Department under the Forest Conservation Act, 1980.
  - (2) The formal mining lease deed shall be executed only after the required clearance from the Forest Department is received.
21. **Other Conditions.—**
  - (1) The Department may require any Mineral Concession Holder to take up environmental friendly activities and set up such modern facilities like weigh bridges, computers, offices at the mining sites or his premises.
  - (2) The Department may lay down such other conditions from time to time on the Mineral Concession Holders as it may deem fit in order to enforce the provision of the Act and these rules. These may, inter alia, include such conditions as are peculiar to a particular minor mineral or a particular geographical area.

#### **CHAPTER – IV**

#### **PROCEDURE FOR GRANT OF A MINING LEASE EXCEPT SAND**

22. Any mineral concession in the form of a mining lease shall be settled by means of public auction cum tender only through e- bidding mode and as per the procedure laid in the latest notification issued by the State Government in this regard or as decided by the State Government in this regard from time to time.
  - (1) For the purpose of grant of mineral concession by public auction cum tender the Collector shall notify the following particulars of the area, namely:-
    - (a) Toposheet No. extent of the area and boundaries.
    - (b) Name of village, Circle, Plot No. Khata No. etc.
    - (c) The period of mineral concession.
    - (d) Date of auction shall be notified before one month from the date of auction.
  - (2) Every bidder of mineral concession shall file required documents before public auction cum tender as notified by the State Government in this regard from time to time including.
    - (a) Clearance Certificate in respect of mining dues, such as royalty or dead rent and surface rent as obtained from competent officer.
    - (b) An affidavit stating that the applicant has-
      - (i) Filed up-to-date income tax return.
      - (ii) Paid the income tax assessed on his total income.
    - (c) Amount equivalent to 10[ten percent] of auction amount as security which shall be adjusted with the last installment of auction amount if the mining leaseholder is not otherwise defaulter in payment. In case of unsuccessful bidder the security deposit shall

be refunded by the Collector.

- (3) **Payment of bid amount.**—The bid amount shall be deposited in yearly basis in equal installments and each installment shall be deposited sixty days before the completion of one year from the date of execution of the lease during the first year followed by the same procedure in the consecutive years.

Provided that leases executed before the commencement of this rule shall continue to deposit yearly instalments before 31st January of every year.

Provided further that notwithstanding repugnant in these Rules or otherwise the settlee shall pay extra royalty for the quantity of mineral extracted and dispatched in excess of the quantity equivalent to bid amount.

- (4) **Default in payment.**—If any installment shall not be deposited before prescribed period, 24 percent simple interest shall be charged up to two months and after that action for cancellation shall be taken.
- (5) **Fixation of Minimum Reserve Value.**—The fixation of minimum reserve value shall be as decided by the Department from time to time.
- (6) **Failure on the part of the successful bidder.**—In case the successful bidder fails to deposit the required security deposit along with other payable taxes within the prescribed time limit as referred to in the prevailing notification of the State Government in this regard, his security deposit shall be forfeited and a fresh settlement process through public auction shall be initiated.
23. All such minerals notified by the Central Government vide notification no. SO 423(E) dated 10.02.2015 and contained in Schedule-III A shall be settled through public auction-cum-tender through e-bidding mode or as decided by the State Government in this regard from time to time.
24. **Application for grant of mining leases.**—Notwithstanding anything contained in this rules any application for grant of mining lease shall be disposed of in the following manner-
- (1) (a) A mining lease except of granite shall be granted by the Collector,
- (b) Mining lease of granite shall be granted by the State Government.
- (2) Every application for a mining lease in respect of any mineral shall be made in **Form "A"** to the competent officer or any other officer authorised by the Collector.
- (3) Every application for a mining lease shall be accompanied by a fee of Rs. 10,000/- and details of the land in respect of which the mining lease is applied for, and where so required, certified copy or copies of the relevant extracts of the record of rights.
- (4) Every application for mining lease shall be accompanied by a valid clearance certificate of payment of mining dues such as royalty or dead rent, surface rent and cess upto the end of last financial year in respect of all mineral concessions held in the State of Bihar.

- (5) Every application shall be accompanied by an affidavit stating that the applicants has-
  - (a) filed Income-Tax returns up-to-date;
  - (b) paid the Income- Tax assessed on him; and
  - (c) paid the Income-Tax on the basis of self assessment as provided in the Income-Tax Act, 1961.
- (6) Every application shall be accompanied by an affidavit showing particulars of areas mineral wise in such State, which the applicant or any person jointly with him -
  - (a) already holds under a mining lease;
  - (b) has applied for but has not been granted; and
  - (c) being applied for simultaneously.
- (7) Every application for grant of mining lease, where the land is not owned by the applicant shall be accompanied by a statement in writing that the applicant has obtained surface right over the area or has obtained the consent of the owners for starting mining operation

Provided that no such statement shall be necessary where the land is owned by the State Govt.

Provided further that consent of the raiyats/owners of the land for starting mining operations in the area or part thereof shall be furnished after execution of the lease deed but before entry into said area;

When an application for a mining lease is not accompanied by the papers specified in sub rules (2) to (7), it shall be rejected by the Competent Officer within a period of 15 days from the date of its receipt.

25. **Survey of the area.**—Survey and demarcation of the area under a mineral concession shall be done by the mineral concession holder and verification of the same shall be done by the competent authority. No mining or quarrying operation shall commence before verification of the boundaries of the applied area for grant of mining lease or quarry permit.

26. **Conditions.**—

- (1)
  - (a) Every mining lease shall be in **Form 'B'** or in a Form as near thereto as circumstances in each case may require.
  - (b) The conditions embodied in **Form 'B'** shall be deemed to be conditions imposed under this Rule and shall be binding upon the lessee.
- (2) The mineral concession holder shall erect boundary pillars at regular intervals (not exceeding twenty meters in any case) at the boundary of the lease hold area. The said boundary pillars should be made of reinforced concrete pillars of dimension of minimum one square feet and height of 1.5 meters, 1/3rd of which shall be erected below the ground. The part of the pillar above the ground shall be painted in white and black colour alternately (in zebra style) so as to render it distinctly visible.
- (3) The Collector may impose such other conditions as he deems necessary in regard to the following namely-
  - (a) The time limit, mode and place of payment of rents and royalties;

- (b) The mineral concession holder shall pay to the occupier of the surface of the land such compensation as may become payable under these rules.
  - (c) The mineral concession holder shall take such measures for planting in the same area or any other area selected by the Central or state Government not less than twice the number of trees destroyed by reasons of any mining operation or to the extent possible, the restoration of flora and other vegetation destroyed by such operation.
  - (d) The restriction of surface operations in any area prohibited by any authority;
  - (e) The notice by mineral concession holder for surface occupation;
  - (f) The provision of proper weighing machines;
  - (g) The facilities to be given by the mineral concession holder for working other minerals in the lease area or adjacent area;
  - (h) The reporting of accidents;
  - (i) The securing of pits and shafts;
  - (j) The indemnity to Government against claims of third party;
  - (k) The delivery of possession of lands and mines on the surrender, expiration or determination of the lease;
  - (l) The forfeiture of properly left after determination of the lease;
  - (m) The power to take possession of plant, machinery, premises and mines in the event of war or emergency;
  - (n) The lessee shall not pay a wage lesser than the minimum wage prescribed by the Central or State Government from time to time under the Minimum Wages Act, 1948.
- (4) The Collector, if he is of the opinion that in the interest of mineral development it is necessary so to do, may, in any case with the previous approval of the Government, impose such further conditions as he thinks fit.

**27. Application for the transfer of mineral concession.—**

1. The transferor and transferee interested in the transfer shall produce valid clearance certificate of payment of mining dues such as settlement amount, royalty, dead rent, surface rent etc.
2.
  - (a) The mineral concession holder shall not assign, sub-let, mortgage or in any other manner transfer the quarrying lease or any right, title or interest vested therein unless prior order of Collector has been obtained, to any other person.
  - (b) Every Mineral Concession Holder seeking prior order under sub-rule (1) shall make an application to the Mining Officer which shall be accompanied by a letter of consent of the owner or occupant of the land to the effect that he has no objection for quarrying minor minerals by the transferee.

- (c) Transfer of Mineral Concession shall require transfer of EC by competent authority of MoEF & CC from transferor to transferee.

28. **Execution of lease.—**

- (1) Where a mineral concession is granted under the rules the formal lease deed shall be executed by the Collector in Form “B” within 180 days of the order sanctioning the lease and if the person to whom such mineral concession has been granted fails to submit the required documents for execution within the aforesaid period the order sanctioning the lease shall be deemed to have been revoked, and in that event the application fee and the security deposit shall be forfeited.

Provided that no lease shall be executed unless the person to whom such lease has been granted submits the mining plan and environment clearances as required under these rules.

Provided further that where the Collector is satisfied that the person to whom such lease has been granted is not responsible for the delay in execution of the formal lease, he may permit the execution of the formal lease even after the expiry of the aforesaid period of 180 days.

- (2) The date of the commencement of the period for which a mineral concession is granted shall be the date on which the mining lease deed is executed under sub-rule (1) and the lessee shall be liable to pay rent/royalty from the date of the execution of the mining lease.
- (3) The lease deed has to be duly registered by paying proper stamp duty and registration fees.
- (4) No claim for extension of lease period shall be entertained for any delay.

**CHAPTER – V**

**SETTLEMENT OF SAND**

- 29 (A) **(1) Mode of Settlement.**—The settlement of sand as minor mineral shall be done by public auction-cum-tender through e-bidding mode in favour of the highest bidder by the Collector/any officer so authorised by the State Government.
- (a) The State Government shall issue a notification regarding mode & detailed procedure for settlement of sandghats from time to time as and when required.
- (b) The highest bidder shall deposit 10% of the auction amount immediately after the auction, following which an in-principle sanction order shall be issued in his favour by the Collector/ any officer so authorised by the State Government.
- (c) The highest bidder shall submit the required documents within the prescribed time limit as referred to in the prevailing notification issued by the State Government in this regard, following which the work order shall be issued in his favour by the Collector/ any Officer so authorised by the State Government.
- (d) The successful bidder or the Government/ Corporation as the case may be shall submit a mining plan prepared for the respective sandghats and shall be approved by the Director or any person / officer authorised in this regard.
- (e) The successful bidder or the Government/ Corporation as the

case may be shall obtain environmental clearance from the competent authority as per the prevailing Environmental Impact Assessment notification of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India and as per the provisions of the Environment Protection Act.

(2) **Restricted areas for sand quarrying.—**

- (i) The quarrying of sand shall be prohibited within 300 (three hundred) meters on both sides of any railway bridge or any bridge falling under any National Highway/ State Highway and shall be prohibited within 100 (one hundred) meters of both sides of any other bridge. However the prohibited zone in respect of any particular bridge may be extended by the State Government through a notification in this regard, if so required for reasons of safety.
- (ii) No quarrying shall be permitted within 50 (fifty) meters of any public place i.e. Cremation ghat or any religious place etc.
- (iii) No quarrying shall be permitted within 5 (five) meters from both banks of the river.
- (iv) The quarrying of sand shall be prohibited within 100 (one hundred) meters upstream and downstream from any dam/ weir or any other structure erected for irrigation purpose.
- (v) Sandghats should preferably be located on the river side of embankment. For low embankment less than 6 metres height, quarrying should not be done within 25 metre from toe/heel of the embankment and depth of mining should not be more than 1.00 metre. In case of higher embankments, the distance should not be less than 50 metre and depth of mining should be maximum 1.50 metre and at a distance of 75 metre or more mining depth should be maximum 2.00 metre. In order to obviate the development of flow parrallel to embankment, crossbars of width eight times the depth of mining pits spaced at 50 to 60 metres center to center should be left in the mining pits.
- (vi) The irrigation outlet shall be maintained at the same level as that of the riverbed and in no case the river bed level shall be permitted to be below the irrigation outlet level. No quarrying shall be permitted around the infiltration well/ intake well up to a distance of 5 meters.
- (vii) The extraction of sand shall be permitted only after obtaining a No Objection Certificate from the Water Resources Department in the case of rivers where from irrigation channels are out flowing.
- (viii) No quarrying of sand shall be permitted in any private land owned by any person unless the settlee obtains the consent of the concerned land owner /raiayat.
- (ix) No quarrying of sand shall be permitted in any area which the State Government notifies as a restricted area.

- (3) **Maximum depth of Sand Mining.**—The maximum depth of mining in the river bed shall not exceed 3 (three) meters measured from the unmined bed level at that point of time or the water level whichever is less. All such pits formed during the course of excavation shall be filled on a regular basis.
- (4) **Fixation of Minimum Reserve Value.**—
  - (i) The minimum reserve value shall be fixed as decided by the Department.
  - (ii) If no bidder turns up during the auction process on the fixed minimum reserve value, even after three attempts, the minimum reserve value shall be revised by the departmental technical committee on the basis of sand reserve in the concerned area, other local/ technical conditions and recommendation received from district level committee headed by Collector. A re-auction of the said reach/sand block/sand ghat shall be conducted on the basis of revised minimum reserve value after taking approval of the State Government.
- (5) **Failure on the part of the successful bidder.**—In case the successful bidder fails to deposit the required security deposit along with other payable taxes within the prescribed time limit as referred to in the prevailing notification of the State Government in this regard, his security deposit shall be forfeited and a fresh settlement process for the concerned sandghats through public auction shall be initiated.

29 B **Payment of Security Deposit.**—

- (1) Every settlee of sand as minor mineral shall deposit the amount equivalent to 10 (ten) percent of auctioned / tendered amount as security for due observance of the terms and conditions of settlement which shall be refunded after the expiry of the period of settlement / adjusted with the last installment of the settlement by the Mining Officer (as defined in the rules).
- (2) **Award of Concession and Signing of Deed.**—The successful bidder shall be awarded the concession to mine sand for a period of 5 years. The successful bidder shall execute the settlement deed in **form 'B'** as prescribed in this rule or a form as near thereto before starting work. In case the approval of mining plan and the environment clearance have not been obtained, successful bidder shall obtain the same before the execution of settlement deed.
- (3) **Mode of Payment of Royalty / Settlement Amount.**—
  - (i) The settlee shall make payment of the settlement amount as laid down in the Tender Document.
  - (ii) In case the royalty computed on annual basis for the mineral extracted exceeds the annual settlement amount, the settlee shall be liable for payment of excess royalty for the additional quantity as extracted in addition to the settlement amount.
- (4) **Default in Payment.**—In case of default in payment of any installment within prescribed date, a simple interest at the rate of 24 percent per annum shall be charged.

- 29 C. **Observance of terms & conditions of mining plan/ environmental clearance.**—The settlee shall observe the terms and conditions of the mining plan as well as the terms and conditions laid in the Environmental Clearance pertaining to the concerned settlement.
- 29 D. **Deployment of Machinery in sandghats.**—The settlee shall follow stipulations enumerated in Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016/conditions specified in Environmental Clearance.
- 29 E. **Online Sand Portal.**—The Settlee shall make sale of sand to all consumers (small, medium or large) either through online or offline mode. All transactions/payments, excavation, production / transportation, stocking details shall be captured through the departmental online real time monitoring system. Sale of sand shall be controlled by electronic documentation linked to a central documentation monitoring facility and all lessee shall upload a monthly progress report on the departmental portal without fail.
- 29 F. **Installation of Weighbridges.**—Each sandghat may have an electronic weigh-bridge, integrated with central server. However for adjacent sandghats, department may allow use of common weighbridge. Any vehicle found carrying sand without proper weighment slip/ e-challan shall be liable to be seized under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 or the rules made there under.
- 29 G. **Government's Right to undertake De-silting.**—The Government reserves the right to take up desiltation projects, in such allocated mining blocks, to maintain the river flow, safeguard the embankments and habitations along the rivers on account of geo-technical and hydrological considerations. The department shall issue guidelines for disposal of sand excavated in the process of De-silting.
- 29 H. **Removal of subsoil sand from raiyati land.**—The settlee may remove subsoil sand from raiyati land after taking consent and adequately compensating the land owner. Such proposals shall be included in mine plan and due environmental clearance from concerned competent authority of MoEF & CC has to be obtained before starting mining operations.
- 29 I. **No objection from Water Resources Department.**—In case of lifting sand from any sandghat if any natural water course / irrigation canal falls in between the link road and the sandghat then the settlee may erect temporary structure for transportation of sand with prior permission of water resources department. Such application for prior permission shall be submitted by the settlee before the concerned Chief Engineer of Water Resources Department. If no decision is communicated in this regard to the settlee within one month from the date of application then it will be deemed that the concerned Department has no objection in the proposal.
30. **Penalty In case of breach of terms.—**  
 (1) In case of mining within restricted area or mining sand beyond a depth of 3 meters, a penalty of Rs. One Lakh shall



be imposed by the Collector against the settlee for a first time violation.

- (2) For a second time violation a penalty ranging from Rs. Five lakh to rupees ten lakhs may be imposed against the settlee keeping in view the gravity of the violation.
- (3) Wherever a settlee is found indulging in such offence for the third time or more the settlement of that particular sandghat may be suspended by the Collector temporarily for a maximum period of one month until such breaches are rectified. If the breaches are not rectified in the time given by the Collector in this regard, action for cancellation of the settlement of the concerned sandghat shall be taken in extreme condition.
- (4) Transportation of sand shall be carried out through covered carriers only and no wet sand shall be loaded in carriers. The Competent Authority shall impose fine equivalent to market price of sand loaded in the said carrier for any transportation of wet sand and sand transported uncovered from the transporter.

#### **CHAPTER – VI**

##### **ROLE OF STATE OWNED MINING CORPORATION**

##### **31. Activities by the Bihar State Mining Corporation.—**

- (1) The State Government may entrust all or any of the mining activity or trade to Bihar State Mining Corporation. The Corporation may undertake, in particular, mining activity, wholesale trading, retail trading, storage, and transportation etc. of sand.
- (2) The Corporation may enter into an arrangement with any Government or semi Government or private undertaking for the said purpose.

##### **32. Corporation to buy minerals at prescribed rates.—**The Department may direct all Mineral Concession Holder to sale some proportion of their produce which should not exceed 50 % of their total produce to the corporation at pit head cost.

#### **CHAPTER – VII**

##### **PROCEDURE FOR GRANT OF QUARRYING PERMIT**

##### **33. Grant of quarrying permits.—**

- (1) On an application made to him, the Mining Officer may grant a quarrying permit in **Form “D”** to any person to extract and remove from any specified land within the limits of his jurisdiction any mineral except sand & stone not exceeding Ten thousand cubic meters in quantity under anyone permit, on pre-payment of royalty at the rates specified in Schedule III'A'. Before granting such permit, the Competent Officer shall satisfy himself that the requirement of the permit is genuine and that it does not obviate the necessity of obtaining a mining lease in the area in respect of which the permit for extraction of the mineral has been applied for.
- (2) The Mining Officer may refuse the issue of such permits for reasons to be recorded by him in writing.
- (3) The permits for extraction of ordinary earth under this rule shall not be granted for excavation beyond a depth of three

feet for areas where “sand deposits” are available below the ordinary earth/clay/soil. No raiyat can claim for any permit from any specific land already leased/ settled to anybody for mining.

- (4) The department may issue instructions for ban of granting Quarrying Permit for any particular mineral or minerals.

34. **Application for quarrying permit.—**

- (1) An application for quarrying permit shall be submitted to the Mining Officer in Form ‘C’.
- (2) Every application for quarrying permit shall be accompanied by a fee of [Rs.5,000/-]. (for Bangla Brick kiln the fee for quarrying permit shall be Rs. 500/- only).
- (3) Every application for quarrying permit shall be accompanied by a valid and up-to-date clearance certificate of payment of mining dues, if any. Every application of a quarrying permit shall, if the lands from which the minor mineral is to be extracted are raiyati lands, be accompanied by a written consent letter from the occupant of such lands to the effect that he has no objection to the extraction of the mineral by the applicant.
- (4) The application fee and royalty shall not be refunded if the raiyat subsequently refuses permission to the permit holder to work in the raiyati area.
- (5) Every application for the extension of the period of the permit shall be accompanied by a fee Rs. 1000.
- (6) The area applied for grant of quarrying permit shall be in a compact block covering not more than 5 hectares.

35. **Disposal of application for quarrying permit.—**

- (1) An application for the grant of quarrying permit shall be disposed of by the Mining Officer within 30 days from the date of its receipt.
- (2) If any application is not disposed of within the period specified in sub-rule (1), it shall be deemed to have been rejected.

36. **Conditions on which the quarrying permit shall be granted.—**

- (1) Every quarrying permit granted under rule 33(1), shall contain a condition that the depth of the pit below the surface shall not exceed 3 meters.
- (2) Any quarrying permit granted under rule 33(1) may contain such other conditions as deem necessary in regard to the following matters, namely:-
  - (a) Time limit, mode and place of payment of rents and royalties;
  - (b) Compensation for damage to the land covered by permit;
  - (c) Felling of trees in consultation with Divisional Forest Officer in case of forest areas and in consultation with the Additional Collector in other areas;
  - (d) Restriction on surface operation in any area prohibited by any authority;
  - (e) Reporting of accidents;
  - (f) Indemnity to Government against claims of third parties;

- (g) Period within which the minor mineral shall be extracted and removed and delivery of possession over lands on the expiry of such period or on the removal of the quantity of the minor mineral for which the permit is valid;
  - (h) Forfeiture of property left after cancellation of the permit; and
  - (i) Disposal of minerals in stock at site after expiry of the permit.
- (3) In case of breach of any of the conditions subject to which the permit is granted, the Mining Officer may cancel the permit issued by him. On cancellation of the permit, the quarried material lying on the land from which they are extracted shall become the absolute property of the Government and shall be sold by public auction by the Mining Officer.
- (4) The Mining Officer after enquiry and verification shall assess amount of royalty and penalty for the excess quantity at the end of the prescribed period.
- (5) Every permit holder shall obtain a prior environmental clearance as specified in Rule 18 (2).
- (6) Every permit holder shall also abide by the following conditions-
  - (i) The activity associated with mining / excavation of brick earth and ordinary clay / earth for purpose of brick manufacturing, construction of roads, embankments etc. shall not involve blasting.
  - (ii) The mining / excavation activity shall be restricted to a maximum depth of 3m below normal ground level at the site.
  - (iii) The mining / excavation activity shall be kept above the ground water table at the site.
  - (iv) The mining / excavation activity should not alter the natural drainage pattern of the area.
  - (v) The mined/ excavated pit shall be restored by the project proponent for useful purpose(s).
  - (vi) Appropriate fencing all around the mined / excavated pit shall be made to prevent any mishap.
  - (vii) Measures shall be taken to prevent dust emission by covering of mined /excavated earth during transportation.
  - (viii) Safeguard shall be adopted against health risks on account of breeding of vectors in the water bodies created due to mining/ excavation of earth.
  - (ix) Workers / labourers shall be provided with facilities for drinking water and sanitation.
  - (x) A berm shall be left from the boundary of adjoining field having a width equal to at least half the depth of proposed excavation.
  - (xi) A minimum distance of 15 m from any civil structure shall be kept from the periphery of any excavation area.
  - (xii) No mining of earth / excavation of 'brick earth' or ordinary earth shall be permitted in case the area of

mining excavation is within 1km of boundary of national parks and wild life sanctuaries:

Provided that the permit holder shall abide by any other condition imposed or any instruction issued by the Central Government / State Government in this regard."

37. (1) **Grant of Mineral Disposal Permit for mineral encountered in the process of construction of Building /Structure/Development Projects.—**

Notwithstanding anything contained in these rules, where any mineral is encountered in the process of construction of any building or a development project and has to be extracted in the process of execution of such project the Collector on a report from concerned mining officer may grant a permit for removal and use of any such minor mineral from any specified land not already leased/settled to anybody for mining. The said permission may be granted on payment of the applicable royalty and other charges to the Government in advance for the specified quantity and period not exceeding three months.

(2) **Grant of Mineral Disposal Permits for minerals excavated in the process of maintenance of Canal and Drainage System by the Department of Irrigation.—**

Notwithstanding anything contained in these rules where any silt or sand or ordinary earth or any other minor mineral is extracted in the process of maintenance and upkeep of a canal or drainage system or clearance of drains, the Collector on a report from concerned mining officer may grant a permit for removal and use of any such minor mineral. The Executive Engineer concerned shall submit an application before the concerned mining office for issue of permit for disposal of the said mineral. The said permission may be granted on payment of the applicable royalty and other charges to the Government in advance for the specified quantity and period not exceeding three months.

(3) **Permits for specific emergency situations.—**

Notwithstanding anything contained in these rules the Collector may grant permit for extraction of minor minerals from such area which has not been granted on mineral concession to such government department or any other government agency or any individual requiring mineral for execution of works relating to emergent flood protection works or any other natural calamity or other pressing circumstances for safety of human and cattle life under emergency conditions. The said permission may be granted on payment of the applicable royalty and other charges to the Government in advance for the specified quantity.

**All application under Rule 37(1), (2) & (3) shall be in Form "E" and the permits shall be granted in Form "F".**

**CHAPTER- VIII**

**REGULATION AND REVENUE COLLECTION FROM BRICK KILN**

**38. (1) Consolidation of royalty on brick earth.—**

Notwithstanding anything contained in these rules, the State Government shall determine a consolidated amount of royalty which may be revised once in three years, to be paid by the Brick Kiln owner/brick earth remover per kiln per annum as mentioned in Schedule III-B of the Rules to the State Government on a fixed number of bricks for every classified area.

Provided that the State Government may for the purposes of determining the consolidated amount of royalty to be so paid classify the place into different categories taking such facts into account which the State Government think proper.

**(2) Authorisation of Sub divisional Officer and Circle Officer to take action.—**

The Sub Divisional Officer (SDO) and Circle Officer of the area concerned shall be duly authorized to function in the manner provided under this Rule.

**(3) Grant of Quarrying permit for Brick Earth.—**

On an application made to the Mining Officer by an applicant and on submission of the required documents as prescribed in Rule 34 of these rules along with the required Environmental Clearance from competent authority as notified by MoEF & CC, a No Objection Certificate and Emission Consent order from the Bihar State Pollution Control Board and the consolidated amount of royalty as per Schedule III 'B' of the rules, He/She shall grant a quarrying permit in form 'D' for extraction and removal of brick earth in respect of any brick kiln for a particular brick season from any specified land within the limits of his jurisdiction.

**(4) Mode of Payment.—**

The brick kiln owner/brick earth remover shall pay the consolidated amount of royalty per kiln per annum as per Schedule III 'B' of the rules to the State Government for different areas within the date as prescribed for the particular brick season shown in the table below:-

<b>Sl. no.</b>	<b>Date of deposition of consolidated amount of royalty</b>	<b>Amount to be paid</b>
1.	By 30 <sup>th</sup> November	95% of consolidated royalty in one installment
2.	By 31 <sup>st</sup> December	100% of consolidated royalty in one instalment
3.	By 31 <sup>st</sup> January	105% of consolidated royalty in one instalment
4.	By 28/29 <sup>th</sup> February	110% of consolidated royalty in one instalment
5.	By 31 <sup>st</sup> March	115% of consolidated royalty in one instalment

Sl. no.	Date of deposition of consolidated amount of royalty	Amount to be paid
6.	By 30 <sup>th</sup> June	150% of consolidated royalty in one instalment
7.	After 30 <sup>th</sup> June	200% of consolidated royalty in one instalment

**(5) Action for default in payment:—**

If the brick earth remover /brick kiln owner fails to make payment of the consolidated amount of royalty in the manner so prescribed of that particular Brick season, he/she shall not be allowed to carry on the business and the competent officer or any other officer duly authorised in this behalf by the State Government shall be competent to stop such business.

**Explanation- For the purpose of this rule-**

- (a) Business means and includes laying, burning or selling of brick by brick earth remover/ brick owner and such other activities as are associated with manufacturing of bricks.
- (b) For the purpose of this rule brick earth remover means and includes person or persons by whom or on whose behalf the brick earth is removed for manufacturing bricks.
- (c) For the purpose of this rule brick kiln owner means a person who owns the bricks kiln or on whose behalf bricks are manufactured in that kiln and includes manager, agent and lessee of such person

**(6) Action for non-submission of required clearance from comp competent authority as notified by MoEF & CC-**

If the brick earth remover / brick kiln owner fails to submit the required Environmental Clearance from the competent authority as notified by MoEF & CC and / or the required Emission Consent Order from the Bihar State Pollution Control Board (BSPCB), the Competent Officer/ Sub Divisional Officer/ Circle Officer shall stop the business and report the matter to competent authority as notified by MoEF & CC/ BSPCB for initiating penal provisions for violation of rules.

**CHAPTER- IX**

**STORAGE OF MINOR /MAJOR MINERALS BEYOND LEASE HOLD AREA**

39. (1) Every person who carried business of minor/major mineral beyond any lease hold area shall obtain a stockist license from the Mining Officer in Form-K which shall be displayed at a conspicuous place of business and shall maintain proper accounts of purchase and sale of all such minerals in a register in form-H which shall be produced before the Mines Commissioner, Director of Mines, Additional Director of Mines or Deputy Director of Mines or Mining officer or any other officers authorised by the Government, for inspection. Every application for obtaining license in **Form-K** shall be accompanied with a fee of Rs. 10,000/- (Ten Thousand Rupees)

- (a) Every such license shall be valid for one calendaryear;
- (b) Every such license may be renewed on application which shall be accompanied by a fee of Rs. 2000 (Two Thousand Rupees)
- (2) Every such person as mentioned in (1) shall issue a transport challan in **Form-'G'** or in the prescribed format to every carrier, while dispatching minerals from his stock.
- (3) If any person as mentioned in (1) fails to maintain a register in **form 'H'** or obtain license in **Form 'K'** or issue a challan in **Form 'G'** or in the prescribed format, shall be punishable with simple imprisonment which may extend up to one year or value of the mineral along with a fine which may extend upto Rs 10,000/- or with both.
- (4) No person shall be permitted to erect, install or operate a stone crusher outside a lease hold area.

Provided that the existing stockist license held for stone mineral used for crusher shall remain operational till the validity of their license period, on the condition of the licensee abiding by all the relevant rules/provision of law / conditions stated in their license/ conditions stated in CTE & CTO issued by BSPCB failing which the license shall be cancelled.

Provided further that the department may allow installation of any crusher including mobile crusher within a periphery of 500 meters of the lease hold boundary to the lease holder or person directly engaged in construction activity on conditions as decided by the department.

## CHAPTER X E-REQUIREMENTS

- 40. **Usage of Electronic Procedures-** The Mines Commissioner may, by notification, require all Mineral Concession Holder or any other Stake Holder to file their returns, statements and activities electronically and undertake all or any operations through electronic mode. Government shall implement all the working system of the Department through e-office system and ultimately convert to paperless working.
- 41. **E-Challan-** The movement of all minor minerals, whether by Mineral Concession Holder or by the Corporation, shall be monitored through e-Challan in **Form G** or in the prescribed format.
- 42. **Mining MIS-**
  - (1) The Department may also require all the Mineral Concession Holder, the Corporation and other persons engaged in the transport and trade of minor minerals to come under the purview of the provision of these rules and under take their activities as per the Mining MIS system to be developed by the Department.
  - (2) The Department may lay down detailed guidelines for its MIS.

**CHAPTER -XI**  
**GRANT OF TRANSIT PASS/ CHALLAN/ E-CHALLAN FOR**  
**MOVEMENT OF MINERALS**

43. **Prohibition on Transportation-** No person shall transport or carry or cause to transport or carry any Ore/ mineral by any means from the place of raising, leasehold area or the area of stock of minerals to another place without being in possession of a valid transit pass/ challan/ E-challan in **Form-G** or in the prescribed format issued by the Competent Officer under the Rules;
44. **Restrictions on Vehicles Carrying Minerals-** The State Government may lay down reasonable restrictions on the vehicles transporting any minerals and may require them to adhere to certain specifications.  
 Provided further that the State Government may direct the owners of transport vehicles to install GPS devices or such other devices, as it may require and give such directions as it deems fit.
45. **Power to Regulate Movement of Minerals-**The Department may by notification regulate the export of mineral from State to other states. The department may set up check-post, barriers, weighbridges etc. and such other facilities to regulate the movement of minerals. If the Department considers it necessary to do so with a view to check the transport and storage of minerals transported without lawful authority, it may direct the setting up of check-post or erection of barrier or both at any place or places within the state by an order in writing.
46. **Registers, returns and Signboard.—**
- (1) Every Mineral Concession holder shall maintain Register in Form '**H**' in which day to day transaction shall be entered. He shall also have to display a signboard.
  - (2) Every Mineral Concession holder shall submit every month to the Competent Officer a true and correct return for minerals in Form '**I**' by the fifteenth day of the following month to which it relates.
  - (3) Every Mineral Concession Holder shall submit annual returns in Form "**J**" as appended to these rules before the 30<sup>th</sup> April of each year in respect of the preceding financial year.
  - (4) Every Mineral Concession holder shall give all reasonable facilities to the Mining Officer or Director of Mines or Additional Director of Mines or Deputy Director of Mines or any other Officer authorised by the Collector in this behalf to inspect, verify and check the accounts of the minerals.
  - (5) If the accounts, returns and other evidence produced by the Mineral Concession holder or any other person who has removed minerals, are in the opinion of any of the officers authorised incorrect, incomplete or unreliable either wholly, or



partly, the officer concerned, shall report to the Mining Officer who shall proceed to assess to the best of his judgment, the amount of royalty due from the assessee:

Provided that if the mining officer himself has formed the opinion he shall proceed forthwith to assess to the best of his judgment, the amount of royalty due from the assessee.

- (6) The state government in addition to accounts/ returns or other evidence may also direct to ascertain the actual quantity of mineral excavated during relevant concession period by deploying modern technology such as aerial survey/ground survey or any latest method.

## **CHAPTER -XII**

### **CANCELLATION OF MINERAL CONCESSION**

#### **47. Power to Suspend or Cancel Mineral Concession.—**

- (1) The Collector shall be competent to cancel / suspend any Mineral Concession in his district.
- (2) Subject to such restrictions as the State Government may prescribe, the Collector may suspend or cancel and forfeit the Security Deposit/Earnest Money Deposit of any mineral concession in the following circumstances after giving reasonable opportunity of being heard -
  - (a) if wrong documents have been furnished to obtain mineral concession; or
  - (b) if the mineral concession is transferred or sublet by the holder thereof; or
  - (c) if any mining revenue payable by the holder thereof is not duly paid; or
  - (d) in the event of any breach by the holder of such mineral concession by his servant or agent, or by any one acting on his behalf, with his express or implied permission, of any of the terms and conditions of such mineral concession; or
  - (e) if the holder of mineral concession or his agent or employee is convicted of an offence punishable under the Act or these Rules or any other law for the time being in force, relevant and connected with mining matters or matter relating to mining revenue or of any cognizable and non-bailable offence under any other relevant law; or
  - (f) if the purpose for which the mineral concession was granted ceases to exist; or
  - (g) if the mineral concession has been obtained through misrepresentation or fraud; or
  - (h) If the Mineral Concession Holder has violated any of the conditions mentioned in these rules; or
  - (i) If the Mineral Concession Holder fails to obtain the environmental clearance or violates any of the condition mentioned therein; or
  - (j) If the Mineral Concession Holder fails to start mining operation within three months from the date of executing deed

- (k) If, for any other reason, the Collector is prima facie satisfied, that the mineral concession is fit to be cancelled.
- (3) For any action taken under sub-rule (1), the Mineral Concession Holder shall not be eligible for any compensation or refund whatsoever.
- (4) Notwithstanding anything mentioned above, in case of detection of any violation of the Act, these rules and any other condition of the mineral concession the State Government or the Collector may, apart from cancelling the mineral concession, also impose suitable financial penalties and/or start criminal prosecution.
- (5) Any such penalties levied shall be recoverable under the Public Demand Recovery Act, 1914 (Act 4 of 1914).
48. **Power of the Collector to take over the Management.**—If any Mineral Concession Holder contravenes any provision of the Act or any rules made there under or defaults in complying with any condition imposed upon him or upon refusal to abide by such reasonable directions as the Collector may issue under these rules, or upon expiry of the mining lease period the Collector, may at any time, with or without cancellation of such mining lease—
- (1) Take over the management of such mining operations at the risk and loss of the owner of that establishment; or
  - (2) Take over the management of such establishment at the risk and loss of the owner of that establishment; or
  - (3) Transfer the establishment, for the unexpired period of the mining lease, at the risk and loss of the owner, to any other person or the Corporation.
49. **Power of Collector to Requisition Minor Minerals.**—Notwithstanding anything mentioned above, in case of any natural disaster or acute shortage or such other emergencies or in order to maintain a buffer stock, the Collector may require a Mineral Concession Holder to produce or excavate a specified quantity of the minor mineral and deliver it to such a place at such rate as he deems fit.
50. **Exit Option for Mineral Concession Holder.**—
- (1) Any Mineral Concession Holder, at any point of the Mineral Concession period, may opt to exit the business upon giving Six months' notice to the Collector. However, this option is not available to Mineral Concession Holder who have not paid their bidding amount or settlement amount or have violated any condition of settlement.
  - (2) The Collector may allow such Mineral Concession Holder to exit the business and return any security money deposited by the Mineral Concession Holder after deducting such dues as are recoverable.
  - (3) The Collector, thereupon, shall initiate arrangement for a fresh bidding.
  - (4) In case of fraud or violation of mining or environmental conditions or any other irregularities reported, no exit option will be available to the Mineral Concession Holder and their security deposit shall be forfeited.

**CHAPTER- XIII**  
**MINING REVENUE**

**51. Rent/royalty and assessment.—**

1. When a Mineral Concession is granted:-
  - (a) Dead rent shall be charged at the rates specified in Schedule II;
  - (b) Royalty shall be charged at the rates specified in Schedule III(A); and
  - (c) Surface rent shall be charged at the rate specified by the Collector from time to time for the area occupied or used by the lessee.
2. On and from the date of commencement of these rules, the provisions of sub-rule (1) shall also apply to the leases granted or renewed prior to the date of such commencement and subsisting on such date.
3. If the Mineral Concession Holder permits the working of more than one mineral in the same area, the Collector may charge separate dead rent in respect of each mineral.  
 Provided that the lessee shall be liable to pay the dead rent or royalty in respect of each mineral, whichever be higher in amount.
4. Notwithstanding anything contained in any instrument of lease the Mineral Concession Holder shall pay rent/royalty in respect of any minor mineral own, extracted and removed at the rate specified from time to time in Schedule II and III(A).
5. The State Government may, by notification in the official Gazette, amend the Schedule II, III(A) & III(B) so as to enhance or reduce the rate at which rents/royalties shall be payable in respect of any minor mineral with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette.
6. The Mining Officer, after such enquiry and verification as he may deem necessary of the monthly returns furnished by the lessee in Form "I" and Annual Return in Form "J" shall assess the amount of rent/royalty payable by the Mineral Concession Holder at the end of the prescribed period.
7. Notwithstanding anything contained in these Rules, the royalty in case of auction of the minor minerals shall be the amount of auction. In cases where the royalty on dispatched quantity exceeds the auction amount, the extra royalty for the excess quantity of mineral extracted shall also be payable.
8. The Mineral Concession Holder shall also pay all assessments and imposition whatsoever being in the nature of public demands which shall from time to time be charged, assessed or imposed by the authority of the State Govt.

**52. Single Bank Account.—**

- (1) All Mineral Concession Holder shall necessarily operate only a single bank account for all their operations connected with the said lease or the license.
- (2) The Mineral Concession Holder must necessarily give the information of the said bank account to the Collector, the Mining Officer of the district, Director Mines and the Mines Commissioner.

- (3) Any person who acts in violation of this provision shall be liable for prosecution.
53. **Power to Freeze Bank Account.**—Where the Collector, upon a report by Mining Officer has reason to believe that the bank account of any Mineral Concession Holder has to be frozen in order to protect Government revenue, he shall forthwith issue an order directing the concerned bank to freeze the bank accounts of such Settlee / licensee, till further orders.
54. **How the fees and deposit to be made.**—Any amount payable under these rules shall be paid into Treasury either through a paper challan or an electronic fund transfer.
55. The Government may, without prejudice to the provisions contained in the Act or any other rule in these rules; charge simple interest at the rate 24 percent per annum on any rent, royalty or fee or other sum due to the Government.

#### CHAPTER XIV

#### OFFENCES AND PENALTIES

56. **Penalty for unauthorized extraction and removal of minor minerals.**—

- (1) Whoever is found to be extracting or removing minor minerals or on whose behalf such extraction or removal is being made he be an agent, a manager, an employee or a contractor or a sub-lessee, otherwise than in accordance with these Rules, shall be presumed to be party to the illegal removal of the minor mineral and every such person shall be punishable with simple imprisonment which may extend upto two years or with fine, which may extend upto rupees five Lakhs or with both.
- (2) If any person in charge of any carrier while carrying mineral fails to furnish the Challan in **Form "G"** or in the prescribed format or refuses inspection of such Challan by the Director of Mines or Additional Director of Mines or Deputy Director of Mines or Mining Officer or Mining Inspector or any officer authorised by the Collector, such officer shall recover from the person in charge of the carrier the value of the mineral alongwith fine which may extend upto Rs. Ten thousand.

In case of transportation of mineral without valid challan in **Form "G"**, total value of mineral and fine which may extend upto Rs. Ten thousand shall be recovered from the person in charge of the carrier and deposited in the Govt. Head.

Provided that when the quantity of mineral loaded in carrier differs from the quantity mentioned in the challan the authorised officer shall recover value of the mineral for the difference quantity only along with fine which may extend upto Rs. Ten thousand. The quantity so assessed shall be based on actual measurement from weighbridge and not on the basis of eye estimation only.

For collection / deposition of penalties so imposed the department may issue Money Receipts to the concerned Mining Inspector/ Mineral Development Officer/Assistant Director who after realizing penalty through Money Receipts shall deposit it in State Exchequer.

- (3) Whoever removes minor mineral without valid lease/ permit or on whose behalf such removal is made otherwise than in accordance with these Rules he be an agent, Manager, contractor or a sub-lessee, shall be presumed to be a party to the illegal removal of the minor mineral and shall be liable to pay the price thereof and the Government may also recover from such person rent, royalty or taxes as the case may be, for the period during which the land was occupied by such person without any lawful authority without prejudice to other action being taken against him under these Rules or any other law for the time being in Force.
57. **Seigniorage Fee from Government Projects.—**
- (1) All the Government Departments, particularly Works Departments using any minor mineral for their schemes or projects, shall deduct a Seigniorage Fee from their suppliers or works contractors of such minor minerals.
- (2) Such Seigniorage Fee shall be at a flat rate of 10(ten) percent of the mineral value involved in the estimate and shall be deducted by the Works Department from their supplier/works contractors and deposited with the Mining Officer of the district.
- Provided that the State Government may increase or decrease the Seigniorage Fee from time to time.

58. **Sale price of Minor Minerals-**  
The sale price of minor minerals to the end user or the public shall be decided by the market forces.

#### **CHAPTER- XV**

#### **DETECTION, INVESTIGATION AND TRIAL OF OFFENCES.**

59. **Power to enter, inspect, search and seize.—**(1) For the purpose of ascertaining the position of the working, actual or prospective of any mine or abandoned mine or for any other purpose connected with these rules, any of the following Officers namely:
- (a) The Mines Commissioner, the Director Mines; or
- (b) The Collector or any other officer authorised by the Collector
- (c) Additional Director, Deputy Director, Assistant Director, Mineral Development Officer and Mining Inspectors; may,
- (i) enter and inspect any mine;
- (ii) survey and take measurements in any such mine;
- (iii) weigh, measure or take measurements of the stocks of mineral lying at any mine;
- (iv) examine any document, book, register or record in the possession or power of any person having the control of, or connected with, any mine and place, marks of identification thereon and take extracts from or make copies of such document, book, register or record;
- (v) order the production of any such document, book register as is referred in clause (iv);
- (vi) examine any person having the control of or connected with any mine;
- (vii) seize any document, sample, equipment, conveyance, animal, commodity, minor mineral, material, raw material or any other item of concern.

- (2) In case of such search and seizure, provisions of Section 100, of the Code of Criminal Procedure 1973 shall apply.
60. **Power to stop and check any carrier, transport or vessel.—**
- (1) Any of the Officers mentioned in Rule 59 may stop any carrier, vehicle or vessel carrying minor minerals, to check for verification of the contents.
- (2) In case such Officer prima facie finds that the load of the carrier, vehicle or vessel, is more than the permitted quantity and / or challan, he may require the driver of the carrier, vehicle, vessel, to take such carrier, vehicle, vessel to the nearest weighbridge and get the contents weighed at the expense of the driver or the owner of such vehicle/carrier/vessel.
- (3) If any person who refuses to obey the lawful command of such Mining Officer shall be prosecuted under these Rules.
61. **Offences cognizable upon written complaints.—**No court inferior to that of a Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under these rules and no court shall take cognizance of any offence under these rules, except upon a written complaint made in writing by the Competent Officer or Dy. Director of Mines or Additional Director of Mines or Director of Mines or any other officer empowered by the Government.
62. **Compounding of Offence.—**The competent officer may, with the approval of the Collector, compound a case instituted against any person, if instituted at his direction and complaint, on payment of such sum as may be determined payable for offence, to the credit of government.
- Provided that where a case has been instituted by the Dy. Director of Mines or Additional Director of Mines or Director of Mines or any other officer empowered by the Government may, with approval of the Commissioner, compound a case instituted against any person.
63. **Reports of Searches and Seizures.—**Every Mining Officer upon making any arrest, search or seizure shall submit a report to the Collector within twenty four hours.
64. **Special Courts.—**
- (1) In terms of power conferred under Section 30B of the Act, the State Government may, if consider necessary in the public interest, for the purposes of trial of all or any of the offences under this rule, either appoint or designate in every District of the State, Special Court(s) in consultation with the Chief Justice of the High Court.
- (2) The Special Court shall be presided over by a Special Judge who is or has been a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge under the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974).
- (3) The trial under this Act of any offence by the Special Court shall have precedence over the trial of any other case against the accused in any other Court (not being a Special Court) and shall be concluded in preference to the trial of such other case.

65. **Power to transfer cases to Regular Courts.**—Where, after taking cognizance of any offence in these rules, a Special Court is of the opinion that the offence is not triable by it, it shall, notwithstanding that it has no jurisdiction to try such offence, transfer the case for the trial of such offence to any Court having jurisdiction under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) and the Court to which the case is transferred may proceed with the trial of the offence as if it had taken cognizance of the offence.
66. **Appeal.**—Any person aggrieved by any order of the Special Court may, within sixty days from the date of order, prefer an appeal in the High Court.

#### **CHAPTER-XVI APPEALS AND REVISION**

67. **Appeals.**—
- (1) All final orders passed by Mining Officer shall be appealable to the Collector within sixty days from the date of the order.
  - (2) All final orders passed by the Collector shall be appealable to the Mines Commissioner within sixty days from the date of the order.
  - (3) All appeals shall be disposed of within three months from the date of the filing. All appeals in the rule shall be in **Form “L”**.
68. **Revision—**
- (1) The Mines Commissioner, at any time for reason to be recorded in writing, may on his own motion, and where any person aggrieved by any order passed by the Collector under these rules files an application within 60 days from the date of communication of the order, and within 75 days from the date on which an application is deemed to have been refused by the Collector, if no communication is made of such refusal, shall start a proceeding for revision of the order:  

Provided that an application for revision may be entertained even after the time specified as above if the applicant satisfies the Mines Commissioner that he had sufficient cause for not making the application within time.
  - (2) On receipt of the application and copies thereof under sub-rule (1), the Commissioner shall send a copy of the application, and where proceeding is started by him on his own motion, under sub-rule (1) he shall send notices of starting the proceeding and reasons thereof to each of the parties impleaded specifying a date on or before which he may make representation, if any, against the revision application.
  - (3) After considering the records referred to in sub-rule (2) the Mines Commissioner may confirm, modify or set aside the order or pass such other order in relation thereto as the Mines Commissioner may deem just and proper and his order shall be final.
  - (4) Pending the final disposal of an application for revision, the Mines Commissioner may, for sufficient cause, stay the execution of the order against which any revision application has been made.

**CHAPTER – XVII**  
**ENFORCEMENT**

69. **State Level Mining Task Force—** (1) There shall be constituted a State Level Mining Task Force as under:-
- |     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| (a) | Chief Secretary                                       | -Chairman          |
| (b) | Development Commissioner                              | - Member           |
| (c) | Principal Secretary Home                              | - Member           |
| (d) | DG Police   | - Member           |
| (e) | Principal Secretary, Environment and Forest           | - Member           |
| (f) | Principal Secretary, Revenue and Land Reforms         | -Member            |
| (g) | Principal Secretary, Industries                       | - Member           |
| (h) | Principal Secretary, Road Construction Department     | - Member           |
| (i) | Principal Secretary, Building Construction Department | - Member           |
| (j) | Principal Secretary, Rural Works Department           | - Member           |
| (k) | Principal Secretary, PHED                             | - Member           |
| (l) | Principal Secretary Commercial Taxes Department       | - Member           |
| (m) | Chairman State Pollution Control Board                | - Member           |
| (n) | Principal Secretary, Mines and Geology Department     | - Member           |
| (o) | Director Mines  | - Member Secretary |
- (2) The Chief Secretary may co-opt or invite any other officer or expert to attend and contribute in the meeting of the State Level Mining Task Force. Half of the Members present shall constitute the quorum.
70. **Monitoring Committee.—**The State Level Mining Task Force shall constitute a Monitoring Committee headed by the Principal Secretary of the Department of Mines and Geology with such members as it may deem fit. The Monitoring Committee shall ensure the compliance of the directions of the State Level Mining Task Force.
71. **Function of State Level Mining Task Force.—**The State Level Mining Task Force shall insure implementation of these Rules and shall monitor the excavation, trade and availability of minor minerals in the State. In addition to the above, it shall also
- (1) Provide guidance to the Department for achieving the objective of the Act and these Rules
  - (2) Frame policies and guidelines essential to implement these Rules
  - (3) Issue direction to any other Department to undertake such action as essential to achieve the objective of the Act and these Rules.
  - (4) Shall ensure that the mining activity is undertaken as per the environmental safeguards laid down by the Ministry of Environment Forest and Climate Change.
72. **Divisional Level Mining Task Force.—**
- (1) There shall be constituted a Divisional Level Mining Task Force as under :-
 

(a)	Divisional Commissioner	- Chairman
(b)	Divisional Commissioners of the Bordering Divisions	-Co-Chairmen
(c)	DIG Police of the Division.	
(d)	DIG Police of the Bordering Divisions	



- (e) The Conservator of Forest
  - (f) All Collectors of the Division
  - (g) All SPs of the Division
  - (h) All DFOs of the Division
  - (i) All Mining Officers of the Division
  - (j) Secretary to the Divisional Commissioner—Member Secretary
- (2) Additionally, the Divisional Commissioner may co-opt such additional members as he may deem fit. The Divisional Commissioner may also invite the Collectors and the SPs of the districts who share boundaries with the Division.
- (3) Half of the Members present shall constitute the quorum.
- (4) It shall meet once in a month.
73. **Function of the Divisional Level Mining Task Force.**—The Divisional Level Mining Task Force shall insure implementation of these rules and shall monitor the excavation, trade and availability of minor minerals in the Division. In addition to the above, it shall also –
  - (1) Ensure the inter-district coordination between the districts of the Division and the bordering districts of Division.
  - (2) Prepare and launch coordinated action plan to check illegal mining and illegal transportation of minor minerals across districts and districts outside the Division.
74. **District Level Mining Task Force.**—
  - (1) There shall be a constituted a District Level Mining Task Force as under:
    - (a) Collector– Chairman
    - (b) Superintendent of Police
    - (c) All Sub Divisional Officers
    - (d) All Sub Divisional Police Officers
    - (e) Divisional Forest Officer
    - (f) Executive Engineer, RCD, BCD, PHED and Rural Works Department
    - (g) District Transport Officer
    - (h) District Mining Officer – Member Secretary
  - (2) The Collector may co-opt or invite any other Officer or expert to attend and contribute in the meeting of the District Level Mining Task Force.
  - (3) Half of the Members present shall constitute the quorum.
  - (4) It shall necessarily meet once a month and at earlier frequencies as directed by the Department.
75. **Function of the District Level Mining Task Force.**—The District Level Mining Task Force shall insure implementation of these rules and shall monitor the excavation, trade and availability of minor minerals in the district. In addition to the above, it shall also
  - (1) ensure that all the mining activity is carried on as per the condition of the mining lease.
  - (2) ensure that no illegal mining, illegal transportation, over loading, hoarding and black marketing of minor mineral is carried on.
  - (3) all the retail business of minor minerals are carried out as per the provision in these rules.
  - (4) issue direction to any other Department to undertake such

action as essential to achieve the objective of the Act and these Rules.

- (5) Shall ensure that the mining activity is undertaken as per the environmental safeguard laid down by the Ministry of Environment Forest and Climate Change.

#### **CHAPTER- XVIII EXEMPTIONS**

76. **Power of State Government to exempt minor minerals from the provisions of these Rules.**—The State Government may, by notification, either wholly or partially, and subject to such conditions (if any) as it may think fit to prescribe, exempt any minor mineral from all or any of the provisions of these rules, either throughout the State or any specified area of the State, for any specified period or occasion or for any specified class of persons and for such purposes.

77. **Power of Government to relax the operation of any provision of these Rules.**—

- (1) State Government may, relax the operation of one or more of the provisions of these Rules if, in the opinion of the Government, such relaxation is necessary in public interest.
- (2) Notwithstanding anything contained in these rules, the State Government, in such case as it deems proper in public interest, may grant a mining lease/mining settlement and may also authorize the grant of a quarrying permit or movement permit to any person on terms and conditions other than those prescribed in these rules for reasons to be recorded in writing:

Provided that the State Government may grant a mining lease/settlement/in any area under its jurisdiction to any Government Department or State owned Corporation on terms and conditions other than those prescribed in these Rules.

78. **Mining Lease etc to any Works Department.**—]

- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the State Government may grant license/lease to any Works Department for any particular project in a specific number of districts for specific period of time.
- (2) The said Works Department shall have to pay the due royalty and such other fee as applicable under these rules.

#### **CHAPTER XIX MISCELLANEOUS**

79. **Power to rectify apparent errors**—Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Government or any other authority or Officer under these rules and any error arising therein from accidental slip or omissions, may within two years from the date of the order, be corrected by the Government authority or the Officer, as the case may be:

Provided that no order prejudicial to any person shall be passed unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.

80. **Submission of copy of lease.**— Every person holding a mining lease or sub-lease from a private person or before the commencement of these rules, shall submit to the Mining Officer in whose jurisdiction the area or areas covered by such lease or sub-lease is or are situated a certified or true copy of the lease or sub-lease.

81. **Interpretation of mining lease.**—Every lease shall provide for submission by the lessee of any question of dispute regarding the lease or any other matter or thing, construction of a term or condition in the lease or anything connected with the mining of minor minerals specified in the lease, or the working or non- working of the mine or the quarry, and the amount of royalty or dead rent or its mode of payment to the Mining Officer, for the decision of the Collector, which shall be final and binding on the lessee.
82. **Mode of realization of rents, royalties and penalty.**—The amounts of rent, royalty or penalty payable under these rules, shall be recoverable as a public demand under the Bihar Public Demands Recovery Act, 1914.
83. **Payment of compensation to owner of surface rights etc.—**
  - (1) The holder of a mineral concession shall be liable to pay to the occupier of the surface of the land over which he holds the mineral concession, such annual compensation as may be determined by the Collector.
  - (2) In case of agricultural land the amount of annual compensation shall be worked out on the basis of the average annual net income for the cultivation of similar land for the previous 3 years.
  - (3) In case of non-agricultural land, the amount of annual compensation shall be worked out on the basis of average annual letting value of similar land for the previous three years;
  - (4) The annual compensation referred to in sub-rule (1) shall be payable on or before such date as may be specified by the Collector.
84. **Power to issue directions.—**
  - (1) The Department may, in the interest of systematic development of mineral deposits, conservation of minerals, scientific mining, sustainable development and protection of the environment, issue direction to the owner, agent or manager of the mining lease/settlement.
  - (2) Every direction issued under sub-rule (1) shall be complied by the owner, agent or manager of the mining lease/ settlement as the case may be, who in case of any difficulty in giving effect to any such direction, may apply for modification or rescinding of such direction and the officer so authorized by the Department in this regard, may either modify or rescind the direction or confirm the same.
85. **Officers to be Public Servants.—**
  - (1) All Officers and persons empowered to exercise any powers or to perform any functions under the Act or these rules shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860).
  - (2) No suit shall lie in any Civil Court against the State Government or any Mining Officer for damages for any act done in good faith or ordered to be done in pursuance of the Act or these rules or of any other law for the time being in force relating to the Mining Revenue.

- (3) No Civil Court shall try any suit against the State Government in respect of anything done, or alleged to have been done, in pursuance of these rules, and except with the previous sanction of the State Government, no Magistrate shall take cognizance of any charge made against any Mining Officer under these rules or made against any other person under these rules.
86. **Protection of action taken in good faith.**—No suit, Prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this rules.
87. **Orders to remain in Force.**—Every Order, Notification, Rule or Regulation which was made under the Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 (as amended from time to time), the Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2003, Bihar Minor Mineral Rules, 2017 or by the Mines Commissioner, the Collector, the Board Of Revenue or any other Mining Officer appointed under those Rules relating to the matter of Mining and which was in force immediately before the expiration thereof shall, in so far as such order or notification or rule or regulation is not inconsistent with the provisions of the Act and these rules, be deemed to continue in force and to have been made under the Act and these rules.
88. **Repeal and Savings.**—
- (1) The Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 (as amended from time to time), the Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2003 and Bihar Minor Mineral Rules, 2017 are hereby *repealed*.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said rules shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Act and these rules.
- (3) All references in any provisions of the rules so repealed shall be construed as references to the corresponding provisions of these rules.
- (4) All proceedings (including proceedings by way of investigations) pending before any Officer, Authority or Court, immediately before the commencement of these rules shall, on such commencement, be deemed to be proceedings pending before it as per these rules and shall continue to be dealt with accordingly.
89. **Power to remove difficulty.**— If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions as it deems necessary or expedient for removing the difficulty.
90. **Laying of Rules.**—
- These rules, as soon as they are promulgated, shall be laid before each house of the State Legislature.

**By the Order of Governor of Bihar.**  
**SUSHIL KUMAR,**  
**Under Secretary to the Government of Bihar.**

Schedule-I  
[See Rule 2(x)]

1	Application for Mining Lease	Form A
2	Mining Lease Deed	Form B
3	Application for Quarrying permit	Form C
4	Quarry Permit	Form D
5	Application for the grant of Mineral Disposal Permit	Form E
6	Form for grant of Mineral Disposal Permit	Form F
7	Format of E Challan	Form G
8	Register to be maintained by the Lessee/Permit Holder	Form H
9	Monthly Returns	Form I
10	Annual Returns	Form J
11	Stockist License	Form K
12	Form for Appeal	Form L

Schedule-II  
[See Rule 51(1)(a) ]  
Dead Rent

Period	Rate of Dead Rent (in Rs.)
1	2
Rate per year for entire period of lease	50,000.00 per acre per year

Schedule-III A  
[See Rule 51(1)(b) ]

Sr. No.	Royalty Name of Minerals	Rate Per Cubic meter in Rupees
1	2	3
1	(a) Boulder, Gravel, shingle or stone as defined by name whichever (b) Stone settled by way of auction	150.00 In case of auction the amount of auction
2	(a) Ordinary sand used for construction purpose (b) Ordinary sand of auctioned ghats	75.00 In case of auction the amount of auction
3	Brick earth (equivalent to 400 standard bricks)	18.00
4	Ordinary Earth/Clay which is used for filling or levelling purposes in construction of embankment, Roads, Railways. Building etc. and for other commercial works.	33.00
5	Lime shell, Lime stone and kankar used in	165.00

Sr. No.	Royalty Name of Minerals	Rate Per Cubic meter in Rupees
1	2	3
	kilns for manufacturing of lime used as a construction material and Lime shell used for manufacture of buttons.	
6	Murram	83.00
7	Chalcedony Pebbles used for Ball Mill purpose only	95.00
8	Granduler Earth	83.00
9	Quartzite used for the purpose of building construction or for making road	150.00
10	Reh Mitti	34.00
11	Saltpetre	38.00
12	Slate and Shell when used for making building material	110.00
13	Fullers Earth	124.00
14	Stone used for making household utensils including grinding stone	95.00
15	Stone sets and Stone Bricks per hundred	95.00
16	Stone dust	30.00
17	Granite (in case of use for decorating stone) per hundred	
	(i) Block more than 60 c.m.	709.00
	(ii) Block less than 60 c.m.	355.00
18	Quartz;	30 % of the sale price on ad valorem basis.
19	Sand (others);	
20	Silica Sand;	
21	Steatite or Talc or Soapstone.	
22	Agate;	
23	Ball Clay;	
24	Barytes;	
25	Calcareous Sand;	
26	Calcite;	
27	Chalk;	
28	China Clay;	
29	Clay (others);	
30	Corundum;	
31	Diaspore;	
32	Dolomite;	
33	Dunite or pyroxenite;	
34	Felsite;	
35	Felspar;	
36	Fireclay;	

Sr. No.	Royalty Name of Minerals	Rate Per Cubic meter in Rupees
1	2	3
37	Fushite Quartzite;	
38	Gypsum;	
39	Jasper;	
40	Kaolin ;	
41	Laterite;	
42	Mica;	
43	Ochre;	
44	Pyrophyllite;	
45	All other minerals	

Note.- (I) Notwithstanding anything contained repugnant Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019 or otherwise, the settlee shall pay extra Royalty for the excess quantity of extracted and dispatched stone more than the equivalent auction amount.

Note.- (II) The settlee shall pay extra Royalty for the excess quantity of extracted and dispatched sand more than the equivalent auction amount.

Note.- (III) No royalty for non-commercial use of ordinary earth shall be levied.

Schedule III- B  
[See Rule 38 (1)]

In exercise of the powers conferred by Rule 38 (1) of the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019 and having regard to location, population, state of Civil Construction, state of Industrial Construction, state of Urbanisation and place of industrial growth in different areas of the State, the Governor of Bihar is pleased to reclassify such areas to determine the number of bricks per fixed kiln and Bangla Bhatta and consolidated amount of royalty to be paid thereon by brick kiln owner/ brick earth remover per kiln per annum to the State Government for different areas as shown in the table below :-

**TABLE**

Sl. no.	Categories of area	Name of district and area	Capacity- fixed no. for the manufactured brick for fixed kiln and Bangla Bhatta situated in areas shown in column 3	Royalty- amount of royalty payable per kiln per annum on number of brick fixed in column 4 (in Rupees)
1	2	3	4	5
1.	I	Urban areas of Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur, Gaya, Darbhanga, districts	45 Lakhs bricks	Rs.2,02,500.00
2.	II	Other Urban areas	35 Lakhs Bricks	Rs.1,57,500.00
3.	III	Rural Areas	25 Lakhs Bricks	Rs.1,12,500.00
4.	IV	Bangla Bhatta	01(One Lakh) Bricks	Rs. 4,500.00

Note:- (I) "Urban area" means the areas within the local limits of Municipality or Municipal Corporation or Notified area Committee and also includes the area falling within 4 Kms. outside the boundary limits of such Municipal Corporation or Municipality or Notified area Committee as the case may be;

Note :- (II) No royalty shall be payable on brick/brick earth manufactured in Bangla Bhatta for non-commercial, Personal consumption.



**FORM A.**

[See Rule 24 (2)]

Form of application for Mining Lease for Minor Minerals.

Dated.....day of.....20

To,

The Collector,

.....

Sir,

I/We have the honour to apply for the  
grant of Mining Lease under the Bihar  
Minerals (Concession, Prevention of Illegal  
Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019.

Received.....on.....(Dated).....(Initial)

A sum of Rs.....being the fee in respect of this application payable  
under rule 24 (3) of the said rules has been deposited in .....(name of  
treasury or branch of the State Bank of India doing the treasury business) and the  
relevant challan is attached herewith.

The required particulars are given below:

**Particulars**

1. Name of individuals, firm or company applying.
2. Nationality of individuals or place of registration of incorporation of firm or company.
3. Profession of individuals or nature of business of firm or company and place of business.
4. Address of the individuals, firm or company.
5. Mineral or minerals which the applicant intends to mine.
6. Period for which the mining lease is required-
7. Details of area in respect of which lease is required-  
(i) District, (ii) Revenue thana, (iii) Village/Mouza, (iv) J.L. no., (v) Plot nos., (vi) Total area.
8. Particulars of map or plan on 16"= 1 Kilometre scale, covering the area mentioned at 7 above, attached. It shall give sufficient information to enable identification of the area in respect of which the lease is required.

9. Brief description of the area.
10. Area and minerals within the jurisdiction of the State Government for which the applicant or any person joint in the interest

with him-

: Mineral ..... Area

: Taluk ..... District

- (a) already holds a lease (s);
- (b) has already applied for but not been granted a lease; or
- (c) has applied simultaneously.
11. Nature of joint interest, if any under 10 above.
12. Approximate quantity of minerals expected to be raised during the first year.
13. Means by which the minerals are to be raised, i.e. by handlabour or mechanical or electrical power and the degree of mechanisation if any contemplated.
14. The amount of money proposed to be invested.
15. Past experience of the applicant in the profession of mining.
16. Manner in which the mineral raised is to be utilised, expected consumers and places of consumption of the mineral.
17. Any other particulars which the applicant wishes to furnish or which the Collector may ask for.
18. Manner and details of payment of the application fee prescribed in these rules.

(**Note.**-The fee to be paid to the credit of the State Government under the head.....)

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details, including accurate plan and security deposit, etc. as required by you before the grant of the lease.

Yours faithfully.

Signature and designation of the  
Applicant

Place.....  
Date.....

**FORM B**  
[See rule 26(1)]

**MODEL FORM OF MINING LEASE FOR MINOR MINERAL**

THIS INDENTURE made this ..... day of ..... 20.....between the Governor

of BIHAR (hereinafter referred to as the “State Government” which expression shall where the context so admits be deemed to include his successors in office and assigns)  
**OF THE ONE PART AND**

**When the lessee is an individual** ..... (Name of person) ;Son of ..... (Address and occupation) ( hereinafter referred to as “the lessee” which expression shall where the context so admits be deemed to include his respective heirs, executors, administrators, and representatives and permitted assigns.)

**When the lessees are more than one individual** ..... (Name of person with address and occupation) and .....(Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as “the lessees” which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns).

**When the lessee is a registered firm or syndicate** ..... (Name and address of partner), son of .....  
.....son of ..... all carrying on business in partnership, under the firm name and style of..... (Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act,1932 (9 of 1932) and having their registered office at ..... in the town of .....(hereinafter referred to as “the lessee” which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives andpermitted assigns)

**When the lessee is registered company** ..... (Name of company) a company registered under..... (Act under which incorporated) and having its registered office at ..... (Address) (hereinafter referred to as “the lessee” which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns), **OF THE OTHER PART.**

WHEREAS THE lessee/lessees has/have applied to Government of Bihar (hereinafter referred to as the ‘State Government’) for a mining lease for .....(Name of Mineral) in accordance with the Bihar Minor Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019 (hereinafter referred to as the said Rules) in respect of the lands described in Part I of the Schedule hereunder written and has/have deposited with the State Government the sum of Rs. .... as security.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in consideration of the rents and royalties, covenants and agreements by and in these presents and the said schedule hereunder written reserved and contained and on the part of the lessee to be paid, observed and performed the State Government both hereby grant and demise unto the lessee/ lessees. All those this mines beds/veins seams of stone [here state the “Minerals”] (hereinafter and in the said schedule referred to as the said “minerals”) situated lying and being in or under the land mentioned and described in part I of the said schedule, together with the, liberties, powers and privileges to be exercised on or enjoyed in connection herewith which are mentioned in part II of the said schedule subject to the restrictions and conditions as to the exercise and enjoyment of such liberties, powers, and privileges which are mentioned in part III of the said schedule Except and reserving out of this demise unto the State Government the liberties, powers and privilege mentioned in part IV of the said Schedule To Hold the premises hereby granted and demised unto the lessee-from the day ..... 20... for the term of five years thence next ensuing Yielding and paying therefor unto the State Government the several rents and royalties mentioned in part V of the said schedule at the respective time therein specified

subject to the provisions contained in part VI of the said schedule And the lessee/lessees hereby covenant/covenants with the State Government as in part VII of the said schedule is expressed and the State Government hereby covenants with the lessee as in part VIII of the said schedule is expressed AND it is hereby mutually agreed between the parties hereto as in part IX of the said schedule is expressed.

In witness whereof these presents have been executed in manner hereunder appearing the day and year first above written.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in manner hereunder appearing the day and year first above written.

The Schedule above referred to.

### **PART-I THE AREA OF THIS LEASE**

**Location and area of the lease:**

All that tract of lands situated at ..... (Description of area or areas)  
in the Registration District of ..... Sub-Division..... and  
Thana.....bearing cadastral Survey Nos. ....containing an area of  
..... or there abouts delineated on the plan here to annexed and thereon marked with  
lines/coloured ..... and bounded as follows:-

On the North by .....

On the South by .....

On the East by .....

And

On the West by .....

hereinafter referred to as “ the said lands”.

### **PART-II**

#### **LIBERTIES, POWERS AND PRIVILEGES TO BE EXERCISED AND ENJOYED BY THE LESSEE/LESSEES SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND CONDITIONS IN PART III.**

1. ***To enter upon land & search for, win, work etc.***— Liberty and power at all times during the term hereby demised to enter upon the said lands and to search for, mine, bore, dig, drill for, win, work, dress, process, convert, carry away and dispose of the said mineral/minerals.
2. ***To sink, drive and make pits, shafts, and inclines etc.***— Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to sink, drive, make, maintain and use in the said lands any pits, shafts, inclines drifts, levels, waterways, airways and other works (and to use, maintain, deepen or extend any existing works of the like nature in the said lands).
3. ***To bring and use machinery, equipments etc.***— Liberty and power for or in connection with any of the purpose mentioned in this part to erect, construct, maintain and use on or under the said lands any engines, machinery, plant, dressing floors, furnaces, coke ovens, brick-kilns, workshops, store houses, bungalows, godowns, sheds and other buildings and other works and conveniences of the like nature on or under the said lands.
4. ***To make roads and ways etc. and use existing roads and ways.***— Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to make any tramways, railways, aircraft landing grounds and other ways in or over the said lands and to use, maintain and go, and repass with or without horses, cattle, wagons, aircrafts, locomotives or other vehicles over the same (or any existing tramways, railways, roads and other ways in or over the said lands) on such conditions as may be agreed to.
5. ***To use water from streams etc.***— Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part but subject to the right of any existing or future lessees and with the written permission of the Collector to

appropriate and use water from any streams, water-courses, springs or other sources in or upon the said lands, to step up or dam any such stream or water course and collect or impound any such water and to make, construct and maintain any water course culverts, drains or reservoirs but not as so to deprive any cultivated lands, villages, buildings or watering places for livestock of a reasonable supply of water as before accustomed or in any way to foul or pollute any stream or springs. Provided that the lessee/lessees shall not interfere with the navigation in any navigable stream nor shall divert such stream without the previous written permission of the State Government.

6. ***To use land for stacking, heaping or depositing purpose.***—Liberty and power to enter upon and use a sufficient part of the surface of the said lands for the purpose of stacking, heaping, storing or depositing therein any produce of the mines or works carried on and any tools, equipment, earth and materials and substances dug or raised under the liberties and powers mentioned in this part.
7. ***Beneficiation and conveying away of production.***—Liberty and power to enter upon and use a sufficient part of the said lands to beneficiate any mineral produced from the said lands and to carry away such beneficiated mineral.
8. ***To clear brushwood and to fell and utilize trees, etc.***—Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part and subject to the existing rights of others and save as provided that Collector may ask the lessee/lessees to pay for any tree or timber felled and utilized by him/them at the rates specified by the Collector.

#### **PART-III**

#### **RESTRICTIONS AND CONDITIONS AS TO THE EXERCISE OF THE LIBERTIES, POWERS AND PRIVILEGES IN PART-II.**

1. ***No building etc. upon certain places.***—No building etc. shall be erected, set up or placed and no surface operations shall be carried on in or upon any public pleasure ground, burning or burial ground, or place held sacred by any class of persons or any house or village site, public road, or other place which the State Government may determine as public ground or in such a manner as to injure or prejudicially affect any buildings, works, property or rights of other persons and no land shall be used for surface operations which is already occupied by persons other than the State Government for works or purpose not included in this lease. The lessee/lessees shall not also interfere with any right of way, well or tank.
2. ***Permission for surface operations in a land not already in use.***—Before using for surface operations any land which has not already been used for such operations, the lessee/lessees shall give to the Collector of the District two calendar months previous notice in writing specifying the name or other description of the situation and the extent of the land proposed to be so used and the purpose for which the same is required and the said land shall not be so used if objection is issued by the Collector within two months after the receipt by him of such notice unless the objections so stated shall on reference to the State Government be annulled or waived.
3. ***To cut trees in unreserved lands.***—The lessee/lessees shall not, without the express sanction of the Collector, cut down or injure any timber or trees on the said lands but may without such sanction clear away any brushwood or under growth which interferes with any operations authorised by these presents. The Collector may require the lessee/lessees to pay for any tree or timber felled and utilized by him/them at the rates specified by the State Government in Forest and Environment Department.
4. ***Not to enter upon reserved forests.***—Notwithstanding anything contained in this Schedule the lessee/lessees shall not enter upon any reserved forest included

in the said lands or fell, cut and use any timber or trees.

5. ***No mining operations within 50 meters of public works etc .***—The lessee/lessees shall not work or carry on or allow to be worked or carried on any mining operations at or to any point within a distance of 50 meters from any railway line except with the previous written permission of the Railway Administration concerned or under or beneath any rope way or any ropeway trestle or station, except under and in accordance with the written permission of the authority owning the ropeway or from any reservoir, canal or other public works such as public roads and buildings or inhabited site except with the previous written permission of the Collector or any other officer authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such instructions, restrictions and conditions, either general or special, which may be attached to such permission. The said distance of 50 meters shall be measured in the case of railway, reservoir or canal horizontally from the outer toe of the bank or the outer edge of the cutting as the case may be and in case of a building horizontally from the plinth thereof. In the case of village roads no working shall be carried on within a distance of 10 meters of the outer edge of the cutting except with the previous permission of the Collector or any other officer duly authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such directions, restrictions and additions, either general or special, which may be attached to such permission.

**Explanation.**—For the purpose of the clause the expression Railway Administration shall have the same meaning as it is defined to have in the Indian Railway Act, 1890 by clause (6) of section 3 of that Act. 'Public Road' shall mean a road which has been constructed by artificially surfaced as distinct from a track resulting from repeated use. Village road will include any track shown in the Revenue record as village road.

6. ***Facilities for adjoining Government licenses and leases.***—The lessee/lessees shall allow existing and future holders of Government licenses or leases over any land which is comprised in or adjoins or reached or is reached by the land held by the lessee/lessees reasonable facilities of access thereto:

PROVIDED THAT no substantial hindrance or interference shall be caused by such holders of licenses or leases to the operations of the lessee/lessees under these presents and fair compensation (as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement, as may be decided by the State Government) shall be made to the lessee/lessees for loss or damage sustained by the lessee/lessees by reason of the exercise of this liberty.

#### PART-IV

### LIBERTIES, POWER AND PRIVILEGES RESERVED TO THE STATE GOVERNMENT.

1. ***To work other minerals.***— Liberty and power for the State Government, or to any lessee or persons authorised by it in that behalf to enter into and upon the said lands and to search for, win, work, dig, get, raise, dress, process, convert and carry away minerals other than the said minerals and any other substances and for those purposes to sink, drive, make erect, construct, maintain and use such pits, shafts, inclines, drifts, levels and other lines, waterways, airways, water courses, drains, reservoirs, engines, machinery, plant, buildings, canals, tramways, railways, roadways and other works and conveniences as may be deemed necessary or convenient.

PROVIDED THAT in the exercise of such liberty and power no substantial hindrance or interference shall be caused to or with the liberties powers and privileges of the lessee/lessees under these presents and that fair compensation (as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government) shall be made to the

lessee/lessees for all loss or damage sustained by the lessee/lessees by reasons or in consequence of the exercise of such liberty and power.

2. ***To make railway lines and roads, etc.***— Liberty and power for the State Government or any lessee or person authorized by it on that behalf to enter into and upon the said lands and to make upon over or through the same any railways, tramways, roadways, electric lines, telephone lines or pipelines for any purpose other than those mentioned in part II of these presents and to get from the said land stoned, gravel, earth and other materials for making, maintaining and repairing such railways, tramway and roads or and existing railways, tramways, and roads and to go and repass at all times with or without horses, cattle or other animals, carts, wagons, carriages, truck, cars, locomotives or the vehicles over or along any such railways, roads, line and other ways for all purposes and occasions may require provided that in the exercise of such liberty and power by such other lessee or person no substantial hindrance or interference shall be caused to or with the liberties, powers and privileges of the lessee for all loss or damage sustained by the lessee by reason or in consequence of the exercise by such lessee or person of such liberty and power, subject to the provision that no compensation shall be deemed to be payable where only electric lines or telephone or similar lines are carried in or over the lands under lease.
3. **Lease by mistake.**—The lessee shall have no claim against the State Government for compensation or damage in respect of land having been included in this lease which already been included in some previous lease but that the lessee shall be entitled to proportionate reduction of the assessment in respect of any land covered by the lease which may subsequently be discovered not to have been available for lease.
4. **Action in case of occurrence of valuable Mineral.**—In case there are reasons to believe at any time that valuable mineral or minerals exist along with the mineral for which this lease is being granted the Collector may issue such order for the compliance of the lessee as the Collector may think proper for dumping of the tailings or screened rejects of the mineral to treated or treatment of the mineral to which this lease is being granted. The granting of this lease to the lessee will always be without prejudice to the right of the Collector to terminate the lease if the mineral leased is found any time to contain any valuable mineral separation of which is not, in the opinion of the Collector, easily possible or within the means of the lessee.

#### PART-V

##### RENTS AND ROYALTIES RESERVED BY THIS LEASE

1. ***To pay dead rent or royalty whichever is higher.***—The lessee shall pay for every year except the first year of the lease, dead rent specified in clause 2 of this Part. Provided that the lessee shall be liable to pay the dead rent or royalty in respect of each mineral whichever is higher in amount but not both.
2. ***Rate and mode of payment of dead rent.***— Subject to the provisions of clause 1 of this Part, as from the day <sup>1</sup>[XXXX].....20.....during the subsistence of the lease, the lessee/lessees shall pay to the Collector(in four equal quarterly installments on the .....day of the months of .....or in four equal half yearly installments on the .....day of and the day of.....(in each year) certain annual dead rent at the following rate per acre of land s, described in Part I of this Schedule subject to revision at any time by state Government by notification of schedule-II of this Rule(here insert the amount payable).

3. **Rate and mode of payment of royalty/Settlement Amount.**—Subject to the provision of clause 1 of this part, the lessee/lessees shall during the subsistence of this lease pay to the State Government at such times and in such manner as the State Government may prescribe, installment of settlement amount/royalty in respect of any mineral/minerals removed by him/them from the leased area at the rate for the time being specified in the Schedule IIIA of the said Rules.
4. **Payment of surface rent, and water rate.**—The lessee/lessees shall pay rent and water rate to the State Government in respect of all parts of the surface of the said lands which shall from time to time be occupied or used by the lessee/lessees under the authority of these presents at the rate of Rs..... and Rs. .... respectively per annum per acre of the area so occupied or used and so in proportion for any area less than a acre during the period from the commencement of such occupation or used until the area shall cease to be so occupied or used and shall as far as possible restore the surface land so used to its original condition. Surface rent and water rate shall be paid as herein before detailed in clause 2:

PROVIDED THAT NO such rent/water rate shall be payable in respect of the occupation and use of the area comprised in any roads or ways to which the public have full right of access.

#### PART-VI

#### PROVISIONS RELATING TO THE RENTS AND ROYALTIES

1. **Rent and royalties to be from deduction etc.**—The rent, water rate and royalties mentioned in Part V of this Schedule shall be paid free from any deductions to the State Government at ..... and such manner as the State Government may prescribe.
2. **Mode of computation of royalty.**—For the purposes of computing the said royalties the lessee/lessees shall keep a correct account of the mineral/minerals produced and dispatched. An Account as well as the weight of the mineral/minerals in stock or the process of export may be checked by an officer authorised by the State Government.
3. **Monthly account to be sent to State Government.**— The accounts for each month in respect of raising, sale, dispatch, local consumption, royalty, and rent dues and paid shall be [submitted] within 15 days of the month following and a true copy signed by the lessees or his/her/its authorised agent shall be sent in triplicate to the Competent Officer thereafter in a form that may be prescribed from time to time by the State Government .
4. **Interest on arrear payments.**—The lessee/lessees shall be liable to pay interest at the rate of [24] percent per annum on any amount remaining payable to the State Government
5. **Course of action if rents and royalties are not paid in time.**—Should any rent, royalty or other sums due to the State Government under the terms and conditions of these presents be not paid by the lessee/lessees within the prescribed time the same, together with simple interest due thereon at the rate of twenty four percent per annum may be recovered on a certificate of such officer as may be specified by the State Government by general or special order, in the same manner as an arrear of land revenue.



**PART-VII**  
**THE COVENANTS OF THE LESSEE/LESSEES**

1. ***Lessee to pay rents and royalties taxes, etc.***—The lessee/lessees shall pay the rent, water rate and royalties reserved by this lease at such times and in the manner provided in PARTS V and VI of these presents and shall also pay and discharge all taxes, rates, assessments and impositions whatsoever being in the nature of public demands which shall, from time to time, be charged, assessed or imposed by the authority of the Central and State Governments upon or in respect of the premises and works of the lessee/lessees in common with other premises and works of a like nature except demands for land revenues.
2. ***To maintain and keep boundary marks in good order.***—The lessee/lessees shall at his/their own expense, erect and at all times maintain and keep in repair, boundary marks and pillars according to the demarcation to be shown in the plan annexed to this lease. Such marks and pillars shall be sufficiently clear of the shrubs and other obstructions as to allow easy identification.
3. ***To commence operations within three months and work in a workmanlike manner.***—The lessee/lessees shall commence operation within three months from the date of execution of the lease and shall thereafter at all times during the continuance of his lease search for, win, work and develop the said minerals without voluntary intermission in a skillful and workman-like manner and as prescribed under clause 12 hereinafter without doing or permitting to be done any unnecessary or avoidable damage to the surface of the said lands or the crops, buildings, structures or other property thereon. For the purposes of this clause, operations shall include the erection of machinery, laying of a tramway or construction of a road in connection with the mine.
4. ***To indemnify Government against all claims.***—The lessee/lessees shall make and pay such reasonable satisfaction and compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury or disturbance which may be done by him/them in exercise of the powers granted by this lease and shall indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith.
5. ***To secure and keep in good condition pits, shafts, etc.***—The lessee/lessees shall, during the subsistence of this lease, well and sufficiently secure and keep open with timber or other durable means all pits, shafts and workings that maybe made or used in the said lands and make and maintain sufficient fences to the satisfaction of the concerned authority of the Central or State Government round every such pit, shaft or working whether the same is abandoned or not and shall during the same period keep all workings in the said lands, except such as may be abandoned, accessible, free from water and foul air as far as possible.
6. ***To strengthen and support the mine to necessary extent.***— The lessee/lessees shall strengthen and support to the satisfaction of the Railway Administration concerned or the State Government, as the case may be, any part of the mine which in its opinion requires such strengthening or support for the safety of any railway, reservoir, canal, road and any other public works or structures.
7. ***To allow inspection of workings.***—The lessee /lessees shall allow any officer authorised by the Central Government or the State Government in that behalf to enter upon the premises including any building, excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting, examining, surveying, prospecting and making plans thereof, sampling and collecting any data and the lessee/lessees shall with proper person employed by the lessee/lessees and

acquainted with the mines and works effectually assist such officer, agents, servants and workmen in conducting every such inspection and shall afford them all facilities, information connected with the working of the mines which they may reasonably require and also shall and will conform to and observe all orders and regulations which the Central and State Governments as the result of such inspection or otherwise may, from time to time, see fit to impose.

8. ***To report accident.***—The lessee/lessees shall without delay, send to the Collector/ competent officer, as the case may be, a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this lease.
9. ***To report discovery of other minerals.***—The lessee/lessees shall report to the Collector/competent officer, as the case may be, the discovery in the leased area of any mineral not specified in the lease within sixty days of such discovery along with full particulars of the nature and position of each such find. If any mineral not specified in the lease is discovered in the leased area, the lessee/lessees shall not win and dispose of such mineral unless such mineral is included in the lease or a separate lease is obtained thereof.
10. ***To keep records and accounts regarding production and employees etc.***— The lessee/lessees shall at all time during the said term, keep or cause to be kept at an office to be situated upon or near the said lands, correct and intelligible books of accounts which shall contain accurate entries showing from time to time.—
  - (1) Quantity and quality of the said mineral/minerals realised from the said lands.
  - (2) Quantity of the various qualities of ores beneficiated or converted.
  - (3) Quantities of the various qualities of the said mineral/minerals sold and exported separately.
  - (4) Quantities of the various qualities of the said mineral/minerals otherwise disposed of and the manner and purpose of such disposal.
  - (5) The prices and all other particulars of all sales of said mineral/minerals.
  - (6) The number of persons employed in the mines or works upon the said lands  
specifying nationality, qualifications and pay of the technical personnel.
  - (7) Such other facts, particulars and circumstances as the State Governments may from time to time require and shall also furnish free of charge to such officers and at such times as the State Governments may appoint, true and correct abstract of all or any such books of accounts and such information and returns to all or any of the matters aforesaid as the State Government may prescribe and shall at all reasonable times allow such officers as the State Government shall in that behalf appoint to enter into and have free access to the said officers for the purpose of examining and inspecting the said books of accounts, plans and records and to make copies thereof and make extracts therefrom.
11. ***To maintain plans, etc.***—The lessee/lessees shall at all times during the said term, maintain at the mine office correct, intelligible, up-to-date and complete plans and sections of the mines in the said lands. They shall show all the operations and workings and all the trenches, pits and drillings made by him/them in the course of operations carried on by him/them under the lease, faults and other disturbances encountered and geological data and all such plans and sections shall be amended and filled up by and from actual surveys to

be made for that purpose at the end of twelve months or any period specified from time to time and the lessee/lessees shall furnish free of charge to the State Government, true and correct copies of such plans and sections whenever required. Accurate records of all trenches, pits and drillings shall show: -

- (a) The subsoil and strata through which they pass.
- (b) Any mineral encountered.
- (c) Any other matter of interest and all data required by the State Government, from time to time.

The lessee/lessees shall allow any officer of the State Government to inspect the same at all reasonable times. He/they shall also supply when asked for by the State Government, Director General, Geological Survey of India, the Controller General, Indian Bureau of Mines, a composite plan of the area showing thickness, dip, inclination, etc. of all the seams as also the quantity of reserves quality-wise.

- 11A. The lessee shall pay a wage not less than the minimum wage prescribed by the Central or State Government from time to time.
- 11B. The lessee shall comply with provisions of the Mines Act, 1952, as and when applicable and the rules made thereunder.
- 11C. The lessee shall take measures for the protection of environment like planting of trees, reclamation of land, use of pollution control devices; and such other measures as may be prescribed by the Central or State Government, from time to time, at his own expense.
- 11D. The lessee shall pay compensation to the occupier of the land on the date and in the manner as prescribed by the State Government.
- 11E. The lessee shall, in the matter of employment, give preference to the tribal and to the persons who become displaced because of the taking up of mining operations.
- 12. **Act 67 of 1957.**— The lessee/lessees shall be bound by such rules as may be issued from time to time by the Government of India under section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act 67 of 1957) and shall not carry on mining or other operations under the said lease in any way other than as prescribed under these rules.
- 13. **To provide weighing machine.**—Unless specifically exempted by the State Government, the lessee/lessees shall provide and at all times keep at or near the pit head or each of the pit heads at which the said minerals shall be brought to bank, a properly constructed and efficient weighing machine and shall weigh or cause to be weighed thereon all the said minerals, from time to time, brought to bank, sold, exported and converted and also the converted products and shall at the close of each day cause the total weights, ascertained by such means of the said minerals, ores products raised, sold, exported and converted during the previous twenty- four hours to be entered in the aforesaid books of accounts. The lessee/lessees shall permit the State Government at all times during the said term to employ any person or persons to be present at the weighing of the said minerals as aforesaid and to keep accounts thereof and to check the accounts kept by the lessee/lessees.
- 14. **To allow test of weighing machine.**—The lessee/lessees shall allow any person or persons appointed in that behalf by the State Government at any time or times during the said term, to examine and test every weighing machine to be provided and kept as aforesaid and the weights used therewith in order to ascertain whether the same respectively are correct and in good repair and order and if upon any such examination or testing any such weighing machine or weights shall be found incorrect or out of repair or order, the State Government may require that the same be adjusted, repaired and put in order

by and at the expense of the lessee/lessees and if such requisition be not complied with within fourteen days after the same shall have been made, the State Government may cause such weighing machine or weights to be adjusted, repaired, and put in order and the expense of so doing shall be paid by the lessee/lessees to the State Government on demand and if upon any such examination or testing as aforesaid any error shall be discovered in any weighing machine or weights to the prejudice of the State Government such error shall be regarded as having existed for three calendar months, previous to the discovery thereof or from the last occasion of so examining and testing the same weighing machine and weights in case such occasion be within such period of three months and the said rent and royalty shall be paid and accounted for accordingly.

15. ***To pay compensation for injury of third parties.***—The lessee/lessees shall make and pay reasonable satisfaction and compensation for all damage, injury or disturbance of person or property which may be done by or on the part of lessee/lessees in exercise of the liberties and power granted by these presents and shall at all times save harmless and keep indemnified the State Government from and against all suits, claims and demands which may be brought or made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance.
16. ***Not to obstruct working of other minerals.***—The lessee/lessees will exercise the liberties and powers hereby granted in such a manner as to offer no unnecessary or reasonably avoidable obstruction or interruption to the development and working within the said lands of any minerals not included in this lease and shall at all times afford to the State Government and to the holders of mining leases in respect of any such minerals or any minerals within any land adjacent to the said lands, as the case may be, reasonable means of access and safe and convenient passage upon and across the said lands to such minerals for the purpose of getting, working, developing and carrying away the same provided that the lessee/lessees shall receive reasonable compensation for any damage or injury which he/they may sustain by reason or in consequence of the use of such passage by such lessees.
17. ***Transfer of lease.***—
  - (1) The lessee/lessees shall not, without the previous approval of the Collector,;-
    - (a) assign, sublet, mortgage, or in any other manner, transfer the mining lease, or any right, title or interest therein, or;
    - (b) enter into or make any arrangement, contract or understanding whereby the lessee/lessees will or may be directly or indirectly financed to a substantial extent by, or under which the lessee's operations or undertakings will or may be substantially controlled by, any person or body of persons other than the lessee/lessees;

**PROVIDED THAT the Collector shall not give its approval unless.—**

- (a) the lessee has furnished an affidavit along with his application for transfer of the mining lease specifying therein the amount that he has already taken or proposes to take as consideration from the transferee;
- (b) the transfer of the mining lease is to be made to a person or body directly undertaking mining operations.
- (2) The lessee/lessees shall make available to the transferee the original or certified copies of all plans of abandoned workings in the area and in a belt 65 metres wide surrounding it.
- (3) The Collector may by order in writing, determine the lease at

any time if the lessee/lessees has/have committed a breach of any of the above provisions.

PROVIDED that no such order shall be made without giving the lessee/lessees a reasonable opportunity of stating his/their case.

18. ***Not to be financed or controlled by a Trust, Corporation, Firm or person.***—The lease shall not be controlled and the lessee/lessees shall not allow themselves to be controlled by any Trust, Syndicate, Corporation, Firm or person except with the written consent of the State Government. The lessee/lessees shall not enter into or make any arrangement, compact or understanding, whereby the lessee/lessees will or may be directly or indirectly financed by or under which the lessee's/lessees' operations or undertakings will or may be carried on directly or indirectly by or for the benefit of or subject to the control of any Trust, Syndicate, Corporation, Firm or person unless with the written sanction given prior to such arrangement, compact or understanding, being entered into or made, of the State Government and any or every such arrangement, compact or understanding, as aforesaid (entered into or made with such sanction as aforesaid) shall only be entered into or made and shall always be subject to an express condition binding upon the other party or parties thereto that it shall be terminable if so required in writing by the State Government and shall in the event of any such requisition being made be forthwith thereafter determined by the lessee/lessees accordingly.
19. ***Lessee shall deposit any additional amount necessary.***—Whenever the security deposit Rs. .... or any part thereof or any further sum hereafter deposited with the Collector in replenishment thereof shall be forfeited or applied by the State Government pursuant to the power hereinafter declared in that behalf the lessee/lessees shall deposit with the Collector such further sum as may be sufficient with the unappropriated part thereof to bring the amount in deposit with the State Government up to the sum equal to the full security deposit amount.
20. ***Delivery of workings in good order to State Governments after determination of lease.***—The lessee/lessees shall at the expiration or sooner determination of the said term deliver up to the State Government all mines, pits, shafts, inclines, drifts, levels, water ways, airways and other works now existing or hereafter to be sunk or made on or under the said lands except such as have been abandoned with the sanction of the State Government and in any ordinary and fair course of working all engines, machinery, plant, buildings, structures, other works and conveniences which at the commencement of the said term were upon or under the said lands and all such machinery set up by the lessee/lessees below ground which cannot be removed without causing injury to the mines or works under the said lands (except such of the same as may with the sanction of the State Government have become disused) and all buildings and structures of bricks or stone erected by the lessee/lessees above ground level in good repair order and condition and fit in all respects for further working of the said mines and the said minerals.

- 21 (a) ***Right of preemption.***—The State Government shall from time to time and all times during the said term have the right (to be exercised by notice in writing to the lessee/lessees) of pre-emption of the said minerals (and all products thereof) lying in or upon the said lands hereby demised or elsewhere under the control of the lessee/lessees and the lessee/lessees shall with all possible expedition deliver all minerals or products or minerals purchased by the State Government under the power conferred by this provision in the quantities at the times in manner and at the place specified in the notice exercising the said right.
- (b) Should the right of pre-emption conferred by this present provision be exercised and a vessel chartered to carry the minerals or products thereof procured on behalf of the State Government or the Central Government be detained on demurrage at the port of loading, the lessee/lessees shall pay the amount due for demurrage according to the terms of the charter party of such vessel unless the State Government shall be satisfied that the delay, is due to causes beyond the control of the lessee/lessees.
- (c) The price to be paid for all minerals or products of minerals taken in pre-emption by the State Government in exercise of the right hereby conferred shall be the fair market price prevailing at the time of pre-emption provided that in order to assist in arriving at the said fair market price the lessee/lessees shall if so required furnish to the State Government for the confidential information of the Government, particularly of the quantities, descriptions and prices of the said minerals or products thereof sold to other customers and of charters entered into for freight, for carriage of the same and shall produce to such officer or officers as may be directed by the State Government original or authenticated copies of contracts and charter parties entered into for the sale or freightage of such minerals or products.
- (d) In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence and President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof), the State Government with the consent of the Central Government shall from time to time and all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the lessee/lessees forthwith take possession and control of the works plant machinery and premises of the lessee/lessees on or in connection with the said lands or operations under this lease and during such possession or control the lessee/lessees shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Government or State Government regarding the use or employment of such works, plants, premises and minerals provided that fair compensation which shall be determined in default of agreement by the State Government shall be paid to the lessee/lessees for all loss or damage sustained by him/them by reason or in consequence of the exercise of the powers conferred by this clause and PROVIDED ALSO that the exercise of such powers shall not determine the said term hereby granted or affect the terms and provisions of these presents further than may be necessary to give effect to the provisions of this clause.
22. ***Employment of foreign national.***—The lessee/lessees shall not employ, in connection with the mining operations any person who is not an Indian national except with the previous approval of the State Government.
23. ***Recovery of expenses incurred by the State Government.***— If any of the works or matters which in accordance with the covenants in that behalf hereinbefore contained are to be carried or performed by the lessee/lessees be not so carried out or performed within the time specified in that behalf, the State Government may cause the same to be carried out or performed and the

lessee/lessees shall pay the State Government on demand all expenses which shall be incurred in such carrying out or performance of the same and the decision of the State Government as to such expenses shall be final.

24. **Furnishing of geophysical data.**—The lessee/lessees shall furnish.—
  - (a) all geophysical data relating to mining fields, or engineering and ground water surveys, such as anomaly maps, sections, plans, structures, contour maps, logging, collected by him/them during the course of mining operations to the State Government and Director-General, Geological Survey of India.
  - (b) all information pertaining to investigations of radioactive minerals collected by him/them during course of mining operations to the Secretary, Department of Atomic Energy, New Delhi and to the State Government.

Data or information referred to above shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the mining lease.
25. **Storage and use of explosive .**—The storage and use of any explosive shall only be in accordance with the provision of Indian Explosive Act, the Metalliferous Mines Regulation for the time being in force and lawful directions of the Inspector of Mines. The lessee shall be responsible for and ensure that no explosive intended for the mine is pilfered or misused or used for purposes, within or outside the lease area, other than mining within the lease area.
26. **Boundary dispute .**—If any boundary dispute or disputes regarding the right or way or any other dispute, whatsoever regarding the construction of any term or condition in the lease arises between the lessee and the lessee of any adjoining block already leased under similar terms or which may subsequently be leased, the lessee shall be bound to submit such dispute to the decision of the Collector or to an officer appointed by State Government for the purpose. An appeal shall lie to the Commissioner of the Division from the decision of the said officer and the order of the Commissioner of the Division thereon shall be final and binding on the lessee.
27. **To abide by rules and regulations.**—The lessee shall abide by all existing laws and rules and regulations as may be enforced by the Government of India or the State Government and all such other laws, rules and regulations as may be enforced from time to time in respect of working of mines and minerals and other matter affecting the safety, health and convince of the employees of the lessee or of the public. On receipt of a notice from the State Government or from an officer authorised by the State Government in this behalf regarding any unlawful or irregular work in connection with the working of the mine the lessee shall also be bound to pay compensation to the State Government for all losses due to any illegal or unlawful work done by the lessee or this employees.
28. The lease shall be liable to cancellation if the lessee ceases to work the mine or the quarry, for a continuous period of one year without obtaining the previous permission of the competent office or collector.

Provided that the lease shall not be cancelled if the lessee is prevented from working the mine or quarry owing to circumstances beyond his control.
29. If the lessee does not work in any part of the area leased out to him continuously for period of six months, of which the Collector shall be the sole judge, the Collector shall have the power to determine the lease and reenter the area, provided that the lessee shall be given a reasonable opportunity to show cause against the same.
30. If the lessee does not work on more than 10% of the area leased out to him continuously for more than 6 months of which the Collector shall be the sole

- judge, the Collector shall have the power to re-enter on 75% of the area comprised in the lease, provided that the lessee shall be given a reasonable opportunity to show cause against the same and the area left with the lessee shall be a compact block including the portion of the area worked by him and the terms of the original lease shall be considered as modified from the date of re-entry by the Collector after his final order.
31. It will be the responsibility of the lessee to ensure that the individual/public/community properties, cultivable land/structures like Road/Temple/ Mosque/ Gurudwara/ Church or any other property is not damaged during the course of mining. Otherwise the lessee will have to pay the compensation to the concerned and his settlement can also be cancelled on these basis and all the deposited amount can be forfeited.
  32. The Collector may cancel the leased area if the said area is notified as archaeological site or reserve/protected forest area in future.
  33. All mining operations shall be in accordance with the terms and conditions laid under the Environmental Clearance submitted by the lessee.
  34. Any mining operation under settlement shall be undertaken by the lessee in accordance with the terms & conditions of approved mining plan prepared for the entire settlement period.
  35. Lessee shall have to pay to the District Mineral Foundation at prescribed rates every calendar year during the entire lease period.
  36. Lessee shall have to pay 2.06% of every calendar year settlement amount as Income Tax and surcharge.
  37. The lessee shall have no claim against the State Government for compensation or damages due to non-availability of minerals or boundary disputes or any hindrance caused in transportation.
  38. The lessee shall allow other lessee to transport the mineral through his auction area.
  39. Lessee shall have to display a signboard at mining sight exhibiting name and address of the Lessee, Settlement period, name and address of local manager.
  40. Lessee shall have to arrange shed/shelter, drinking water, 'Palna Ghar', First Aid kit etc. at mine site under the provisions of labour act/ rules.
  41. Lessee shall abide by any other conditions imposed by the Collector as he deems necessary in regard to public interest. The Collector may determine the settlement by passing reasoned order if the lessee commits any breach of terms and conditions mentioned above after the applicant is given reasonable opportunity of being heard.
  42. If the lessee makes default in payments of any Installments, GST, Income Tax, Stamp Duty and Registration fees on time, the Collector shall give a thirty days notice to the lessee requiring him to pay within prescribed time limit and if not paid within such period the Collector may without prejudice to any proceeding that may be taken against lessee, determine the settlement and forfeit the whole or part of the security deposit.
  43. The lessee shall have to take permission from DGMS under Rule 106 (2) (b) of Metalliferrous Mines Regulation 1961 for any deep hole blasting and before deploying any HEMM in mining area.
  44. The lessee shall have to dispatch mineral loaded vehicles by main roads only and not by the PMGSY roads.
  45. Lessee shall submit a mine closure plan within prescribed time period in the rule.
  46. The lessee shall have to submit a yearly report before 31<sup>st</sup> December of every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan.



47. The lessee shall maintain the boundary pillars on his own cost in the whole lease period according to provisions prescribed in the rule.
48. The lessee shall use and store any explosive only after getting permission from District Magistrate. The lessee shall use any explosive in accordance with provisions of Indian explosives act and rules. Explosives shall be supplied by the firms recommended by the Collector.
49. The lessee shall have no claim on any type of property lying within settled area before the execution of the lease deed.
50. The period of the lease will be valid for five years from the date of execution of the lease deed. No claim for delay in handing over the area shall be accepted in future.
51. The lease deed shall be registered by depositing required fees. The lease may be cancelled in case of non registration of lease deed.

**PART-VIII**

**THE COVENANTS OF THE STATE GOVERNMENT**

1. ***Lessee/lessees may hold and enjoy rights quietly.***— The lessee/lessees paying the rents, water rate and royalties hereby reserved and observing and performing all the covenants and agreements herein contained and on the part of the lessee/lessees to be observed and performed shall and may quietly hold and enjoy the rights and premises hereby demised for and during the term hereby granted without any unlawful interruption from or by the State Government, or any person rightfully claiming under it.
2. ***Acquisition of land of third parties and compensation thereof.***— If in accordance with the provision of clause 4 of Part VII of this Schedule the lessee/lessees shall offer to pay to an occupier of the surface of any part of the said lands compensation for any damage or injury which may arise from the proposed operations of the lessee/lessees and the said occupier shall refuse his consent to the exercise of the right and powers reserved to the State Government and demised to the lessee/lessees by these presents and the lessee/lessees shall report the matter to the State Government and shall deposit with it the amount offered as compensation and if the State Government is satisfied that the amount of compensation offered is fair and reasonable or if it is not so satisfied and the lessee/lessees shall have deposited with it such further amount as the State Government shall consider fair and reasonable, the State Government shall order the occupier to allow the lessee/lessees to enter the land and to carry out such operations as may be necessary for the purpose of this lease. In assessing the amount of such compensation, the State Government shall be guided by the principles of the Land Acquisition Act.
- 3 (1) ***Liberty to surrender the lease.***—The lessee/lessees may at any time surrender this lease by giving not less than Six months notice in writing to the Collector, and upon the expiration of such notice provided that the lessee/lessees shall upon such expiration render and pay all rents, water rates, royalties, compensation for damages and other moneys which may then be due and payable under these presents to the lessor or any other person or persons and shall deliver these presents to the State Government then this lease and the said term and the liberties, powers and privileges hereby granted shall absolutely cease and determine but without prejudice to any right or remedy of the lessor in respect of any breach of any of the covenants or agreements contained in these presents.

4. Collector may on an application made by the lessee, permit him to surrender one or more minerals from his lease which is for a group of minerals on the ground that deposits of that mineral have since exhausted or depleted to such an extent that it is no longer possible to work the mineral economically, subject to the condition that the lessee-
  - (a) Makes an application for such surrender of mineral at least Six months before the intended date of surrender; and
  - (b) Gives an undertaking that he will not cause any hindrance in the working of the mineral surrendered by any other person who is subsequently granted a mining lease for that mineral.
5. **Refund of security deposits.**— On such date as the State Government may elect within 12 calendar months after the determination of this lease the amount of the security deposit paid in respect of this lease and then remaining in deposit with the State Government and not required to be applied to any of the purposes mentioned in this lease shall be refunded to the lessee/lessees. No interest shall run on the security deposit.

#### PART IX GENERAL PROVISIONS

1. **Breach of any condition.**—In case of breach of any of the condition of the lease other than mentioned in clauses 2 and 3 of this part the Collector may require the lessee or his transferees or assignees to pay penalty not exceeding an amount of annual deed rent specified under clause 2, part V
2. **Obstruction to inspection.**—In case the lessee or his transferees or assignees obstructs/obstruct or does/do not allow entry or inspection any of the conditions of the lease mentioned in clause 1 part III and clauses 13, 14 and 2 of part VII, the Collector may cancel the lease and forfeit the whole or part of the security deposit.
3. **Breach of any other condition.**— In case of lessee or his transferee or assignee commit any breach of any of the conditions specified in (clause 3 of part III) and clauses 2, 3, 6, 10, 23 of part VII then and in any such case the Collector shall give notice in writing to the lessee or his transferees or assignees as the case may be asking him/them to remedy the breach within 30 days from the date of the notice and if the breach is not remedied within such period the Collector may determine the lease; provided that nothing therein contained shall debar the Collector from enforcing any other right or remedy that the Collector may have against the lessee or his transferees or assignees under any other provisions herein contained.
4. In case of breaches of the covenants and agreements by the lessee on which the aforesaid notice has been given, the Collector in lieu of giving notice may impose such penalty not exceeding four times the amount of annual deed rent specified in clause 2 of part V.
5. **Failure to fulfill the terms of lease due to “force majeure” .**—Failure on the part of the lessee to fulfill any of the terms and conditions of this lease shall not give the Collector any claim against the lessee or be deemed a breach of this lease, in so far as such failure is considered by the said Collector to arise from force majeure, and if through force majeure the fulfillment by the lessee of any of the terms and condition of this lease be delayed the period such delay shall be added to the period fixed by this lease. In this clause the expression “force majeure” means act of god, war, insurrection, riot, civil commotion, a strike, earthquake, tide, storm, tidal wave flood, lightening, explosion, fire, earthquake and other happenings which the lessee could not reasonable prevent or control.

6. **Lessee to remove his properties on the expiry of lease.**—The lessee having first paid and discharged the rents and royalties payable by virtue of these presents may at the expiration or sooner determination of the said term or within six calendar months thereafter take down and remove for his own benefit all or any machinery, plant, building, and other works, erections and conveniences which may have been erected, set up or placed by the lessee in or upon the said lands and which the lessee is/are not bound to deliver to the Collector under clause 18 part VII of this schedule and which the Collector shall not desire to purchase.
7. **Forfeiture of property left more than six months after determination of lease.**—If at the end of three calendar months after the expiration or sooner determination of the said term or after the expiration or sooner determination of the said term or after the date from which any, surrender by the lessee of the said lands under the provision contained in clause 4 of part VIII of this schedule become effective there shall remain in or upon the said land, any machinery, plant, buildings, structures and other work, erections and conveniences or other property, the same may be sold or disposed of in such manner as the Collector shall deem fit without liability to pay any compensation or account to the lessee in respect thereof.
8. **Recovery under the public demand act.**—Without prejudice to any other mode of recovery authorised by any provision of this lease or by any law all amount falling due hereunder against the lessee may be recovered as a public demand under the Bihar & Orissa Public Demands Recovery Act or any Statutory Act or Rules Thereof for the time being in force.
9. **Anticipated royalty for the purpose of stamp duty.**—For the purpose of stamp duty, the anticipated royalty is Rs .....
10. **Responsibility of managing agents.**—The managing agent of the lessee shall be equally responsible as the lessee.
11. **service of notice.**—Every notice by these presents required to be given to the lessee shall be given in writing to such person resident on the said lands as the lessee may appoint for the purpose of receiving such notices and if these shall be sent the lessee by registered post addressed to the lessee at the address recorded in this lease or at such other address in India as the lessee may from time to time in writing to the Collector or the competent officer authorised by the Collector in this behalf designate for the receipt of notices and every such service shall be deemed to the proper and valid service upon the lessee and shall not be questioned or challenged by him, In witness where of these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day, month and year first above written.
12. For the purpose of stamp duty the anticipated royalty from the demised land is Rs.....per year.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written.

Signed by.....

For and on behalf of the Governor of Bihar in the presence of:

1.

2.

Signed by.....

for and behalf of..... in presence of:

1.

2.

**Form C**

[See Rules 34(1)]

Form of application for Quarrying Permit

No.-.....

Date .....

To,

The Competent Officer,

.....

Sir,

I/We request that a quarrying permit under the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019 be granted to me/us.

A sum of Rs. 5000/- being the fee in respect of application is deposited (copy of challan is enclosed)

The following particulars are enclosed:-

- (i) Clearance certificate for payment of mining dues to be attached
- (ii) Written consent of the Raiyatas from which mineral is to be extracted if the land from which minor mineral is to be extracted are raiyati lands.
- (iii) Mineral which the applicant intends to quarry.
- (iv) The details of the land from which mineral will be quarried.

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details as may be required by you. I/We do hereby declare that I/We shall adhere to the terms and conditions as indicated in these rules and any other conditions imposed by competent authority.

Yours Faithfully,

Signature and Designation  
of the applicant

Place-  
Date-

**FORM D**

[See Rules 33(1)]

Form of Permit For Minor Minerals To be Issued Under The Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019.

Permit No.-\_\_\_\_\_ of 20\_\_\_\_\_

Name and address of the permit holder:-

Name of locality village, plot, number etc.	Date of expiry of permit	Name and description of minor minerals	Purpose for which it will be used	Number of quantity of materials	Rate of royalty	Total amount paid
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>

Seal

Competent Officer

The permit is issued subject to the terms and conditions noted below:-

**CONDITIONS.**

- (1) Materials shall have to be removed within the prescribed time- limit.
- (2) Quarrying is not allowed beyond a depth of 3m from the surface.
- (3) Compensation, if any, shall have to be paid for damage to the land covered by permit.
- (4) Felling of trees is not allowed without prior permission of competent authorities within whose jurisdiction the area lies.
- (5) Surface operation shall not be done on any public prohibited and restricted place.
- (6) Every type of accident shall be reported to the Competent Officer immediately.
- (7) The party shall be liable to indemnify the claims of third parties. State Government shall not be responsible for such claims in any way.
- (8) The materials left after the cancellation of the permit shall be forfeited to Government and the same shall be deemed to be Government property.
- (9) No excess quantity of materials beyond this permit this permit shall be removed without obtaining prior permit, otherwise the permit-holder shall be liable for action Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019.
- (10) Proper accounts for the extraction and removal shall be maintained in the prescribed form and a monthly return shall be submitted within the month following the month to which extraction relates.
- (11) e-chalans in the prescribed form shall have to be issued for the materials to be dispatched or sold from the area.

**N.B.- Breach of any of the conditions noted above is liable for the cancellation of permit, forfeiture of materials extracted and such other action as may be deemed necessary.**

**Form- E**

{See Rule 37(1), (2) &amp; (3)}

Application for the grant of Mineral Disposal Permit for disposal of mineral extracted during the process of maintenance / drainage of drain / canal / river or generated during the process of construction or repair or demolition of building / structure / or accumulated due to floods / dispersed through production activity.

To

The District Mining Officer,  
Mines and Geology Department,

.....

Dear Sir,

Undersigned has to remove and transport minor minerals during the process of maintenance / drainage of drain / canal / river or generated during the process of construction or repair or demolition of building / structure / or accumulated due to floods / dispersed through production activity at ..... (Location of site). The approved copy of the site plan is attached. In the process of digging / repair/ demolish mineral(s) namely..... shall also be excavated incidental to the above developmental activity .The same requires to be consumed at the site or disposed off, for which permission is solicited.

2. The details of the area for which permission is being sought, is given as under:-

- (a) Location of the area
- (b) Purpose
- (c) Total area/ built up area
- (d) Extent of the area required for digging giving length, breadth & depth
- (e) Quantity and particulars of the mineral(s) to be removed
- (f) Advance royalty payable

3. The applicant further state that:-

- (i) the royalty at the rates prescribed under the rules shall be paid in advance on the mineral(s) excavated incidental to digging of foundation/ basement / demolish of structure / maintenance of drain /canal / river / accumulated due to floods.
- (ii) the intention of digging is not to excavate mineral(s) from the said site for commercial mining but for lying of foundation or basement / demolish of structure or developmental activity duly approved by the competent authority.
- (iii) The incidental mineral(s) excavated will be disposed of only on issuance of a valid E-challan / Transit Pass as supplied by the Competent Officer / District Mining Officer.

Dated :

Enclose: As above.

(Name and address of the applicant)

- (i) Proof of ownership of land.
- (ii) Site plan along with a copy of permission/ sanction of competent authority to undertake development activities or construction / demolition of building etc.

**FORM-F**

[See Rule 37(1), (2)&(3) ]

**FORM FOR GRANT OF MINERAL DISPOSAL PERMIT**

Mineral Disposal permit no.....Place .....  
Date.....

Whereas, Shri ..... (Name and Designation) applied for grant of Mineral Disposal permit for disposal of ..... cubic meters / tones / cubic feet of ..... (Name of Minor Minerals) from Khesra No.....of Village ..... Circle ..... District ..... under Rule 37 of the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019 and has paid an application fee of Rs. .... and advance royalty amounting to Rs.. ..

2. Permission is hereby granted to quarry, collect, remove and transport .....(mineral) from the area indicated on the plan annexed hereto during the process of maintenance / drainage of drain / canal / river or generated during the process of construction or repair or demolition of building / structure / or accumulated due to floods / dispersed through production activity at ..... (village) ..... (Circle)..... (District).

3. The mineral disposal permit shall be valid for..... (Period) from ..... to .....

4. The Mineral disposal permit shall be governed by the following conditions namely-

- (a) The holder of permit shall maintain complete and correct account of the mineral removed and transported from the area;
- (b) The holder of permit shall allow Deputy Director/Mining Officer/Mining Inspector or any officer authorized by the Collector to inspect the site and verify the accounts.
- (c) No sooner the permitted quantity is transported within the time period of 30 days or earlier, complete statement of the quantities deposited duly certified by the Officer of the concerned department shall be furnished to the Sanctioning Authority.
- (d) The holder of permit shall obtain all permissions/ consents from the competent authority under any Act and Rules applicable for excavation or removal of the minerals from the area.
- (e) The holder of permit shall submit by the 15<sup>th</sup> of every month, to the District Mining Officer / Collector a return in prescribed format.
- (f) Any other condition, the sanctioning authority may deem fit.

**Enclosure :-** Plan showing area granted under permit.

Signature of the Competent Authority  
With seal of office

**Form-G**

[ See Rule 41 ]

**Mineral Transit pass/ e-challan**

Deptt. Of Mines &amp; Geology

Government of Bihar

- Challan/Pass No. :
1. Year :
2. Name of the Sand ghat/quarry :
3. GPS co-ordinates of sand ghat/quarry :
4. Name of sand ghat Owner/Settlee :
5. Mobile No. of Settlee :
6. Full Address of Settlee :
7. Date of expiry of lease :
8. Date and time of issuance of this Challan :
9. Challan Valid Upto :
- 10 . Name of the customer :
11. Mobile No. of the customer :
12. Name of Mineral :
13. Weight of the mineral(in MT) :
14. Volume of the mineral (in Cft ) :
15. Amount Collected at Pit Head :
16. Vehicle No. :
17. Type of Vehicle :
18. Driver Name :
19. Driver Mobile No :
20. Destination :

**Note:- Additional entries may be made in the prescribed format in electronic system as per need.**





**FORM- I****MONTHLY RETURN**

[see rule 46 (2)]

(To be submitted before the 15th day of every month in respect of preceeding month)

1. Return for the month: \_\_\_\_\_(name of month and year)
2. Name of the lessee with address: \_\_\_\_\_
3. Details of the mining lease:
  - (a) Grant order No.& Date \_\_\_\_\_
  - (b) Date of execution of the lease \_\_\_\_\_
  - (c) Location of the mining lease \_\_\_\_\_
  - (d) Area of the mining lease \_\_\_\_\_
  - (e) Period of the mining lease \_\_\_\_\_
4. Name of the Minor Mineral: \_\_\_\_\_
5. Opening stock on the first day of the month \_\_\_\_\_
6. Quantity produced: \_\_\_\_\_
7. Quantity consumed: \_\_\_\_\_
  - b) Quantity dispatched: \_\_\_\_\_
8. Closing stock at the end of the month: \_\_\_\_\_
9. Pits mouth value \_\_\_\_\_
10. Number of days the mine worked: \_\_\_\_\_
11. The number of days of works stoppage. \_\_\_\_\_  
In the mine. Indicate reason for such stoppage. \_\_\_\_\_
12. No. of mandays worked: \_\_\_\_\_
13. Average daily employment: \_\_\_\_\_
14. Details of machinery and equipment deployed \_\_\_\_\_
15. Details of explosives consumed with Quantity \_\_\_\_\_

Remarks: \_\_\_\_\_

Date:

Place:

Signature of the lessee.

Or his Authorized Agent or Manager with Seal.

**FORM- J**

**ANNUAL RETURN**

[see rule 46 (3)]

(To be submitted by 30th April of each year in respect of the preceding financial year)

1. Annual Return for the year 1st April 20\_\_ to 31st March 20\_\_
2. Name of lessee with address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. Details of the mining lease: \_\_\_\_\_
  - a. Grant order No.& Date \_\_\_\_\_
  - b. Date of execution of the lease \_\_\_\_\_
  - c. Location of the mining lease \_\_\_\_\_
  - d. Area of the mining lease \_\_\_\_\_
  - e. Period of the mining lease \_\_\_\_\_
4. Name of the Minor Mineral: \_\_\_\_\_
5. Opening stock on the first day of the month \_\_\_\_\_
6. Quantity produced during the year: \_\_\_\_\_
7. a) Quantity consumed during the year: \_\_\_\_\_  
b) Quantity dispatched during the year: \_\_\_\_\_
8. Closing stock at the end of the year: \_\_\_\_\_
9. Average Pits mouth value (Rs): \_\_\_\_\_
10. Royalty (Rs) paid / Installment amount: \_\_\_\_\_
  - (a) for the current year: \_\_\_\_\_
  - (b) towards past arrears: \_\_\_\_\_
11. Dead Rent (Rs) paid: \_\_\_\_\_
  - (a) for the current year: \_\_\_\_\_
  - (b) towards past arrears: \_\_\_\_\_
12. Number of days the mine worked during the year: \_\_\_\_\_
13. The number of days of work stoppage during the year. Indicate reason(s) for such stoppage(s). \_\_\_\_\_
14. No. of mandays worked: \_\_\_\_\_
15. Average daily employment: \_\_\_\_\_
16. Accidents (if any): \_\_\_\_\_
17. Details of machinery & equipment deployed \_\_\_\_\_
18. Details of explosives used with quantity: \_\_\_\_\_

Remarks: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Signature of the lessee  
Or his Authorized Agent or Manager with Seal

**License in Form 'K'**

[See Rule 39 (1)]

Shri/S. Sri.....is approved to be a person to stock Minor/Major minerals at .....(name of place).....P.S..... District ..... and he will abide by the provisions of BIHAR MINERALS (Prevention of Illegal Mining, Transportation, Storage & CONCESSION) RULES, 2019

Seal and Signature of Competent officer'

**FORM- L**  
**FORM FOR APPEAL**

[See rule 67 (3)]

1. Name and address of individual (s) /firm or \_\_\_\_\_  
Company \_\_\_\_\_
2. Number & date of order against which appeal is made. (certified copy to be enclosed) \_\_\_\_\_
3. Designation of the authority that passed the order. \_\_\_\_\_
4. (i) Whether the appeal has been filed within 60(Sixty) days from the date of communication of the order in terms of sub rule 1/2 of Rule 67. \_\_\_\_\_  
(ii) If not, the reasons thereof \_\_\_\_\_
5. Name(s) of mineral or minerals for which appeal is made \_\_\_\_\_
6. Details of the area in respect of which appeal is made (A Plan of the area to be attached)  
(a) Village/Locality: \_\_\_\_\_  
(b) P.O/Thana: \_\_\_\_\_  
(c) Pin code: \_\_\_\_\_  
(d) Block/Sub-Division/District: \_\_\_\_\_
7. Grounds for appeal. a. \_\_\_\_\_  
b. \_\_\_\_\_  
c. \_\_\_\_\_
8. Name and address of the party/parties impleaded. Reasons for impleading him/them to be mentioned. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
9. Proof of fee paid (to be attached)

Yours faithfully,  
Signature of the applicant.

Place .....  
Dated .....

\_\_\_\_\_  
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1068-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>